ಶುಭ್ ಲಾಭ್

खबरें जो सोच बदल दे

शुभ लाभ

DAILY

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

दलितों पर अन्याय करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई... @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 । शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 । हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित । epaper.shubhlabhdaily.com । संपादक : गोपाल अग्रवाल । पृष्ठ : 14 ।*। मूल्य-6 रु.। वर्ष-6 । अंक-193

हज पर हर साल क्यों मर रहे हजारों श्रद्धालु!

इस्लामिक फर्ज में माफिया और मानव तस्करों की घुसपैठ

सऊदी अरब का मक्का शहर दुनियाभर के मुसलमानों के लिए पवित्रतम स्थान है। हर साल 18 से 20 लाख मुस्लिम श्रद्धालु हज के लिए मक्का जाते हैं। हज परमिट देने के लिए सऊदी सरकार भारी-भरकम शुल्क लेती है, इसलिए इस इस्लामिक फर्ज में अपराधियों, मानव तस्करों और अंडरवर्ल्ड की दखलंदाजी बढ़ती ही जा रही है। ये बिना परमिट कम पैसे में हज यात्रा करवाते हैं। अवैध तरीके से हज करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवस्था के चरमराने से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है।

परमिट शुल्क बचाने के चक्कर में त्रासद मौत का शिकार हो रहे श्रद्धालु

इस वर्ष हज के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि इस संगठित अपराध में कई मुस्लिम देशों के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और निजी टूर ऑपरेटर शामिल हैं। इस साल हज में भारी संख्या में हज यात्रियों की मौत के बाद अरब देशों के अखबार खंगाले गए, तब तस्वीर यह उभर कर सामने आई कि इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने वाले इस्लामिक देश, इस्लामिक मीडिया और इस्लामिक संगठन और बुद्धिजीवी इस मसले पर खामोश रहे।

शुभ-लाभ सरोकार

दुनियाभर में मुस्लिम उत्पीड़न का दावा करने वाला अल-जजीरा अखबार और चैनल भी इन मौतों पर चुप्पी साधे रहा।

सरकार और बादशाहियत के अधीन चलने वाला अधिकांश मीडिया ऐसी खबरों को दबाने की चाहे जितनी कोशिश करे, सच यह है कि 2024 की हज यात्रा हो या उससे पहले की, तमाम हज यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत प्राकृतिक से कहीं अधिक कृत्रिम ढंग से पैदा किए गए बदतर हालात के कारण हुई। वार्षिक हज अदा करने वालों को परमिट लेना पड़ता है। सऊदी सरकार ने दुनिया के सभी देशों को हज का कोटा दे रखा है। शुल्क के अधिक होने के बावजूद हर साल हज यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सुन्नी मुसलमानों के पांच इस्लामिक फर्जों (तौहीद, नमाज, रोजा, जकात व हज) में हज भी एक है, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिकांश मुस्लिम देशों के लोग भी हर हाल में हज करना चाहते हैं। ऐसे में वे कम खर्च में हज करने के लालच में मानव तस्करों के जाल में फंस जाते हैं और जान गवां बैठते हैं।

मुस्लिम देश, मुस्लिम मीडिया और मुस्लिम संगठन सब साधे हैं चुप्पी

तथ्य यह है कि वार्षिक हज यात्रा में संगठित अपराध पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। गिरोहों के लोग सऊदी अरब के चोर रास्तों और मक्का-मदीना शहर तक फैले हुए हैं। ये सरकारी परमिट से बहुत कम कीमत पर हज यात्रियों को ▶10 पर

तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐतिहासिक बनाने की तैयारी

भारत को आर्थिक शक्ति बनाने का मोदी-विमर्श

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आम बजट के संदर्भ में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्यवर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। नीट पेपर लीक घटना से गंभीर हुई केंद्र सरकार इस बार के बजट से एनटीए का प्रावधान समाप्त कर सकती है या उसमें संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। वर्ष 2017 के बजट में केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की योजना अधिक से अधिक निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करने की है। बीते सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार तीसरे कार्यकाल में सुधारों को तेज गति देगी। सरकार की रणनीति अधिक निवेश हासिल कर विकास दर बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की है। बैठक में पीएम मोदी ने आर्थिक विशेषज्ञों विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को लेकर विचार-विमर्श किया। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने की है। इसके लिए विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विशेष प्रयास की जरूरत है। बैठक में पीएम ने विकसित भारत के रोडमैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव लिए। राजनीतिक दृष्टि से सरकार की मुख्य चिंता गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग है। अर्थशास्त्रियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इनके लिए राहत की मांग कर रहे हैं। सरकार की योजना आयकर, होम लोन मामले में मध्य और निम्न मध्य वर्ग को राहत देने की है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी क्या कुछ खास होगा, इस पर पीएम मोदी की नजर है। यही वजह है कि पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों से लेकर अपने कैबिनेट मंत्रियों तक से लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीएम मोदी बजट की हर एक चीज को अपने स्तर से देखना और समझना चाहते हैं ताकि बजट आम जनता के ज्यादा अनुरूप बनें। ▶10 पर

प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक

बजट से जनता के प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करने पर चल रहा मंथन

● मोदी काल के 10 बजट

बजट 2014 (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)

पहले बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुचर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करना, सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना था। इस योजना में सामान्य जागरूकता और कल्याणकारी सेवाओं के बेहतर वितरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

बजट 2015 (सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

गोल्ड मोनेटाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अरुण जेटली ने अपने दूसरे बजट भाषण में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। इसे मेटल सोना खरीदने के विकल्प के रूप में घोषित किया गया था। अपनी शुरुआत के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एसजीबी ने निवेशकों को उच्च मात्रा में रिटर्न दिया। ▶10 पर

कश्मीर में हिंदुओं पर बर्बर हिंसा करने वाले सरगना की परिणति

एनआईए की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील

यासीन मलिक को फांसी की सजा मिले

एनआईए के अभियोजक रहे जज ने केस से खुद को अलग किया

नौ अगस्त को नई बेंच में लिस्टेड होगा केस, सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से फांसी की सजा की मांग की है। यह मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच में लिस्टेड था। इस बेंच के सदस्य अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब अगली सुनवाई 9 अगस्त को उस बेंच के समक्ष लिस्टेड होगी, जिसके सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे।

जस्टिस अमित शर्मा 2010 में एनआईए के अभियोजक थे। इस वजह से उन्होंने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग किया है। हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर 29 मई 2023 को यासीन मलिक को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक के ऊपर लगे आरोपों को सही पाया था। उन्होंने कहा था, यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे। यह कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि एनआईए के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मलिक ने कश्मीर के माहौल को बिगड़ने की कोशिश की। मेहता ने कहा था कि यासीन मलिक लगातार सशस्त्र विद्रोह कर रहा था। वह सेना के जवानों की हत्या में शामिल रहा। कश्मीर को अलग करने की बात करता रहा। क्या यह दुर्लभतम मामला नहीं है? भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले मे मौत की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे अपराधी को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। यासीन मलिक वायुसेना के चार जवानों की हत्या में शामिल था। उसके सहयोगियों ने तत्कालीन गृहमंत्री की बेटी रुबिया सईद का अपहरण किया। ▶10 पर

केंद्र सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा

आंध्र प्रदेश के लिए 60 हजार करोड़ की योजना मंजूर

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की सीएम चंद्रबाबू नायडू की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा की थी। अब लोगों की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जा टिकी हैं। ▶10 पर

विपक्ष के इकलौते विधायक सत्ताधारी दल से जुड़े

अब सिक्किम में कोई विपक्ष नहीं

गंगतोक, 11 जुलाई (एजेंसियां)। सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां कोई विपक्ष नहीं रहा। सिक्किम में विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के सिर्फ एक विधायक थे, वे भी अब सत्ताधारी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) से जुड़ गए हैं। 2 जून को सिक्किम विधानसभा के नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती थीं। एसडीएफ से तेनजिंग नोरबू लाम्था को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया, मुझे आज अपने सरकारी आवास मिंटोकगांग पर 23-सियारी विधानसभा सीट से ▶10 पर

रूस और ऑस्ट्रिया में मोदी के वक्तव्य पर विश्व में चर्चा

हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं : मोदी

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक कार्यक्रम में जो वक्तव्य दिया, उस पर दुनियाभर में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के बयान को रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिया गया और उस पर तमाम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था, हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिया, बल्कि हमने युद्ध झेला है। हम सीना तानकर दुनिया को कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। भारत ने हमेशा शांति की बात की है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज भारत के बारे में सुनकर आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में भी राष्ट्रपति पुतिन और विश्व समुदाय से कहा, भारत शांति के पक्ष में है। भारत यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में मदद के लिए तैयार है। नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। यदि लोगों की जान जाती है तो मानवता में विश्वास करने वाला हर शख्स दुखी होता है। उसमें भी यदि बेगुनाह बच्चों की हत्या हो तो यह बहुत ही पीड़ादायक है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषतौर पर यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देने के लिए आपका आभारी हूं। पुतिन ने कहा, भारत और रूस अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों के बीच अटूट रणनीतिक साझेदारी है। इन बयानों पर पूरी दुनिया में मंथन चल रहा है। विश्व के बड़े नेता रूस और यूक्रेन युद्ध के थमने के प्रति आशान्वित हो रहे हैं। रूस के दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचने पर भी मोदी ने अपना सैद्धांतिक स्टैंड रखा और युद्ध को लेकर भारत की ▶10 पर

पीएम मोदी ने कहा: हमने युद्ध दिए नहीं हैं, युद्ध झेले हैं

रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में मोदी-वक्तव्य की समीक्षा

सर्राफ़ा बाज़ार

(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 75,250/- (प्रति 10 ग्राम)

चाँदी : 95,780/- (प्रति किलोग्राम)

मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 36^0

न्यूनतम : 27^0

सीबीआई की चार्जशीट से हुआ इसरो जासूसी कांड के फर्जीवाड़े का खुलासा

हवस में नाकाम पुलिस वालों ने रचा था षडयंत्र

नम्बी नारायण समेत तीन वैज्ञानिकों का जीवन नष्ट कर डाला

मालदीव की रशीदा पर सीआई ने ढाया था प्रताड़ना का कहर

साजिश में लिप्त थे केरल पुलिस के डीजीपी और दूसरे अफसर

तिरुअनंतपुरम, 11 जुलाई (एजेंसियां)। साल 1994 के जिस इसरो जासूसी केस में देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक नम्बी नारायणन और 3 अन्य वैज्ञानिकों को फंसाकर उनका करियर खत्म कर दिया गया और देश को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के विकास में पीछे हो जाना पड़ा, वो पूरा मामला ही फर्जी था। वो मामला था एक-एक पुलिस वाले की हवस न मिटाने वाली विदेशी महिला के साथ खुन्नस निकालने का। उसने तो पहले महिला के सारे कागजात जब्त कर लिए और फर्जी केस में उसे गिरफ्तार कर लिया, फिर इस मामले में इसरो के वैज्ञानिकों को घसीट लिया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया है।

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, मालदीव की महिला मरियम रशीदा तिरुअनंतपुरम के एक होटल में रुकी थी। तब बतौर सर्किल इंसपेक्टर काम कर रहा एस विजयन उसी होटल में पहुंचा था। वो मरियम रशीदा के कमरे में घुस गया था और उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी, मरियम ने इसका विरोध किया तो विजयन ने मरियम को सबक सिखाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में विजयन ने रशीदा का संपर्क इसरो वैज्ञानिक डी शशिकुमारन से जोड़ा और फिर इस पूरे केस का तानाबाना बुना गया। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा, यह शुरू से ही कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। पीड़िता मरियम रशीदा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। पीड़िता के खिलाफ झूठी पूछताछ रिपोर्ट दी गई। उनपर गंभीर आरोप लगाए गए। सीबीआई ने जासूसी मामले में अंतरिक्ष वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को फंसाने के सिलसिले में दो पूर्व डीजीपी, ▶10 पर

कार्टून कॉर्नर

शुभ लाभ DAILY खबरें जो सोच बदल दे हिंदी दैनिक समाचार पत्र

जेबीएन रेफरल मीट वी कनेक्ट का आयोजन

समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ने वाली शक्ति का नाम है नारी : अर्चना जैन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

साधारण से असाधारण बनने की राह में अनेक रोड़े आने के बावजूद आगे बढ़ने वाली शक्ति का नाम ही नारी है। एक आम गृहिणी अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर हर चुनौती को पार कर लेती है। अपना सफर जीरों से शुरू करने वाली आज मेट्रीमोनी व्यवसाय में पिछले 2 वर्षों में नामचीन छब्बीस रिश्ते करवाने वाली जय माता दी कंपनी की संस्थापिका अर्चना जैन ने उक्त विचार यशवंतपुर में जीतो चैप्टर के अंतर्गत जीतो महिला विंग द्वारा आयोजित जीतो बिजनेस नेटवर्क जेबीएन रेफरल मीट वी कनेक्ट में कही।

उन्होंने जीतो द्वारा आयोजित विविध विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी योगा, स्पोर्ट्स, कभी बैंकिंग का और छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए समय-समय पर प्रेरित करती है। जेबीएन का यही उद्देश्य है कि मिलो और आगे बढ़ो, आप जितना मिलोगे, जितना नेटवर्क बढ़ाओगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सुदृढ़ बनना जरूरी है।

अपने बिजनेस हेतु कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कीजिए, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा रहने का आत्मविश्वास दीजिए। फिर जीवन साथी ढूँढिये। एक नारी के आगे बढ़ने से वह घर आगे बढ़ता है घर से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण। लैब ग्रोन डायमंड की सुमन रांका ने लैब में विकसित हीरे की जानकारी देते हुए कहा कि हीरा एक अनमोन रत्न है।

यही वजह है कि किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज की तुलना हीरे से की जाती है। सगाई की अंगूठियों से लेकर बढ़िया गहनों तक, हीरे रोजमर्रा के जीवन में इतने आम हैं कि अक्सर सब यह सोचते हैं कि आखिर वे कहां से आए हैं, लेकिन इन छोटे रत्नों के निर्माण से लेकर गहनों की दुकान तक की यात्रा वास्तव में काफी प्रभावशाली है। हीरे के सान पर चढ़ने के बाद से लेकर जितनी परीक्षाओं को पार करता है वह सारा कार्य पीपीटी के जरिए बताया। हीरा खरीदने पर सावधानी बरतने के मुख्य बिन्दु बताये। जीतो चैप्टर चेयरमैन इंदरचंद बोहरा, महामंत्री सुधीर गादिया, संयोजक कमल पुनमिया ने शुभकामना दी। जेबीएन टायकूंस के विकेश जैन, किरण जैन, प्रवेश जैन, क्षितिज धारिवाल उपस्थित रहे एवं आगामी कार्यक्रम की सूचना दी। सदस्यों को अपने-अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी साझा करने का अवसर मिला। बैठक के आँकड़े में सामूहिक उपलब्धियों के अनुसार पारित रेफरल की कुल संख्या 15, कुल वैल्यू बिजनेस 3,27,180 रुपये, कुल कारोबार 14,30,896 रुपये, वन-टू-वन की कुल संख्या 155 रही। अध्यक्ष सुमन रांका ने सभी का स्वागत किया। सचिव सीमा शाह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उपाध्यक्ष पिंकी मेहता ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जेबीएन बिन्दु मेहता एवं निर्मला सुराणा ने अपने-अपने व्यवसाय के स्टॉल रखे। जेबीएन बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जीतो महिला विंग बेंगलूरु नॉर्थ अध्यक्ष बिन्दु रायसोनी, उपाध्यक्ष रेश्मा पुनमिया, महामंत्री सुमन वेदमुथा, कोषाध्यक्ष मधु कटारिया, रक्षा छाजेड़, सोमना सिसोदिया, मनीषा दोशि, पूर्व जेबीएन मंत्री तनुजा मेहता उपस्थित रहे।

निगम में कथित धोखाधड़ी के लिए पूर्व मंत्री नागेंद्र की हो गिरफ्तारी : श्रीरामुलु

राष्ट्रीय एसटी आयोग से करेंगे शिकायत

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एसटी कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले बी. नागेंद्र की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। यहां गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्रीरामुलु ने तर्क दिया कि सरकार की ओर से नागेंद्र का इस्तीफा लेना और उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही से बचना ही पर्याप्त नहीं है। पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नागेंद्र में थोड़ी भी गरिमा बची है, तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भाजपा के एसटी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वह स्वयं भी शामिल हैं, राष्ट्रीय एसटी आयोग के समक्ष इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाएगा। श्रीरामुलु ने आरोप लगाया कि एसटी कल्याण के लिए निर्धारित निधि से 80 लाख रुपये अवैध रूप से नागेंद्र के निजी सहायक बी. ए. हरीश के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। उन्होंने नागेंद्र के आवास और अन्य स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा हमें इंतजार करना चाहिए कि ईडी की छापेमारी क्या सामने लाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अच्छा काम किया होता तो ईडी को इसमें शामिल नहीं होना पड़ता।

उन्होंने आरोप लगाया कि निगम के धन का उपयोग कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा लेम्बोर्गिनी कार खरीदने और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के खर्चों को पूरा करने में किया गया। उन्होंने एसआईटी से बी. नागेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसटी विकास निगम से कथित रूप से अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए 187 करोड़ रुपये वापस लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा तब तक हार नहीं मानेगी जब तक सरकार सारा पैसा वापस नहीं ले लेती। उन्होंने सरकार से यह पता लगाने का आग्रह किया कि क्या अन्य निगमों में भी धन के गबन का कोई ऐसा ही मामला है। पूर्व मंत्री राजू गौड़ा ने चिंता जताई कि सरकार अब तक केवल 24 करोड़ रुपये ही वसूल पाई है, जबकि कथित तौर पर कुल 187 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। उन्होंने कथित गबन को जघन्य अपराध बताया। उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय के 14 कांग्रेस विधायकों से आग्रह किया कि वे कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाकर शोषित वर्गों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं।

राष्ट्रीय आयोग ने एससी/एसटी फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक सरकार से मांगी रिपोर्ट

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक संवैधानिक निकाय, ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड के उपयोग के संबंध में कर्नाटक सरकार से सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एससी/एसटी फंड के कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग पर मीडिया रिपोर्ट के बाद आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। संयुक्त सचिव राजीव कुमार तिवारी द्वारा हस्ताक्षरित 9 जुलाई के आयोग के पत्र में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए कर्नाटक अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत आवंटित फंड का उपयोग करने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने एससीएसपी और टीएसपी आवंटन से 14,730.53 करोड़ रुपये की राशि को गारंटी योजनाओं में बदलने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से विशेष घटक योजना (एससीपी) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के संदर्भ में निगरानी करने का अधिकार है। पत्र में लिखा है कि यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों के भीतर इस आयोग को प्रस्तुत की जाए। इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए। कर्नाटक भाजपा ने कथित मामले को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है।

मुडा साइट विवाद मामला

विपक्षी दल पिछड़े समुदाय के व्यक्ति के दो बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर असहिष्णु हैं : सीएम

एक राजनीतिक साजिश है

मैसूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि राज्य में विपक्षी दल पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के दो बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर ईर्ष्यालु और असहिष्णु हैं। मुडा साइट आवंटन को लेकर विरोध और आरोप महज राजनीतिक कारणों से की गई एक राजनीतिक साजिश है। सीएम ने कहा क्या मैं इससे डरूंगा? हम यह भी जानते हैं कि इसका राजनीतिक रूप से कैसे मुकाबला किया जाए। हालांकि, एक बार जब एसआईटी मुडा में कथित अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट दे देगी, तो हम खामियों को दूर करेंगे। हम मुडा को साफ करेंगे।

वह गुरुवार को मैसूरु के शारदादेवीनगर में अपने आवास के पास मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। सिद्धरामैया ने बताया कि डीसी ने 2005 में मेरे साले मल्लिकार्जुनस्वामी की कृषि भूमि को बदल दिया था और 2010 में जब उन्होंने इसे मेरी पत्नी को उपहार में दिया था, तब यह विकसित नहीं थी।

उन्होंने दावा किया कि मुडा ने 2014 में इसे अवैध रूप से अधिग्रहित किया और साइटों को विकसित करके वितरित किया। उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई के लिए उन्होंने 2021 में विजयनगर में वैकल्पिक विकसित क्षेत्र में साइटें दी हैं, जब भाजपा सत्ता में थी, भले ही हमने उस लेआउट में साइटें नहीं मांगी थीं। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें हमारी अधिग्रहीत भूमि के लिए भूमि का तीन गुना मूल्य यानी 57 करोड़ रुपये देना चाहिए।

ब्याज के साथ, मूल्य 63 करोड़ रुपये हो जाता है। श्रीरामपुरा द्वितीय चरण की एक और महिला भी है, जिसने इसी तरह से भूमि खो दी है और उसने मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अगर वे हमारी जानकारी के बिना अवैध रूप से हमारी भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? टी जे अब्राहम द्वारा उनके चुनावी हलफनामों में उल्लिखित उनकी पत्नी की संपत्ति के मूल्य के बारे में शिकायत के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा यदि चुनाव आयोग नोटिस जारी करता है, तो हम इसका जवाब देंगे। वाल्मीकि विकास निगम में कथित घोटाले के बारे में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर, उन्होंने कहा हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक बार एसआईटी जांच कर ले और एक रिपोर्ट और आरोप पत्र प्रस्तुत कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है। हो सकता है कि राजकोष ने वाल्मीकि निगम को पैसा जारी कर दिया हो। जब उनसे पूछा गया कि विपक्षी नेता वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि वह वित्त मंत्रालय भी संभालते हैं, तो उन्होंने कहा क्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों में अनियमितताओं से संबंधित कई आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया है? अधिकारी खजाने से पैसा जारी करते हैं। वित्त मंत्री के तौर पर यह बात मेरे संज्ञान में नहीं आई।

भारत चावल की अनुपलब्धता पर लोगों ने जताई निराशा

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भारत चावल, जिसे कभी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद की किरण माना जाता था, लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे जिले में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह एक राजनीतिक नौटंकी हो सकती है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किफायती दामों पर अच्छा और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई भारत चावल पहल, लोगों को इसके वापस आने का इंतजार करवा रही है।

इस योजना के तहत बिना आधार, बीपीएल या एपीएल कार्ड के, केवल मोबाइल पंजीकरण के माध्यम से चावल खरीदने के निर्देश के बावजूद, महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं। रिलायंस, फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्धता के दावे साकार नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टॉक कम है। स्थानीय

लोगों ने कहा कि भारत चावल और अन्य उत्पाद बहुत कम कीमतों पर लोगों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब यह लोकसभा चुनाव के लिए एक राजनीतिक नौटंकी की तरह लग रहा है। इस पहल में देश भर में कई लोगों की मदद करने और उन्हें भोजन कराने की क्षमता थी, जिसमें 1 किलो चावल की कीमत 29 रुपये है, लेकिन इसकी अनुपलब्धता नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा कर रही है। एक अन्य निवासी ने देरी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा भारत चावल जिले के किसी भी आउटलेट में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में, यह केवल प्रीमियम कीमतों पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे यह गरीब लोगों के लिए दुर्गम और दुर्गम हो गया है।

इसका एकमात्र समाधान चावल को आस-पास की दुकानों और राशन की दुकानों में वितरित करना है, जहाँ गरीब पृष्ठभूमि के लोग उचित मूल्य पर चावल और अन्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। एक दुकानदार ने कहा जहाँ तक मुझे पता है, भारत चावल केवल 2-3 दुकानों में उपलब्ध है, जिसमें हमारी दुकान भी शामिल है। हम चुनाव के दौरान भारत चावल बेच रहे थे, लेकिन जब से यह खत्म हुआ है, हमें कोई स्टॉक नहीं मिला है। हालाँकि कुछ अधिकारियों ने कहा है कि चावल कुछ दिनों में हमारे पास पहुँच जाएगा, लेकिन यह वर्तमान में शहर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप भी शामिल हैं।

दलित विरोधी है कांग्रेस सरकार : सुनीलकुमार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा के प्रदेश महासचिव वी. सुनील कुमार ने कहा कि भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में यह राय बनी कि कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दलित विरोधी है।

वह गुरुवार को शहर के मल्लेश्वरम में भाजपा प्रदेश कार्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे। वाल्मीकि निगम घोटाले में कांग्रेस ने वह पैसा निगल लिया जो अनुसूचित जनजाति के लिए खर्च होना चाहिए था। इसी तरह बैठक में महसूस किया गया कि इस सरकार ने गारंटी योजनाओं के लिए एसईपी और टीएसपी फंड का उपयोग करके 2 समुदायों के साथ अन्याय किया है, जिसका उपयोग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार ने इन वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया था और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थी। लेकिन आज की कांग्रेस सरकार दलितों का नाम लेकर दलितों का पैसा हड़पने के लिए भ्रष्टाचार में लगी हुई है। इस प्रयास के कप्तान सिद्धरामैया के होते हुए, यह खेदजनक है कि कैबिनेट दलितों का पैसा निगलने पर सहमत हो गई। यह घोटालों की सरकार है। मुडा घोटाला, वाल्मीकि निगम घोटाला, एसईपी, टीएसपी घोटाला, श्रम विभाग घोटाला, यह घोटालों की एक श्रृंखला है और शून्य विकास वाली सरकार है। इस मौके पर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अश्वथ नारायण उपस्थित थे।

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। *बेंगलूरु में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीबीएमपी द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को विवेकानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयनगर में बीबीएमपी के स्वास्थ्य कर्मियों ने डेंगू बीमारी के लक्षण के बारे में बताते हुए बच्चों को लापरवाही न बरतने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर महेंद्र मुणोत एवं विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे।*

दलितों पर अन्याय करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई : विजयेंद्र

बेंगलूर/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेन्द्र ने कहा कि राज्य में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने दलितों के लिए आवंटित धन को गारंटी में स्थानांतरित करके दलितों के साथ अन्याय किया है। शहर के भाजपा प्रदेश कार्यालय जगन्नाथ भवन में अपने नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार ने एसटी विकास निगम, एसईपी टीएसपी में दलितों के लिए निर्धारित राशि को गारंटी के तौर पर ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी ओर, वाल्मीकि निगम में दलितों के लिए आवंटित पैसे को लूट लिया गया और लोकसभा चुनाव में उसका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा इन्हें गंभीरता से ले रही है और संघर्ष कर रही है। सिद्धरामैया ने दलितों के लिए निर्धारित 12 हजार करोड़ रुपये गारंटी के तौर पर ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर लगभग इतनी ही रकम ट्रांसफर कर दी। गारंटी के लिए कुल 24,500 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को इस संबंध में दिल्ली से आये पत्र का जवाब देना चाहिए। हमने इसका इस्तेमाल दलितों के लिए किया। उन्होंने कहा कि कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दलितों के साथ अन्याय किया है। यह एक अक्षम्य अपराध है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदन के अंदर और बाहर इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। सिद्धरामैया अहिंदा के नेता होने का दावा कर अपनी पीठ थपथपाते हैं। उन्होंने कहा कि वे दलितों के मसीहा हैं और उन्हें खुद पर गर्व है कि उन्होंने दलितों का उद्धार किया है। इससे पहले भाजपा के राज्य कार्यालय, जगन्नाथ भवन में भाजपा के राज्य पदाधिकारियों की एक बैठक की विजयेंद्र ने अध्यक्षता की। कर्नाटक राज्य के संयुक्त प्रभारी सुधाकर रेड्डी, राज्य प्रमुख सचिव वी. सुनील कुमार, पी. राजीव, नंदीश रेड्डी, प्रीतम गौड़ा और राज्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर दबाव बढ़ाते हुए विपक्षी भाजपा ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को उनके गृह जिले मैसूरु में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। भाजपा भारत के चुनाव आयोग में याचिका दायर करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनावों में सिद्धरामैया के हलफनामे में उनकी पत्नी के पास मुडा को दी गई 3.16 एकड़ जमीन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि इस संबंध में उपहार विलेख 2009-10 में निष्पादित किया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वतम्मा को 2009-10 में अपने भाई से उपहार विलेख के माध्यम से 3.16 एकड़ जमीन मिली थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिद्धरामैया ने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामे में इसका उल्लेख नहीं किया था।

कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे

भाजपा के राज्य अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां उन्होंने पार्टी के आरोपों के समर्थन में दस्तावेज जारी किए, कि हम इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष याचिका दायर करने की संभावना जानने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं, क्योंकि यह जनप्रतिनिधि अधिनियम और चुनाव मानदंडों से संबंधित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की संलिप्तता में मुडा में करीब 4,000 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है, जिसमें वैकल्पिक स्थलों का अवैध आवंटन शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल 15 जून को एक व्यक्ति को अवैध रूप से 42 वैकल्पिक स्थल आवंटित किए गए। उन्होंने मांग की कि वैकल्पिक स्थलों के ऐसे अवैध आवंटन को वापस लिया जाए और ये स्थल गरीब और योग्य लोगों को दिए जाएं। विजयेंद्र ने आगे आरोप लगाया कि उपहार विलेख में भूमि को कृषि भूमि के रूप में उल्लेख किया गया था, हालांकि इसका भूमि उपयोग पैटर्न पहले ही गैर-कृषि में परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने सीएम के करीबी सहयोगी और शहरी विकास मंत्री बैरती सुरेश पर मुडा कार्यालय से सभी संबंधित फाइलें ले जाकर इस प्रकरण को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

महर्षि वाल्मीकि विकास निगम घोटाला

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

महर्षि वाल्मीकि विकास निगम में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई लगातार 24 घंटों से जारी है। पूर्व मंत्री नागेंद्र और महर्षि वाल्मीकि विकास निगम के अध्यक्ष और रायचूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बसनगौड़ा दद्दल से बुधवार रात से पूछताछ की जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने सुबह 5 बजे बैंक अधिकारियों को पूर्व मंत्री नागेंद्र के घर बुलाया और घर में मिले दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि नागेंद्र और दद्दल मामले को लेकर ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं और हर बात का त्वरित जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार, ईडी की टीम आगे की जांच के लिए दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के बाद गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गयी है। घर और ऑफिस में मिले कुछ दस्तावेजों की जांच के लिए आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। ईडी सूत्रों ने बताया कि उनसे जानकारी मिलने के बाद उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बुधवार को पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र और रायचूर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक बसनगौड़ा दद्दल के आवासों पर ईडी का छापेमारी शुरू हुआ, जो बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक जारी रहा। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पिछले चौबीस घंटे से मंत्री नागेंद्र के आवास की तलाशी ले रहे हैं। अधिकारियों ने विधायक दद्दल के आवास और कार्यालय समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी जारी रखी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुल अठारह जगहों पर छापेमारी की और रात बारह बजे अधिकारियों ने छापेमारी रोक दी। ईडी अधिकारियों की एक टीम नागेंद्र के आवास पर और दूसरी दद्दल के आवास पर रुकी। एक साथ अठारह से अधिक स्थानों की जांच की गई। ईडी ने पूर्व मंत्री नागेंद्र के करीबी हरीश को हिरासत में लिया और पूछताछ की। ईडी ने बसनगौड़ा दद्दल के पूर्व पीए पंपन्ना के घर पर छापेमारी की है और दद्दल के रिश्तेदारों पर हमले की बात सामने आ रही है। पंपन्ना, जो बिचचली गांव के पीडीओ के रूप में तैनात थे, पीडीओ का प्रभार लिए बिना रायचूर टी.पी. में केस वर्कर के रूप में बने रहे। वह आजाद नगर में आलीशान फ्लैट में रह रहे थे। तालुक पंचायत कार्यालय में काम करते हुए भी दद्दल का निजी व्यवसाय देख रहे थे। पंपन्ना पर घोटाले में 50 लाख रुपये का कमीशन लेने का आरोप है। आरोपों के मद्देनजर एसआईटी ने 5 जुलाई को उनसे पूछताछ की थी। ईडी ने पंपन्ना के पास से अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी अधिकारियों ने पंपन्ना के घर से मिले दस्तावेजों को स्कैन किया और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया। ईडी ने पूर्व मंत्री नागेंद्र के पीए हरीश से पूछताछ की तो पता चला कि यह डील मल्लेश्वरम में सागर होटल के पास हुई थी। हरीश दो बैग में 25 लाख रुपये ले गए। पीए हरीश द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नागेंद्र से पूछताछ की जा रही है और बयान दर्ज किया जा रहा है। ईडी को यह जानकारी चाहिए कि यह 25 लाख रुपये कौन लाया और वह पैसा कहां है। ईडी के पांच अधिकारियों की टीम फिलहाल नागेंद्र के घर की तलाशी ले रही है और बैंक अधिकारियों पर ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मंत्री से पूछताछ की जा रही है। लाख लाख कमीशन दिया गया। अवैध मनी ट्रांसफर के लिए मंत्री और अध्यक्ष के पीए लगातार बैंक के चक्कर लगाते रहे। बैंक के सीसी कैमरे के रिकॉर्ड की जांच एसआईटी पहले ही कर चुकी है, जिसे ईडी ने भी इकट्ठा कर लिया है। मंत्री और विधायक पर हमला करने से पहले उन्होंने बैंक का दौरा किया और बैंक कर्मचारियों से जानकारी जुटाई।

कर्नाटक लोकायुक्त ने 11 सरकारी अधिकारियों से जुड़े 56 ठिकानों पर मारे छापे

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक लोकायुक्त ने गुरुवार सुबह 11 आय से अधिक संपत्ति के मामलों में नौ जिलों में 56 ठिकानों पर छापे मारे। चित्रदुर्ग और दावणगेरे में दो स्थानों पर और कलबुर्गी, मांड्या, धारवाड़, बेलगावी, कोलार, मैसूरु और हासन में एक-एक स्थान पर छापे मारे गए।

अधिकारियों ने दो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों सहित 11 सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर छापे मारे। जिसमें बीबीएमपी (केंगेरी जोन) के राजस्व अधिकारी बसवराज मागी, मांड्या से सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी शिवराजू एस, लघु सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एम रवींद्र, परियोजना निदेशक शेखर गौड़ा, कार्यकारी अभियंता डीएच उमेश और सहायक कार्यकारी

अभियंता एमएस प्रभाकर से संबंधित संपत्तियां शामिल थी। इसके साथ ही लोकायुक्त अधिकारी विजयन्ना, तहसीलदार, महेश के, अधीक्षक अभियंता, एन एम जगदीश, ग्रेड 1 सचिव और के जी जगदीश, अधीक्षण अभियंता के यहां भी छापेमारी की। लोकायुक्त के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने छापेमारी से पहले ही डीए के मामलों को अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने उन अधिकारियों से जुड़ी सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए पृष्ठभूमि का काम किया था, जिन पर छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी कर्नाटक लोकायुक्त विंग और भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था की पुलिस विंग का संयुक्त अभियान है। संबंधित जिलों में कर्नाटक लोकायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक (एसपी) चल रही छापेमारी की निगरानी कर रहे हैं और 100 से अधिक अधिकारी उनकी सहायता कर रहे हैं। यह इस साल लोकायुक्त द्वारा की गई तीसरी ऐसी बड़ी छापेमारी है।

सरकारी स्कूलों में हम इंसान हैं नामक एक अभिनव कार्यक्रम होगा शुरू

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच हम इंसान हैं नाम से एक नया विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका मकसद बच्चों में सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम चालू शैक्षणिक वर्ष से ही राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में लागू किया जाएगा। अब से विद्यालयों में चर्चा, आलोचना एवं संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक भावना एवं सह-अस्तित्व विकसित करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले मार्च में मुख्यमंत्री

सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट के दौरान उन्होंने राष्ट्रकवि कुवेम्पु की समतामूलक समाज बनाने की इच्छा का उल्लेख किया था और कहा था कि हम सभी इंसान हैं। इस प्रकार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत, हमने घोषणा की है कि चालू शैक्षणिक वर्ष से हम स्कूली बच्चों के बीच सद्भाव पैदा करने और संवैधानिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब से सभी स्कूलों में शिक्षकों के लिए छात्रों के लिए वी मनुजारू नामक एक अभिनव शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रति सप्ताह दो घंटे (40 मिनट की तीन अवधि के साथ) चर्चा और बातचीत शामिल है। इसके लिए एक अवधि मूल्य शिक्षा और दो अवधि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य निर्धारित हैं। आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने और जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग (डीएसईआरटी) को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारूप जारी कर दिया है। सामाजिक समरसता और उसके महत्व पर चर्चा के लिए समरसता पाठ प्रारूप, स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों, लोक खेलों, खेल आदि पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक भावना, मूल्यपरक शिक्षा एवं सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित कर संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। प्रति सप्ताह दो घंटे (प्रत्येक 40 मिनट के तीन कार्यक्रम) का सुझाव दिया जाता है। देश के समाज सुधारकों के क्रांतियों के बारे में जानकारी देने, छात्रों को आसपास के ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाने, समाज में असमानता को खत्म करने पर चर्चा आयोजित करने के लिए कहा गया है।

विजयेंद्र ने डेंगू के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला

शिवकुमार को केवल रियल एस्टेट में दिलचस्पी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेन्द्र ने गुरुवार को राज्य में डेंगू के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि कर्नाटक सरकार को कोई परेशानी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। यहां पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा यह सरकार बिल्कुल भी परेशान नहीं है। यहां तक कि संबंधित मंत्री भी बेंगलूरु में बैठे हैं और राज्य का दौरा नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। दिन-प्रतिदिन डेंगू के मामले और मौतें बढ़ती जा रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, डेंगू के कारण नौ महीने के बच्चे की मौत हो गई। हम इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री

डीके शिवकुमार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें केवल रियल एस्टेट में दिलचस्पी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार को राज्य के विकास की कोई परवाह नहीं है। राज्य में विकास कार्य ठप हो गए हैं। अब, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने की बात कर रहे हैं। भगवान जाने कि इस फैसले के पीछे क्या एजेंडा है। पूरा कर्नाटक जानता है कि डीके शिवकुमार को केवल रियल एस्टेट में दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि इस सोच के पीछे रियल एस्टेट एजेंडा है। यह एक राजनीतिक नौटंकी है। कर्नाटक में 7000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू के मामलों के लिए हर अस्पताल में एक वार्ड में 10 बेड अलग से आवंटित करने का निर्देश दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मंगलवार को कहा था कि वे स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और सभी विभागों को स्रोत में कमी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण जिला करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपा गया है। शिवकुमार, जो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, के नेतृत्व में रामनगर जिले के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिद्धरामैया को एक प्रस्ताव सौंपा था। शिवकुमार ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपने के बाद संवाददाताओं को बताया कि यह पहल रामनगर, चन्नपटना, मगदी, कनकपुरा और हरोहल्ली तालुकों के विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में, शिवकुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण जिला करने का प्रस्ताव रखा था। विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने नाम बदलने के प्रस्ताव को रियल एस्टेट कारणों से जोड़ा। शिवकुमार ने कहा डोड्डबल्लापुर, देवनहल्ली, होसकोटे, कनकपुरा, रामनगर, चन्नपटना, मगदी के लोग मूल रूप से बेंगलूरु के ही हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए रामनगर और बेंगलूरु ग्रामीण जिलों को बेंगलूरु शहरी जिले से अलग किया गया था। हमने रामनगर जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया है।

हमारी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया: शिवकुमार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजकर एससी-एसटी के फंड को कथित तौर पर डायवर्ट करने पर जवाब मांगा है। आयोग के नोटिस पर राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि उनकी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है और ऐसा ही कानून आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है। शिवकुमार ने कहा कि 'हमने राज्य में ऐसा कानून बनाया है, जिसके तहत एक तय रकम किसी समुदाय पर खर्च की जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश में ऐसा ही कानून लाया गया था। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस समीक्षा कर रही है। गुरुवार को बेंगलूरु में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 14-15 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हमने अपनी गलतियों की समीक्षा के लिए बैठक की। हम जानते हैं कि भाजपा और जेडीएस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस नेता एमबी पाटिल भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात की चर्चा की गई कि हम 15 सीटें क्यों नहीं जीत सके। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने आठ सीटें जीतीं।

कर्नाटक के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए

केएफसीसी फिल्म पर्यटन मॉडल पर फिर से कर रही विचार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने फिल्मों के माध्यम से राज्य में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की संभावना को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया है। केएफसीसी ने इस संबंध में पर्यटन विभाग के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है और सरकार से राज्य में 100 ऐसे स्थानों की पहचान करने का आग्रह किया है जो दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर सकें। चैंबर ने सरकार से स्थानों पर शूटिंग के लिए मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने और अपनी फिल्मों के माध्यम से गंतव्यों को बढ़ावा देने वाले निर्माताओं के लिए सब्सिडी की मांग की है। ये मांगें केएफसीसी द्वारा आगामी पर्यटन नीति (2024-29) से पहले रखी गई हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 100 स्थलों की सूची तैयार करने का काम चल रहा है, जिसमें पश्चिमी घाट, समुद्र तट, पहाड़ियाँ, झरने, बाँध, स्थानीय शिल्प और व्यंजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि हवाई अड्डों,

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिन कागजी कार्रवाई शामिल है। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रबंधित विरासत स्थलों के लिए यह प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। केएफसीसी के अध्यक्ष एन एम सुरेश ने कहा कि फिल्में राज्य के 25,000 विरासत स्मारकों में से कुछ को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने कहा कन्नड़ फिल्म उद्योग हर साल 200 से ज्यादा फिल्में बनाता है। फिल्में विरासत संरचनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं और राज्य में शूटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो को आकर्षित कर सकती हैं। केएफसीसी के अध्यक्ष ने कहा कि विभाग इन स्टूडियो से संपर्क स्थापित करने के लिए मुंबई और हैदराबाद की एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकता है। फिल्म पर्यटन, एक विचार के रूप में, राज्य में रुक-रुक कर आगे बढ़ा है। कर्नाटक पर्यटन नीति 2020-25 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर शीर्ष स्थलों को दिखाने वाले फिल्म निर्माताओं को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों पर प्रकाश डाला गया है। नीति में कहा गया है कि अनुमोदन और मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन सिंगल-विंडो तंत्र का निर्माण किया जाएगा। अपनी 2018 की फिल्म पर्यटन नीति के तहत, राज्य ने फिल्मों के जरिए लोकप्रिय स्थलों को बढ़ावा देने वाले फिल्म निर्माताओं को 2.5 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन की घोषणा की। सिंगापुर में लोकेशन-स्काउटिंग के अनुभव को साझा करते हुए, बेंगलूरु के एक फिल्म निर्माता ने कहा कि यदि फिल्म लोकेशन को बढ़ावा देती है, तो अधिकारी क्रू को चिड़ियाघर में मुफ्त में शूटिंग करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। केरल के एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता संजू सुरेंद्रन ने बताया कि कोरियाई फिल्म उद्योग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर के-ड्रामा के माध्यम से गंतव्यों, व्यंजनों, फैशन और पॉप संस्कृति को बढ़ावा देने में कैसे कामयाब रहा। उन्होंने कहा जब फिल्म निर्माताओं को कुछ स्थानों पर शूटिंग के लिए बड़ी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, तो वे ऐसे स्थानों के आसपास स्क्रिप्ट लिखने से बचते हैं। हालांकि फिल्म पर्यटन प्रस्ताव पर आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है, लेकिन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की जाती है। विभाग ने कोडागु, उडुपी, हम्पी और चिकमगलूरु जैसे स्थलों को संभावित फिल्म स्थानों के रूप में बढ़ावा दिया है। अधिकारी ने कहा कि जबकि पर्यटन स्थलों का प्रबंधन विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, एकल-खिड़की मंच का निर्माण एक अंतर-विभागीय प्रयास होगा।

पतंजलि वेलनेस हुब्बल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ वेलनेस : बाबा रामदेव

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो।

अपने एक दिवसीय हुब्बल्ली प्रवास पर पहुंचे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्थापक योग गुरु स्वामी रामदेव व आचर्य बालकृष्ण ने एमडब्ल्यूबी ग्रुप के रमेश बाफना के निवास पर मुथा वागमल भुरा बाफना परिवार से मुलाकात की। साथ ही स्वस्थ जीवन की दिनचर्या बताई। 50 वर्ष से ऊपर की आयु वाले रात्रि भोजन नहीं करें। सुबह प्रभात को अमृत वेला में 5 बजे उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान करें, तथा इस समय जो भी धार्मिक अनुष्ठान करें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपके संकल्प पूरे होंगे।

बाफना परिवार ने हुब्बल्ली धारवाड़ एवं उत्तर कर्नाटक वासियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने हेतु बहुत ही पवित्र संकल्प करके हुब्बल्ली में एक सर्वश्रेष्ठ पतंजलि वेलनेस प्रारंभ किया है। वर्तमान में हरिद्वार में जो भी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है वे सारी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। यहां के निवासी इसका पूरा लाभ ले सकते है। बाफना परिवार ने यह सेवा व्यापार के लिए नहीं उपकार के लिए आरंभ की है, इसलिए यह परिवार बधाई का पात्र है। पूरे परिवार में धार्मिक वातावरण देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आजकल लोगों की दिनचर्या बहुत की अस्त व्यस्त है, जिसके कारण बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द सहित अनेक रोग होना आम बात हो गई है। इसका समाधान सिर्फ योग में है। आज समाज में बड़ी विषमता है, गरीब इंसान भोजन के लिए दौड़ रहा है, तथा अमीर आदमी भोजन पचाने के लिए दौड़ रहा है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के लिए भी सेवा देनी चाहिए। पतंजलि योगपीठ के कर्नाटक राज्य प्रभारी योगाचार्य भंवरलाल आर्य के नेतृत्व में यहां बहुत अच्छी योगसेवा चल रही है। उन्होंने अपना पर जीवन योग सेवा के लिए समर्पित किया है। लाखों लोगों को योग की दीक्षा दी है। आज कर्नाटक में योग आयुर्वेद स्वदेशी का कार्य आदर्श रूप में हो रहा है। इस अवसर पर एमडब्ल्यूबी ग्रुप के उकचंद बाफना, रमेश बाफना, गौतम बाफना, सुरेश मेहता, मुकेश बाफना, राकेश बाफना, हितेश बाफना, श्रीपाल बाफना, महावीर बाफना, ऋषभ बाफना, युवराज बाफना, निखिल मेहता, कमला देवी, सुरेखा, सुशीला बाफना सहित अन्य लोग मौजूद थे।

डेंगू से निपटने के लिए कमर कस लें अधिकारी: मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को मानसून के मौसम में डेंगू की रोकथाम और उससे निपटने के तरीकों और साधनों पर रणनीति बनाने के लिए बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (बीआरआईएमएस) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की। खंड्रे ने अधिकारियों को डेंगू के खिलाफ रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के कदमों को मजबूत करने और तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए शहर में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए छिड़काव और फॉगिंग गतिविधियों को बढ़ाया जाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे डेंगू रोगियों का डेटा एकत्र करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त शिल्पा शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश बडोले को निर्देश दिए गए कि वे स्वास्थ्य, राजस्व और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को जिले भर में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थिर पानी के संचय को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए नियुक्त करें। बैठक से पहले, खंड्रे ने ब्रिम्स अस्पताल में डेंगू के मरीजों से भी मुलाकात की। नगरीय प्रशासन मंत्री रहीम खान भी मौजूद थे।

बारिश के कारण मेंगलूरु में 83 स्कूल हुए क्षतिग्रस्त

मरम्मत अनुदान के लिए डीसी से अपील

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मानसून की शुरुआत के एक महीने के भीतर, दक्षिण कन्नड़ में 83 स्कूल बारिश और तेज हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बंतवाल में 49 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए, जबकि उल्लाल में 12 स्कूलों में नुकसान की सूचना है।

मेंगलूरु दक्षिण और बेल्टांगडी में छह स्कूल, पुत्तुर में तीन स्कूल, सुलिया में एक स्कूल, मूडबिद्री में दो स्कूल और कडाबा में चार स्कूल भी प्रभावित हुए। मुल्की में कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ

स्कूलों की कंपाउंड की दीवारें ढह गईं, जबकि अन्य स्कूलों की छत से रिसाव और दीवारों में दरारें आ गईं। कक्षाओं के दौरान किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए कुछ कक्षाओं को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है, और अन्य कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। लोक शिक्षा विभाग के अनुसार, नुकसान का अनुमान लगभग 3 करोड़ रुपये है। विभाग के आयुक्त ने स्कूलों को क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ फंड का उपयोग करने का निर्देश दिया। लोक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, स्कूलों को इस संबंध में डीसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसके लिए अनुदान जारी किए जाने की संभावना है। मेंगलूरु दक्षिण के बीईओ ईश्वर ने कहा क्षतिग्रस्त स्कूलों की एक सूची पहले ही बनाई जा चुकी है। हम इसे पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग को भेजेंगे। एक बार जब वे मरम्मत की अनुमानित लागत प्रदान करते हैं, तो इसे डीडीपीआई के माध्यम से आयुक्त को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर मरम्मत का काम शुरू होगा। यदि नुकसान गंभीर है, तो एनडीआरएफ/एसडीआरएफ फंड का उपयोग किया जाएगा।

योजनाओं का बजट न देने पर स्टालिन नाराज, कहा-

लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने नहीं सीखा सबक

चेन्नई/ शुभ लाभ ब्यूरो

तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को मक्कलुदन मुधलवार' योजना के विस्तार का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लाखों याचिकाओं में वर्णित लोगों की शिकायतों का समाधान करने, शिकायतों के निवारण के लिए सीएम हेल्पलाइन सहित सेवाओं को एकीकृत करके एक नया विभाग मुधलवारिन मुगावरी बनाने जैसी पहलों को याद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में दलों को जलन और चिढ़ हो रही है। इसीलिए वे प्रचार और बदनाम के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे उन्होंने डीएमके को वोट दिया हो या नहीं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों में ऐसी उदारता नहीं देखी जा सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के पास चेन्नई में मेट्रो रेल चरण-2 जैसी तमिलनाडु की प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में करारी हार से कोई सबक नहीं लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपने राज्य के लोगों के लिए इस तरह के प्रतिबद्ध काम से विपक्षी आवंटित करने का मन नहीं है। न ही इन्होंने अपने शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य में कोई बड़ी परियोजना लागू नहीं की है। उन्होंने कहा, ''तमिलनाडु के लोगों की ओर से, मैं कहता हूं, भाजपा को कम से कम अब यह महसूस करना चाहिए कि केंद्र सरकार सभी लोगों के लिए एक समान शासन

होनी चाहिए, जो पसंद और नापसंद से परे हो। उन्होंने कहा कि जहां तक डीएमके का सवाल है, हम लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं; यही हमारी सफलता का रहस्य है और यही तमिलनाडु के विकास का रहस्य है।

इस दौरान उन्होंने मुधलवारिन मुगावरी बताते हुए कहा कि 7 मई, 2021 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक 68.30 लाख याचिकाओं में से 66.25 लाख याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है, संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया है। वहीं धर्मपुरी जिले में 72,438 याचिकाओं में विस्तृत मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी याचिकाएं लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों को सौंपी गई थीं। इससे आगे बढ़कर, मक्कलुदन मुधलवार योजना पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसके तहत शिविरों का आयोजन करके लोगों से उनके अपने शहरों में याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं। फिर 30 दिनों के भीतर मुद्दों का समाधान किया जाता है। ऐसे मक्कलुदन मुधलवार शिविरों में प्राप्त 8.74 लाख याचिकाओं में पाए गए मुद्दों का समाधान किया गया है। धर्मपुरी जिले के शहरी क्षेत्रों में 3,107 याचिकाएं प्राप्त हुईं और 30 दिनों के भीतर 1,868 अभ्यावेदन संबोधित किए गए।

उन्होंने समझाया कि यह योजना लोगों के लिए लाभकारी है, इसलिए अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। प्रारंभ में, यह योजना नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और शहरी इलाकों से सटे ग्राम पंचायतों में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री ने 444.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी हुई 621 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही, उन्होंने 2,637 लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करने की शुरुआत करते हुए लोगों को कल्याण सहायता भी वितरित की, जिसकी कुल लागत लगभग 56 करोड़ रुपये है। धर्मपुरी जिले के लिए की जाने वाली नई पहलों पर स्टालिन की घोषणाओं में 51 करोड़ रुपये की लागत से हरूर सरकारी अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार, हरूर को उसके वर्तमान नगर पंचायत के दर्जे से नगरपालिका में अपग्रेड करना - मोबिरीपट्टी और डोड्डमपट्टी के अंतर्गत क्षेत्रों को जोड़कर और तीर्थमलाई में एक उप-कृषि विस्तार केंद्र स्थापित करना शामिल है।

बसनगौड़ा बदरली ने विधान परिषद सदस्य के रूप में ली शपथ

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

विधान परिषद की एक सदस्य सीट के लिए विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्विरोध चुने गए बसनगौड़ा बदरली ने गुरुवार को सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसौधा के सभा कक्ष में आयोजित एक समारोह में विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराट्टी की उपस्थिति में बदरली ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सदस्य की सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बसनगौड़ा बदरली को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। विपक्षी दल जद (एस) और भाजपा चुनाव से दूर रहे। इस प्रकार बदरली को निर्विरोध चुना गया। सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बदरली को अध्यक्ष बसवराज होराट्टी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मानित किया।

शोभा करंदलाजे ने शाह से वाल्मीकि निगम घोटाले की विस्तृत जांच शुरू करने का किया आग्रह

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के स्वामित्व वाले कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से धन के अवैध हस्तांतरण की गहन जांच करने का निर्देश दें। करंदलाजे ने निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी की आत्महत्या पर भी प्रकाश डाला, जिससे घोटाला सामने आया। अपने सुसाइड नोट में चंद्रशेखरन ने आरोप लगाया कि निगम से संबंधित 187 करोड़ रुपये की राशि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई। इसमें 88.62 करोड़ रुपये कुछ आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित एक सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए गए। करंदलाजे, जो कर्नाटक के लोकसभा क्षेत्र बेंगलूरु उत्तर से सांसद हैं, ने कहा कि चंद्रशेखरन की

आत्महत्या घोटाले के संबंध में उनके द्वारा सामना किए गए तीव्र दबाव और संभावित खतरों से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने शाह को लिखे पत्र में कहा चंद्रशेखरन का जाना एक बहुत बड़ा झटका है और उनकी मृत्यु से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके असामयिक निधन के कारणों की पारदर्शी और गहन जांच की तत्काल आवश्यकता है। मंत्री ने यह भी कहा कि यूनियन बैंक पर वाल्मीकि कॉरपोरेशन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा देने या उनकी अनदेखी करने के गंभीर आरोप हैं। कथित रूप से गबन किए गए धन के प्रबंधन और प्रसंस्करण में बैंक की भूमिका की जांच करना अनिवार्य है। करंदलाजे ने अपने पत्र में कहा सीबीआई में औपचारिक शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है और इस जांच को अत्यंत परिश्रम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

देवभूमि का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तानाबाना गड़बड़ाया

उत्तराखंड की बिगड़ रही सात्विक तस्वीर

जनसंख्या असंतुलन के कारण विद्रूप हो रहा पर्वतीय प्रदेश

देहरादून, 11 जुलाई (एजेंसियां)। आबादी के असंतुलन ने उत्तराखंड राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के रहने लायक 84.6 प्रतिशत भूभाग में 48 प्रतिशत आबादी रह रही है जबकि 14.4 प्रतिशत भूभाग में 52 प्रतिशत लोग बसे हैं। रोज-गार, अच्छे इलाज और बेहतर जीवन शैली के लिए पहाड़ से बड़ी आबादी का पलायन लगातार जारी है। जिससे जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है।

पिछले 24 वर्षों से पर्वतीय क्षेत्र की बड़ी आबादी का राज्य के 100 से अधिक शहरों और कस्बों में बसना जारी है। इस कारण पहले से ही आबादी के दबाव का सामना कर रहे शहरों और कस्बों की जन सुविधाएं और बुनियादी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सामाजिक ताना-बाना, रीति-रिवाज तो प्रभावित हुए ही हैं, आर्थिक और राजनीतिक हालात में भी बदलाव दिखे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी करीब 103 करोड़ थी, जो बढ़कर 141 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इस लिहाज से जनसंख्या करीब 37 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। वहीं उत्तराखंड में 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 84.89 लाख थी। 2011 के बाद राज्य की आबादी के 1.25 करोड़ होने का अनुमान है। यानी राज्य में आबादी 47 फीसदी की

दर से बढ़ रही है। चूंकि नई जनगणना नहीं हुई है इसलिए आबादी के अनुमानित आंकड़े कम या ज्यादा भी हो सकते हैं।

जानकारों का मानना है कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि बेशक विस्फोटक नहीं है लेकिन असंतुलन एक बड़ी चिंता और चुनौती का कारण है। यह असंतुलन जितना अधिक बढ़ेगा, राज्य के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक ताने-बाने को उतना अधिक छिन्न-भिन्न करेगा। इसलिए नीति नियामकों को जनसांख्यिकीय असंतुलन को संभालने के लिए गंभीर प्रयास और नीति नियोजन करने होंगे। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 3946 गांवों से 117981 लोग पलायन कर गए। वर्ष 2022 तक 6430 गांवों से 307310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। बड़ी आबादी के पलायन से पर्वतीय क्षेत्र में खेती-बाड़ी उजाड़ हो रही है और अन्य आर्थिक व पारंपरिक काम धंधे ठप पड़ चुके हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में लोग गांवों को छोड़कर वहां के छोटे कस्बों और शहरों में आ बसे हैं। भू-धंसाव के कारण सुर्खियों में रहा जोशीमठ इसका ताजा उदाहरण है। जोशीमठ में उसके आसपास के गांवों के लोग लगातार बसते गए और इस शहर पर उसकी धारण क्षमता से अधिक आबादी का दबाव बढ़ चुका है। यही हाल देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज के आसपास के ग्रामीण इलाकों का है। यूपी, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली राज्य की सीमाओं से सटे शहरों में पड़ोसी राज्य की आबादी का दबाव पहले से ही बना है। इन शहरों में पहाड़ से भी लोग पलायन कर आ रहे हैं।

स्थिति यह है कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर सरीखे मैदानी जिलों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र नए शहरों और कस्बों में बदल रहे हैं। यहां कृषि क्षेत्र लगातार घट रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2011-12 से 2022-23 तक राज्य में 156291 हेक्टेयर कृषि रकबा घट गया। 2011-12 में 909305 हेक्टेयर कृषि भूमि थी, जो 2022-23 में 753014 हेक्टेयर रह गई।

जनसंख्या संतुलन गड़बड़ाने से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी घट गया। राज्य गठन के समय पर्वतीय क्षेत्र में 40 और मैदानी क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें थीं। परिसीमन के बाद पहाड़ में छह सीटें कम हो गईं। इस तरह अब पहाड़ और मैदान की सीटों में 34:36 का अनुपात है। भविष्य में होने वाले परिसीमन में और सीटें कम होने का अनुमान है।

मैदानी और पर्वतीय सीटों में मतदात-ाओं की संख्या से जनसंख्या अंसतुलन का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2012 से 2022 के बीच 10 सालों में राज्य की मैदानी क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर 41 फीसदी से लेकर 72 फीसदी तक मतदाता बढ़े। वहीं इस अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों में मतदाताओं की संख्या आठ से 16 फीसदी की दर से बढ़ी।

शहरों में आबादी का लगातार दबाव बढ़ने से ट्रैफिक जाम, जल भराव, कूड़े की गंभीर होती समस्या और पेयजल संकट की चुनौती लगातार गंभीर हो गई है। सरकार के स्तर पर अगले 20 से 30 वर्षों को ध्यान में रखकर बेशक योजनाओं का स्वरूप तैयार हो रहा है, लेकिन इनके निर्माण की गति से अधिक नई आबादी का दबाव बढ़ने से दिक्कतें और गंभीर हो रही हैं।

पर्यटन और तीर्थाटन राज्य होने की वजह उत्तराखंड पर फ्लोटिंग आबादी का सात गुना दबाव है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम से लेकर नीति आयोग और केंद्र सरकार के मंचों पर राज्य में फ्लोटिंग आबादी के हिसाब से केंद्रीय सहायता की मांग करते हैं। राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, हेमकुंड यात्रा समेत कई धार्मिक यात्राओं में करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए सरकार को बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करानी होती है। इस बार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब के आगे राज्य की व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं।

प्रदेश के बुद्धिजीवियों का कहना है कि जनसंख्या असंतुलन के चलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन का राजनीतिक असर यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में छह विधानसभा सीटें कम हो गईं। इससे सत्ता में पहाड़ का प्रतिनिधित्व भी कम हो रहा है। आने वाले समय में परिसीमन हुआ तो और सीट कम हो जाएंगी।

एनआईए ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट

जाली नोट और आतंकवाद में 100 दोषी करार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में बीते 18 माह में 100 से अधिक आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। जांच एजेंसी द्वारा तैयार आंकड़ों के हवाले से अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि, यूएपीए एक्ट के प्रावधानों के तहत आतंकवाद और जाली भारतीय नोटों को लेकर की गई है।

जांच एजेंसी के आकंड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2023 में एनआईए ने 27 मामलों में 79 आरोपियों को दोषी ठहरा पाई थी। जबकि, इस वर्ष-2024 की पहली छमाही में विशेष अदालतों द्वारा अपना फैसला सुनाए गए छह मामलों में 26 को दोषी ठहराया गया था। वहीं अगर पिछले पांच साल के वक्त को देखें तो (2019-24) को देखा जाए तो विभिन्न एनआईए मामलों में दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या 354 हो गई हैं।

इस अवधि के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालतों में विचाराधीन 103 मामलों में से 100 मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक एफआईसीएन मामलों 18 आरोपियों को दोषी साबित करने में सफलता हासिल हुई है। अधिकारियों ने कहा कि इस अवधि के दौरान एनआईए की विशेष अदालतों द्वारा विचाराधीन 103 मामलों में से 100 मामलों में दोषसिद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक एफआईसीएन मामलों में 18 दोषसिद्धि हासिल की गई है। इसके बाद, भारत में अपने पैर फैलाने के आतंकी नेटवर्क के प्रयासों पर एनआईए की कार्रवाई के परिणामस्वरूप आईएस से संबंधित मामलों में 15 आरोपियों को सजा सुनाई गई।

हरियाणा में इनेलो और बसपा का हुआ चुनावी गठजोड़

53 विधानसभा सीटों पर इनेलो और 37 पर लड़ेगी बसपा

चंडीगढ़, 11 जुलाई (एजेंसियां)। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। चंडीगढ़ में गठजोड़ का एलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा-इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे।

1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। इनेलो ने सात लोकसभा सीटों पर और बसपा ने तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने एक अंबाला लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि इनेलो प्रत्याशी राज्य की चार लोकसभा सीटों कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के गठबंधन की पहल की है। पिछले सप्ताह ही अभय सिंह चौटाला बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं।

इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा एक सांझा घोषणा पत्र है। एससी एसटी की नौकरियां भरी जाएंगी। जो कोटा खत्म किया गया, उसे वापस दिया जाएगा। एससी-एसटी को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे।

एससी एसटी बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। एससी और बीसी को मुफ्त कॉलेज शिक्षा दी जाएगी। चाहे वे सरकारी या प्राइ-वेट किसी कॉलेज में पढ़े। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो बांड भरवाए जा रहे हैं हम उसे खत्म करेंगे। चौटाला ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर रोक लगाएंगे। हमारी पूर्व की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी जो अब खत्म हो चुकी है। हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट से हुए कई अहम खुलासे

केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन

- **मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं आरोपी नंबर 37**
- **बेल याचिका पर शीघ्र सुनवाई से कोर्ट की मनाही**

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली शराब घोटाले में दाखिल ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। कुल 38 आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने बुधवार 10 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ट्रॉयल कोर्ट से मिली बेल को रद्द कर दिया था। वहीं इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी, जिसमें से सीधे-सीधे 45 करोड़ का फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा था। ये पैसे हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए गए थे और फिर इन्हें ही चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से चार्जशीट के अनुसार, केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने अपराध की आय के 45 करोड़ रुपए अपने लिए उपयोग किए और इस तथ्य को छुपाने की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। चार्जशीट में ईडी ने मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को बताया है और उन्हें 37वें नंबर का आरोपी बनाया है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सऐप चैट की पूरी जानकारी दी। आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता के पीए विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए थे। चैट से यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ में अच्छे संबंध थे। विनोद चौहान के पास से एक करोड़ रुपए भी रिकवर किए गए थे।

चार्जशीट में बताया गया कि आरोपित विनोद चौहान के मोबाइल से

हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं।

ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि विनोद चौहान क्राइम यानी अपराध से अर्जी आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। वहीं वहाँ उन पैसों को मैनेज चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था।

ईडी ने चार्जशीट में उसका बयान भी लिया है। इसके साथ ही प्रवर्तन निद-ेशालय ने आरोप पत्र में बताया है कि केस में विजय नायर की भी अहम भूमिका थी। इस मामले में वह केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहा था। हालांकि मामले में फंसने के बाद नायर ने बता दिया था कि इस पूरे खेल को अरविंद केजरीवाल द्वारा ही चलाया जा रहा है।

दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निद-ेशालय (ईडी) ने दाखिल चार्जशीट में गोवा चुनाव का उल्लेख किया है। एजेंसी का कहना है कि गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और वह इस साजिश में शामिल थे। ईडी ने सबूत के तौर पर अरविंद केजरीवाल और के कविता के पीए व आरोपी विनोद चौहान के वॉट्सएप चैट की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराई है। यह भी बताया है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। ईडी का आरोप है कि विनोद के जरिए 25 .5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आपा को दिए गए थे।

ईडी ने अपनी चार्जशीट में प्रोसीड ऑफ क्राइम का उल्लेख किया है। विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के स्क्रीन शॉट मिले हैं। गोवा में इन पैसों को चनप्रीत सिंह ठिकाने लगा रहा था। पैसों को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक पिल्लई के बीच की बातचीत के सबूत भी ईडी के पास हैं। अशोक कौशिक का बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। उसने अभिषेक पिल्लई के कहने पर विनोद चौहान को पैसे पहुंचाए। ये मनी ट्रेल दिखाता है कि यह पैसा साउथ ग्रुप ने रिश्वत के तौर पर दिया। ईडी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पैसे की पूरी जानकारी थी। वह पूरे मामले के सूत्रधार हैं।

दिल्ली आबकारी नीति मामले के पीछे भी पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का ही है। विजय नायर, अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी है और उसकी इस मामले में बड़ी भूमिका थी।

दिल्ली शराब घोटाले में मिले पैसे अरविंद केजरीवाल ने गोवा में खर्च किए। रिश्वत में मिले 100 करोड़ में से कुछ हिस्सा उन्होंने गोवा में एक आ-लीशान होटल में ठहरने में खर्च किए थे। घोटाले का यह पैसा सीधे तौर पर इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आतंकियों के साथ ही ओवर ग्राउंड वर्कर भी हैं असली खतरा

सुरेश एस डुग्गर
जम्मू, 11 जुलाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मोर्चे पर तैनात सुरक्षाबलों के लिए खतरा सिर्फ बंदूकधारी आतंकी नहीं बल्कि उनके ओवर ग्राउंड वर्कर भी हैं जिनकी संख्या हजारों में है। ऐसे में अब सुरक्षाबल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की ओर ध्यान देने के साथ ही ओवर ग्राउंड वर्करों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। अधिकारियों के अनुसार, जम्मू संभाग को आतंकी हमलों से दहलाने में ओजीडब्लू की अहम भूमिका है।

हालत यह है कि अब प्रदेश में चलाए जा रहे अधिकतर कासो अर्थात तलाशी अभियानों में सुरक्षाबलों का जोर आतंकियों की धर पकड़ से ज्यादा ओवर ग्राउंड वर्करों की तलाश की ओर है क्योंकि अधिकारियों ने इसे माना भी है कि इन तलाशी अभियानों में अगर कोई ओवर ग्राउंउ वर्कर मिल जाता है तो समझो दो-चार आतंकियों का खात्मा पक्का है क्योंकि ये ओवर ग्राउंड वर्कर उस इलाके में सक्रिय आतंकियों के प्रति खबर रखते हैं। साथ ही ये ओजीडब्लू आतंकियों को गाइड करने के साथ ही हमले व हत्याएं करने में मदद कर रहे हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण सक्रिय आतंकियों की संख्या बेशक घट रही है मगर लगातार बड़ रहे आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्लू) की संख्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे प्रदेश में लगभग 246 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन उनके ओजीडब्ल्यू की 21186 हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जिन जिलों में एक भी आतंकी नहीं है, वहां भी उनके ओजीडब्ल्यू सक्रिय हैं। इतना जरूर था कि पांच साल पहले नए बने यूटी प्रदेश लद्दाख संभाग ही ऐसा क्षेत्र हैं, जहां न आतंकी हैं और न उनके ओजीडब्लू।

हाल ही में एक जारी की गई एक गोपनीय विभागीय रिपोर्ट में कहा गया था कि पहले सिर्फ कश्मीर में ओजीडब्ल्यू से सुरक्षाबल जूझ रहे थे पर अब उन्हें इनसे जम्मू संभाग के लगभग प्रत्येक जिले में जुझना पड़ रहा है। यही कारण है कि सुरक्षाबल सबसे पहले ओजीडब्ल्यू का खात्म करने की रणनीति तैयार करने लगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ओजीडब्ल्यू आतंकियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह रहते आम लोगों की तरह हैं, लेकिन आतंकियों के लिए काम करते हैं। यह न सिर्फ आतंकियों तक सुरक्षाबलों की सूचनाएं पहुंचाते हैं, बल्कि उनके लिए हथियारों, पैसों और सुरक्षित ठिकाने बंदोबस्त करते हैं। आतंकियों के लिए महत्वपूर्ण जगहों की रैकी करते हैं। कई बार तो आतंकी हमले का समय और जगह का चयन करने से लेकर पूरी साजिश यही ओजीडब्ल्यू रचते हैं।

बंदूक के बूते घरों में शरण ले रहे आतंकी

जम्मू, 11 जुलाई (ब्यूरो)। हीरानगर, मच्छेड़ी, रियासी और राजौरी व पुंछ के इलाकों में हुए आतंकी हमलों की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आतंकवादी बंदूक के बूते जम्मू संभाग के लोगों के घर में शरण ले रहे हैं और पेट भर रहे हैं। पिछले महीने हीरानगर के सैडा सोहल गांव में मारे गए दो आतंकियों ने भी सबसे पहले गांव के कुछ घरों में जबरदस्ती शरण लेकर भोजन और पानी की मांग की थी। हालांकि वे समय पर गांववालों द्वारा पुलिस को सूचित कर दिए जाने के कारण सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए पर बिलावर के मच्छेड़ी में हमला करने वाला आतंकियों का दल ऐसा करने में कामयाब रहा था। करीब डेढ़ दर्जन युवा आतंकियों के लिए मच्छेड़ी इलाके के गांव सडोता की एक बुजुर्ग महिला ने खाना तैयार किया था। यह जानकारी हमले के शक में पकड़े गए 24 के करीब लोगों से पूछताछ के बाद सामने आई है। यही नहीं अब यह भी सामने आया है कि ये डेढ़ दर्जन के करीब आतंकी बाद में 3 और 4 के गुटों के बंट कर विभिन्न क्षेत्रों की ओर चले गए थे।

पेपर लीक मामले में दो विधायकों के खिलाफ वारंट जारी

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

पेपर लीक मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

गाजीपुर की जखनियां सीट से सुभासपा विधायक बेदी राम और भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। स्पेशल जज पुष्कर उपाध्याय ने दोनों विधायकों समेत एक दर्जन आरोपियों के कोर्ट में हाजिर न होने के लिए वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कृष्णा नगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं।

एसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदी राम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का दावा किया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। कोर्ट ने बेदी राम और विपुल दुबे की हाजिरी माफी की अर्जी को भी खारिज कर दिया है।

फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदी राम द्वारा दिए गए शपथ पत्र से सामने आया था कि विधायक पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 केस दर्ज रहे हैं। बेदी राम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में आठ पेपर लीक से जुड़े हैं। 2009 में जयपुर में एसओजी ने रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में बेदी राम पर एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक कराने के मामले में भी एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज किया था।

इसी तरह 2006 में रेलवे का पेपर लीक कराने के मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर में बेदी राम पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। इसके बाद 2008 में रेलवे का पेपर लीक कराने में गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर 2014 में पेपर लीक कराने के मामले में आशियाना में बेदी राम पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इतना ही नहीं 21 अगस्त 2014 को यूपी एसटीएफ गैंगस्टेर एक्ट में बेदी राम की लखनऊ व जौनपुर की 8 प्रॉपर्टी कुर्क कर चुकी है।

साल 2010 में भी जौनपुर के मडियाहू में बेदी राम पर पुलिस भर्ती पेपर लीक करने में एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल, पेपर लीक से जुड़े सभी आठ मामलों में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। कोर्ट में चार्जफ्रेम/आरोप तय हो चुके हैं।

बेदी राम गाजीपुर की जखनियां विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक है। बेदीराम को सुभासपा अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का करीबी माना जाता है।

किडनी गिरोह के सात आरोपियों में आजमगढ़ का मो. शारिक

आजमगढ़, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारत व बांग्लादेश में चल रहे अंतरराष्ट्रीय किडनी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार बांग्लादेशियों समेत सात को गिरफ्तार किया है। इनमें आजमगढ़ का मोहम्मद शारिक भी शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत जिन सात लोगों को गिरफ्तार किया है, इस किडनी रैकेट के खुलासे के दौरान जांच में यह पाया गया कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, उसमें डॉ. डी. विजया राजकुमारी का निजी सहायक विक्रम सिंह रोगियों की फाइलें तैयार करने में सहायता करता था।

रोगी और डोनर का हलफनामा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। विक्रम सिंह आरोपियों से प्रति मरीज 20 हजार लेता था। पकड़े गए आरोपियों में रसेल ने अपने एक सहयोगी के रूप में मोहम्मद शारिक का नाम भी बताया। मोहम्मद शारिक डॉ. डी. विजया राजकुमारी से मरीजों का अपॉइंटमेंट लेता था और पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता था और डॉक्टर की टीम से संपर्क करता था। मोहम्मद शारिक प्रति मरीज 50 से 60 हजार लेता था।

दो आरोपियों विक्रम सिंह और मोहम्मद शारिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों रसेल अहमद, विक्रम सिंह और शारिक ने खुलासा किया कि डॉ. डी. विजया राजकुमारी को इन लोगों द्वारा जाली कागजात के आधार पर किए जा रहे प्रत्येक अवैध कार्य के बारे में पूरी जानकारी थी। मो. शारिक की तलाश में दिल्ली पुलिस 23 जून को जनपद आई थी। लेकिन, वह हाथ नहीं लगा। मोहम्मद शारिक पुत्र कलीम बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। वह दिल्ली में पैथालॉजी का संचालन करता है।

ग्रामीण एएसपी चिराग जैन ने कहा, मोहम्मद शारिक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस 23 जून को आजमगढ़ आई थी। दिल्ली पुलिस ने बिलरियागंज थाने की पुलिस की मदद मांगी। थाना पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस मोहम्मद शारिक के घर गई लेकिन घर पर वह नहीं मिला। इसके बाद शारिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। शारिक दिल्ली में पैथोलॉजी चलाता था।

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को मिली एनपीजी की मंजूरी

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) के डीपीआर की मंजूरी की दिशा में एक और सकारात्मक पहल हुई है। परियोजना को 9 जुलाई 2024 को दिल्ली में हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अर्थात एनप-ीजी की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को इसी वर्ष मार्च माह में अनुमोदन मिल चुका है।

चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी, जिसमें एलिवेटेड लंबाई 4.286 किलोमीटर, जबकि भूमिगत लंबाई 6.879 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में कुल स्टेशनों की संख्या 12 होगी, जिसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस प्रस्तावित कॉरिडोर के पूरा होने का अनुमानित समय 5 साल लगेगा और इसकी अनुमानित लागत 5081 करोड़ रुपए हैं। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर मौजूदा नार्थ साउथ कॉरिडोर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा। चारबाग मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर काम करेगा।

चारबाग से वसंत कुंज तक लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के प्रमुख स्थानों जैसे अमीनाबाद, चौक आदि को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अपने मार्ग के साथ अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को भी जोड़ेगा और लखनऊ के लोगों को सुविधा प्रदान करेगा।

प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ने वाले स्टेशनों में चारबाग (भूमिगत), गौतम बुद्ध नगर (भूमिगत), अमीनाबाद (भूमिगत), पांडेयगंज (भूमिगत), सिटी रेलवे स्टेशन (भूमिगत), मेडिकल चौराहा (भूमिगत), चौक (भूमिगत), ठाकुरगंज (एलिवेटेड), बालागंज (एलिवेटेड), सरफराजगंज (एलिवेटेड), मूसाबाग (एलिवेटेड) और वसंत कुंज (एलिवेटेड) शामिल होंगे।

अब मुफ्त में विदेशी भाषा सीख सकेंगे छात्र और प्रोफेशनल्स

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

युवाओं के कौशल को निखारकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार नए-नए कार्यक्रम ला रही है। इसी क्रम में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आज़मगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, झांसी और बांदा जिलों के छात्रों को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने की एक अनूठी पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और प्रोफेशनल्स को फ्रांसीसी, स्पैनिश और जर्मन भाषाओं में दक्षता हासिल कराना है, जिससे वे अपने प्रोफाइल में एक नई योग्यता को जोड़ सकें और अपने करियर में उन्नति करके

देश और विदेशों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें। यह प्रशिक्षण अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विशेषज्ञ संकाय द्वारा दिया जाएगा और इसका पूरा खर्च यूपी कौशल विकास मिशन के द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र इन सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि 192 घंटे होगी। इनका संचालन सप्ताहांत (वीकेंड) में किया जाएगा।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो अपने नियमित कामकाजी घंटों के अलावा अपने भाषा कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन के स्नातक छात्र और फ्रांस, कनाडा जैसे फ्रेंच भाषी देशों में रोजगार की इच्छा रखने वाले नर्सिंग और हेल्थकेयर पेशेवर शामिल हैं। विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ फैकल्टी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए जिलों का दौरा करेंगे। इसके माध्यम से छात्रों और प्रोफेशनल्स को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और साथ ही उनकी स्किल में भी इजाफा होगा। पहले चरण में 9 जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन मांग बढ़ने पर अन्य जिलों में भी इस तरह के कोर्स संचालित किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन डायरेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि सीटों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, यह पहल प्रारंभिक रूप से नौ जिलों में शुरू की जा रही है। इसका हिस्सा बनने के लिए इच्छुक छात्र और प्रोफेशनल्स यूपीएसडीएम के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने इन सभी 9 जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिलों के संबंधित संस्थानों के छात्रों को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे बिना कोई पैसा खर्च किए या फीस का भुगतान किए मुफ्त में विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित हो सकें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें।

आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को मजबूत आधार देंगे डीटीआईएस

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

भारत के डिफेंस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (डीटीआईएस) के अंतर्गत यूपीडा प्रदेश में तीन प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। कानपुर और लखनऊ में स्थापित होने वाले तीनों डीटीआईएस डिफेंस टेक्नोलॉजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर के परीक्षण की बुनियादी कमियों को दूर करने में मददगार होंगे। यूपी में डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए 117 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से 75 प्रतिशत, जबकि योगी सरकार 25 प्रतिशत का अनुदान देगी।

डीटीआईएस के जरिए लेटेस्ट टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए टेक्निकल आर एंड डी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) का कार्य किया जाएगा। साथ ही टेस्टिंग फैसिलिटी में टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए अनुशंसाएं और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता और स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करना भी डीटीआईएस का महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस स्कीम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देसी रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार हो और स्वदेशी कंपनियों को अच्छी परीक्षण सुविधाएं प्राप्त हों। इसका उद्देश्य देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीद-ारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा परीक्षण की बुनियादी संरचना में कमी को दूर करने का ये बड़ा माध्यम साबित होगा।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इन तीनों डीटीआई स्कीम को शुरू किया जाना है। इसके लिए यूपीडा को इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। यूपी में तीनों डीटीआई स्कीम के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए रणनीतिक साझेदार मिधानि (मिश्र धातु निगम लिमिटेड) लखनऊ में मैकेनिकल और मैटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी प्रदान करेगी, जिसपर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जाएंगे। वहीं आईआईटी कानपुर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की ओर से कम्युनिकेशन टेस्टिंग फैसिलिटी पर 31 करोड़ रुपए से अधिक और आईआईटी कानपुर में ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की ओर से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (यूएएस) टेस्टिंग फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। तीनों डीटीआई स्कीम को एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के जरिए स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की जाएगी।

यूपीनेडा के अधिकारियों के अनुसार डीटीआई स्कीम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में एक महत्त्व-पूर्ण कड़ी साबित होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति तो मिलेगी ही, साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, फलस्वरूप सैन्य उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी।

शिमला का सेब अब पूरब की तराई में भी

गोरखपुर में बड़े पैमाने पर सेब की खेती की तैयारी

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

शिमला का सेब तराई में भी उगेगा। ठंडे और ऊंचे पहाड़ों से शिमला के सेब को तराई में लाने की पहल हो चुकी है। यह पहल की है गोरखपुर के बेलीपार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने। तीन साल पहले केंद्र ने सेब की कुछ प्रजातियां हिमाचल से मंगाकर लगाईं। 2023 में इनमें फल आने लगे। इससे प्रेरित होकर मुख्यमंत्री के गृह जनपद के पिपराइच स्थित उनौला गांव के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह ने 2022 में हिमाचल से मंगाकर सेब के 50 पौधे लगाए। इस साल उनके भी पौधों में फल आए। इससे उत्साहित होकर वह इस साल एक एकड़ में सेब के बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक 2022 में उन्होंने हिमाचल से लाकर सेब के 50 पौधे लगाए। प्रजातियां थीं अन्ना और हरमन 99। इस साल उनमें फल भी आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में खेतीबाड़ी पर खासा फोकस है। आसानी से पारदर्शी तरीके से तय अनुदान मिल जाता है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से जरूरी सलाह भी मिली। इन सबकी वजह से सेब की खेती शुरू की। अब इसे विस्तार देने की तैयारी है। पौधों का ऑर्डर दे चुका हूं। रोपण के लिए हिमाचल से उनके आने की प्रतीक्षा है।

कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार जनवरी 2021 में सेब की तीन प्रजातियों अन्ना, हरमन- 99, डोरसेट गोल्डन को हिमाचल प्रदेश से मंगाकर केंद्र पर पौधरोपण कराया गया। 2 वर्ष बाद ही इनमें फल आ गए। यही तीनों प्रजातियां पूर्वांचल के कृषि जलवायु क्षेत्र के भी अनुकूल हैं।

हरे भरे होंगे यूपी के शहर, उपवन योजना शुरू

लखनऊ, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग ने उपवन योजना की शुरुआत की है। पर्यावरण को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और देशी जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता इस पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शहरों को हरे-भरे क्षेत्र में बदलना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, जिससे राज्य जलवायु-प्रतिरोधी बने और शहरी हरित आवरण और विकसित पार्कों से समृद्ध हो।

उपवन योजना के लिए 70 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। यह बजट विभिन्न नगरीय निकायों के बीच उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वितरित किया जाएगा। नगर निगमों को उनके परियोजनाओं के पैमाने और हरित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच प्राप्त होंगे। नगर पालिकाओं को 50 लाख से 1.5 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जबकि नगर पंचायतों को 50 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम निकायों में, नगर आयुक्त समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि पालिका और पंचायत स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेट नेतृत्व करेंगे।

शहरी क्षेत्र बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक स्थानों की कमी का सामना कर रहे हैं। उपवन योजना इन समस्याओं का समाधान करके हरियाली को बढ़ाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण और विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, यह योजना हरित क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे निवासी इन हरित स्थानों के रोपण और रखरखाव में भाग लें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करें।प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के अनुसार, उपवन योजना की रणनीति में भूमि क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक चयन महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ सुनिश्चित किया गया है। मियावाकी वृक्षारोपण विधि का उपयोग तेजी से घने और विविध हरित स्थान बनाने में किया जाएगा।

संपादकीय

जम्मू में लौटा आतंकवाद

अक्सर कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर में पाकपरस्त आतंकवाद घाटी तक ही सीमित था। जम्मू संभाग, कठुआ, डोडा, राजौरी-पुंछ में वैकल्पिक रणनीति के तहत आतंकी हमले किए जाते थे। ज्यादातर सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता था। करीब 20 साल पहले जम्मू संभाग से आतंकियों का सफाया कर दिया गया था। कुछ हद तक सरकार का यह दावा सही है, लेकिन अब जो आतंकी हमले बढ़े हैं, उनके मद्देनजर लगता है कि जम्मू क्षेत्र और उसके आसपास पाकपरस्त आतंकवाद लौट रहा है। बीते साल सबसे अधिक आतंकी हमले राजौरी-पुंछ में किए गए, जिनमें 25 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन हमारे 20 जवान भी 'शहीद' हुए। ताजातरीन हमला कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गांव में किया गया। सैनिक एक वाहन में सवार थे। यह हमला पुलवामा हमले का सारांश लगता है। इस बार भी आतंकियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। हमले में अमरीका की वे अत्याधुनिक राइफलें इस्तेमाल की गई थीं, जो आतंकियों का नाश करने के लिए पाकिस्तान को मुहैया कराई गई थीं। सवाल और जवाबदेही अमरीका और पाकिस्तान से है कि वे राइफलें आतंकियों के पास कैसे पहुंची? जाहिर है कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों की मदद कर रहा है और उनकी 'पनाहगाह' बना है। दरअसल जम्मू संभाग में आतंकी हमले लोकसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर में लबालब मतदान के जरिए लोकतंत्र के समर्थन और 9 जून को तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ-ग्रहण के बाद बढ़े हैं। चुनावी जनादेश की घोषणा की तारीख 4 जून के बाद जम्मू-कश्मीर में कुल 24 आतंकी हमले किए गए हैं, लेकिन इनमें से 18 हमले जम्मू संभाग में ही किए गए। सोमवार 8 जुलाई के कठुआ हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) समेत 5 सैनिक 'शहीद' हुए और 5 अन्य घायल हैं। न जाने उनकी तबीयत भी कैसी होगी? यकीनन सेना इन शहादतों का प्रतिशोध जरूर लेगी। इस हमले से 24 घंटे पहले सेना ने दो मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे थे, जबकि 2 जवान 'शहीद' हुए थे। कठुआ जिले में यह दूसरा आतंकी हमला है। बीती 12-13 जून को कठुआ में हमले के दौरान 2 आतंकी मार गिराए गए थे। बहरहाल हमें विश्वास है कि आतंकी जिन बिलों में छिपे होंगे, हमारा सैन्य ऑपरेशन वहां से निकाल कर उन्हें ढेर करेगा, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकियों के प्रति रणनीति बदलनी पड़ेगी। उसके बिना आतंकियों को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। राजौरी और पुंछ पाकिस्तान सरहद से सटे हुए जिले हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गुर्जर और बकरवाल आदिवासी ही इन क्षेत्रों में रह पाते हैं। इन पर आतंकियों से पैसे लेकर मदद देने का भी आरोप लगता रहा है। सेना के सामने इन्हें मुखबिर बनाने की गंभीर चुनौती है। इनकी मदद के बिना पाकपरस्त आतंकियों का सफाया असंभव है। बीते दिनों गृह मंत्रालय में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ आदि क्षेत्रों में सक्रिय 30 आतंकियों की सूची बनाई गई। यह भी तय किया गया कि आतंकियों और उनके मददगारों के सफाए के लिए 'शत्रु एजेंट्स अधिनियम' को मूल रूप में फिर लागू किया जाए। इसमें मददगारों की संपत्ति जब्त करने से लेकर उम्रकैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि सजा घटा कर 10 साल कर दी गई है। अभी यूएपीए भी लागू है, लेकिन 'शत्रु एजेंट्स अधिनियम' ज्यादा सख्त है। इसे जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, राजौरी-पुंछ में वे गुफाएं भी ध्वस्त की जाएंगी, जहां आतंकी छिपते रहे हैं। बहरहाल सवाल यह है कि भारतीय सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। कश्मीर में आतंकवाद के करीब साढ़े तीन दशक बीत चुके हैं। बेशक हमारे ऑपरेशन कामयाब भी रहे हैं। आखिर हमारी सेना पाकिस्तान से अनवरत जारी रही घुसपैठ को रोक क्यों नहीं पाई? कश्मीर में अब भी 130-135 आतंकवादी सक्रिय बताए जाते हैं। उन्हें मार क्यों नहीं दिया गया? उनके मददगारों पर कानूनी प्रहार की याद अब क्यों आई है? हमारी सेना के पास अद्भुत अस्त्र हैं। उन्हें घुसपैठियों पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान के साथ युद्धविराम का समझौता बेमानी है, लिहाजा पुनः सोच-विचार करना चाहिए। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करना होगा।

> जम्मू संभाग, कठुआ, डोडा, राजौरी-पुंछ में वैकल्पिक रणनीति के तहत आतंकी हमले किए जाते थे। ज्यादातर सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता था। करीब 20 साल पहले जम्मू संभाग से आतंकियों का सफाया कर दिया गया था। कुछ हद तक सरकार का यह दावा सही है, लेकिन अब जो आतंकी हमले बढ़े हैं, उनके मद्देनजर लगता है कि जम्मू क्षेत्र और उसके आसपास पाकपरस्त आतंकवाद लौट रहा है। बीते साल सबसे अधिक आतंकी हमले राजौरी-पुंछ में किए गए, जिनमें 25 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन हमारे 20 जवान भी 'शहीद' हुए। ताजातरीन हमला कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गांव में किया गया। सैनिक एक वाहन में सवार थे। यह हमला पुलवामा हमले का सारांश लगता है। इस बार भी आतंकियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। हमले में अमरीका की वे अत्याधुनिक राइफलें इस्तेमाल की गई थीं, जो आतंकियों का नाश करने के लिए पाकिस्तान को मुहैया कराई गई थीं।

डार्क वेब को आम तौर पर गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है

इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग महत्त्वपूर्ण

डा. वरिंदर भाटिया

> इंटरनेट का 96 फीसदी हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल चार फीसदी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा एक हिस्सा है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है। डार्क वेब को आम तौर पर गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लंदन में किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डैनियल मूर और थॉमस रिड ने 2015 में 5 सप्ताह तक 2723 लाइव डार्क वेब साइट्स की सामग्री को नजर रखी और पाया कि 57 प्रतिशत में अवैध सामग्री मौजूद थी।

डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है, जहां वैध और अवैध दोनों तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है। यह इस समय साइबर दुनिया में चर्चा का विषय है। इंटरनेट का 96 फीसदी हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल चार फीसदी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा एक हिस्सा है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है। डार्क वेब को आम तौर पर गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लंदन में किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डैनियल मूर और थॉमस रिड ने 2015 में 5 सप्ताह तक 2723 लाइव डार्क वेब साइट्स की सामग्री को नजर रखी और पाया कि 57 प्रतिशत में अवैध सामग्री मौजूद थी। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है जिसमें ई-मेल, नेट बैंकिंग आते हैं। डार्क वेब को खोलने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीजें उपलब्ध रहती हैं। डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और उनकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और री-रूट करता है। आसान शब्दों में समझें तो वो शख्स कुछ भी करे, उसे पकडना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क वेब ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहां यूजर की इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है, जिसे डिकोड करना नाममुकिन है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस न किया जा सके। कहते हैं कि डार्क वेब पर हत्या की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं, जो बेहद सस्ते में वो चीजें

भी बेचते हैं जो बैन हैं। बहुत से लोग वहां सस्ते फोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। सरे विश्वविद्यालय में डा. माइकल मैकगायर्स द्वारा किए गए एक अध्ययन 'इनटू द वेब ऑफ प्रॉफिट' से पता चलता है कि हालात बदतर हो गए हैं। 2016 से 2019 तक डार्क वेब लिस्टिंग की संख्या जो किसी उद्यम को नुकसान पहुंचा सकती है, 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है? सभी लिस्टिंग (ड्रग्स बेचने वालों को छोडक़र) में से 60 प्रतिशत संभावित रूप से उद्यमों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिग डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, नशीली दवाइयां, अवैध हथियार, नकली मुद्रा, चोरी की गई सदस्यता के क्रेडेंशियल, हैक किए गए नेटफ्लिक्स समेत अन्य अकाउंट खरीदे जा सकते हैं। यही नहीं, यहां ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदे जा सकते हैं जो आपको दूसरे लोगों के कंप्यूटर में सेंध लगाने में मदद करते हैं। हालांकि सब कुछ अवैध नहीं है, डार्क वेब का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है। उदाहरण के लिए आप शतरंज क्लब या ब्लैकबुक में शामिल हो सकते हैं, जिसे टॉर का फेसबुक जैसा एक सोशल नेटवर्क माना जाता है। अगर आपसे संबंधित डार्क वेब पर कोई जानकारी या दस्तावेज मिलते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आप जोखिम वाले स्थान पर चिन्हित हैं। अगर आपकी निजी जानकारी या ऐसी कोई जानकारी डार्क वेब पर है, जिससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, तो आप सूचना एवं प्रौद्यगिकी मंत्रालय के पोर्टल पर या पुलिस को सूचित कर अपना बचाव कर सकते हैं। डीप वेब और डार्क वेब शब्दों का इस्तेमाल कभी-कभी एक-दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। डीप वेब इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया है और इसलिए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। डीप वेब कंटेंट में वह सब कुछ शामिल है जो पेवॉल के पीछे है या जिसके लिए साइन-इन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। इसमें वह सभी कंटेंट भी शामिल हैं जिसे उसके मालिकों ने वेब क्रॉलर को इंडेक्स करने से रोक दिया है। मेडिकल रिकॉर्ड, शुल्क आधारित सामग्री, सदस्यता वेबसाइट और गोपनीय कॉर्पोरेट वेब पेज डीप वेब बनाने वाली चीजों के कुछ उदाहरण हैं। अनुमान है कि डीप वेब का आकार इंटरनेट के 96 फीसदी से 99 फीसदी के बीच है। इंटरनेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मानक वेब ब्राउजर के माध्यम से सुलभ है, जिसे आम तौर पर क्लियर वेब के रूप में जाना जाता है। डार्क वेब दरअसल डीप वेब का एक उपसमूह है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, जिसे एक्सेस करने के लिए एक विशिष्ट ब्राउजर टोर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब का आकार वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन अधिकांश अनुमान इसे कुल इंटरनेट का लगभग 5 फीसदी बताते हैं। डार्क वेब पर नेविगेट करना आसान नहीं है। यह जगह उतनी ही अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त है जितनी आप उम्मीद करेंगे जहां हर कोई गुमनाम है और एक बड़ा वर्ग ठगने के लिए तैयार बैठा हो। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए टोर नामक एक अनाम ब्राउजर का उपयोग करना आवश्यक है। टोर ब्राउजर आपके वेब पेज अनुरोधों को दुनिया भर में हजारों यूजर्स द्वारा संचालित प्रॉक्सी सर्वर की एक सीरिज के माध्यम से कनेक्ट करता है, जिससे आपके आईपी एड्रेस को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक छलावे की तरह काम करता है, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसा अनुभव होता है जो डार्क वेब जैसा ही होता है।

दृष्टि कोण

भारत को प्रभावी जनसंख्या नीति की जरूरत

वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या 8118835999 है जो वर्ष 2023 से 0.91 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या 1441719812 है जो वर्ष 2023 से 0.92 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन को पीछे छोड़ कर विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1425181397 है। जनसंख्या में वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाब डालती है। माल्थस थ्योरी के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति प्रगति से बढ़ती है तथा खाद्य उत्पादन केवल अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। मतलब आर्थिक संसाधनों में वृद्धि की गति काफी कम होती है और जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। जनसंख्या वृद्धि का भार वर्तमान संसाधनों पर पड़ता है जिससे अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, अगर उत्पादकता को जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से न बढ़ाया जाए। बढ़ती आबादी से गरीबी और असमानता बढ़ती है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी की जरूरतों से जूझ रहा होता है तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक चुनौती बन जाती है। बढ़ती आबादी से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत सरंचनाओं पर दबाव बढ़ता है तथा रोजगार के अवसर और परिवहन सुविधाएं प्रभावित होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती आबादी के बोझ से पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है जिससे जल की उपलब्धता भी कम हो जाती है। 2050 तक विश्व की अनुमानित जनसंख्या 9.7 बिलियन तथा जीवन प्रत्याशा 72.6 से बढ़ कर 77.1 वर्ष हो जाएगी। इससे संसाधनों की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या संबंधी मुद्दों और सतत विकास पर उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में स्थापित यह परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हर साल नया थीम घोषित किया जाता है। इसी के अनुसार पूरे विश्व में जागरूकता अभियान चलाया जाता है तथा इस दिशा में कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 का थीम हमें याद दिलाता है कि समस्याओं को समझने, समाधान तैयार करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह में निवेश करना महत्वपूर्ण है। वित्त भी वैसा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वल्ड पापुलेशन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि चीन की औसत वार्षिक वृद्धि दर से दुगनी से भी अधिक है, जो चिंतनीय है। भारत में शहरीकरण, साक्षरता दर के बढने, देरी से विवाह, एक बच्चा या बच्चा न करने का संकल्प, औरतों का नौकरी करना, आर्थिक मजबूरी के कारण एक बच्चा, बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आदि से प्रजनन दर कम हो गई है। प्रजनन दर 1950 में 6.18 बच्चे थी जो 2021 में 1.91 रह गई है जो 2.1 के आवश्यक स्तर से भी कम है। कम प्रजनन दर के दीर्घ समय में भारत की जनसंख्या गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेंगे, जो सोचनीय विषय है। भारत अभी युवा देश है। यहां 27 वर्ष तक की आयु वाली आधी आबादी है तथा 27 वर्ष से ऊपर वाली भी आधी आबादी है। भारत को युवा कार्यबल की आबादी, बुजुर्गों की आबादी से ज्यादा ही बनाए रखनी है। इसलिए भारत को मौजूदा जनसंख्या नीति की पड़ताल करनी चाहिए और बढ़ती जनसंख्या के बारे में सरकार को गंभीरता से लेकर इसे नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला है जिससे पानी की उपलब्धता मांग के बढने के कारण कम हो रही है। भारत में 766 जिलों में से 266 जिलों में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु तथा अन्य राज्यों में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु जल संसाधन वही हैं। जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण बढ़ जाता है जिससे ठोस अपशिष्ट 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन पैदा हो रहा है जो वर्तमान 50 करोड़ शहरी आबादी का 150000 टन प्रति दिन है। यह विकसित देशों से तीन गुणा अधिक है। शहरों के बाहर कचरा भराव क्षेत्र ने पहाड़ों का रूप ले लिया है। ये कचरे के पहाड़ टोक्सिन का रिसाव भूतल पानी में भेजते हैं। भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। 23 वर्ष में वर्तमान जीडीपी $3.73 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन तक लानी है। इसके लिए परिवार नियोजन ही जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जिम्मेदार परिवार नियोजन प्रयासों को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में व्यापक चुनौतियों के व्यापक रूप से निपटने के लिए यह कमेटी सरकार को सिफारिशें देगी। परंतु दुःख की बात है कि भारत में पिछले 13 वर्षों से जनगणना नहीं करवाई है। यह वर्ष 2021 में होनी चाहिए थी।

कुछ अलग

बूढ़ा बरगद और अघोरी पर्यावरण प्रेमी...

हालांकि मैं अघोरी पर्यावरण प्रेमी हूं, पर इतना अघोरी भी नहीं कि जून में भी पौधे लगाने निकल पड़ूं। इसलिए हर साल केवल मानसून के आने पर ही पौधे लगाता हूं। उसी खाली जगह में। बरसों से। अबके भी ज्यों ही मौसम विभाग को कहीं से भनक लगी कि मानसून आने वाला है तो उसने समाज को जागरूक करने के औपचारिक इरादे से खबर छपवाई- पर्यावरण को बचाने वाले अखबारों में फोटो छपवाने को बेकरार अपने अपने कंधों पर फावड़ा कुदाल उठा लें। हर साल की तरह नदियों के किनारे बसने वाले बहने के लिए कमर कस लें। बाढ़ मानसून आने से पहले भी आ सकती है। वे हमारी चेतावनी का इंतजार न करें। पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़ों पर संभल कर रहें। अपनी जान एक दूसरे की हथेली पर रखकर। शहर वाले अपने घरों की तीसरी मंजिल पर जाने की तैयारी कर लें। सडक़ों पर पानी बादलों के गरजने भर से भी भर सकता है तो मैंने इधर उधर से लगाने के लिए पौधे इक_ा करने शुरू कर दिए। मैं पांव के नीचे की धरती को तो धरती को, सिर के ऊपर के आसमान को भी पौधे लगाकर हरा भरा करना चाहता हूं। सो मैं अपने सिर पर के आसमान में ख्याली पौधे लगाता अपने मोहल्ले के इकलौते बचे बरगद के पास गुजरा तो बरगद ने मुझे प्रसन्न देख पूछा, 'बंधु! इतने प्रसन्न क्यों? क्या सरकार ने डीए की किस्त अनाउंस कर दी? यहां तो जनता का सब लूट भगवान और दो! भगवान और दो! कहते कहते रो रहे हैं।' 'मानसून आ रहा है मित्र! दूसरे मोहल्ले की बगल में पहुंच गया है। क्या टीवी नहीं देखते? अपडेट रहने के लिए टीवी शीवी जरूर देखा करो यार! अब इस साल भी हर साल की तरह पौधे लगाने को मेरी बांछें फडफ़ड़ा रही हैं', कह मैं हाथ में कुदाल न होने के बाद भी हवा में दोनों हाथों से पूरी ईमानदारी से कुदाल लहराता पौधे लगाने का अभिनय करने लगा। 'अब तक कितने पौधे लगा चुके हो?' 'लगा ही रहा हूं दस पंद्रह सालों से। गिनती तो कभी नहीं की।' 'वेतन के पैसे भी गिनते हो तो पौधे भी गिन लिया करो। पर पौधे लगाते कहां हो?' 'जमीन पर और कहां?' मैंने कंधे उचकते कहा। हद है यार! इतना बूढ़ा हो गया जमीन पर रहते रहते, पर इतना भी मालूम नहीं कि पौधे जमीन पर ही लगते हैं, आसमान पर तो नहीं। बहुधों के साथ ऐसा ही होता है। वे रहते तो जमीन पर हैं, पर असल में जमीन पर होते नहीं। मैंने कहा तो उसने पूछा, 'पर जमीन पर तो मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे। तुम्हें दिख रहे हों तो दिखा दो। हो सकता है इतने बरसों से जमीन पर पौधे ढूंढते ढूंढते मेरी नजरें कमजोर हो गई हों', उसके कहने पूछने पर मैंने इधर उधर देखा। वहां वहां देखा जहां मैंने पिछले कई सालों से पौधे लगाए थे। सचमुच दूर दूर तक एक भी पौधा नहीं दिख रहा था। मैंने पौधे लगाए तो फिर गए कहां होंगे? पहली बार प्रश्न सामने खड़ा और भी यक्ष सा। 'क्यों, क्या सोचने लगे?' 'कुछ नहीं।' 'नहीं मिल रहे हैं न अपने लगाए पौधे? मिलेंगे भी कहां? मिलेंगे भी क्यों? ऐसा ही है मित्र! पौधे और रिश्ते लगाने की जरूरत नहीं होती। वे खुद उग आते हैं। जरूरत है तो बस, उन्हें बचाने की। असल में तुम अब पौधे लगाते नहीं। पौधे लगाने का अभिनय भर करते हो। एक से एक के कर कमलों द्वारा तस्वीरें खींचते खिचवाते हर साल लगते तो लाखों पौधे हैं, पर बचते नहीं। कारण, तुम केवल टारगेट पूरा करने के लिए कागजों में पौधे लगाते हुए फोटो छपवाने भर को पौधे लगाते हो। पौधे लगाने को अखबारों में छपने की चीज मानते हो। जो तुमने अखबारों में पौधे लगाने के बदले अपने आप उगे पौधे ही बचाए होते तो आज हमें तुमसे बचने के लिए इधर उधर न छुपना पड़ता। जिस दिन तुम किसी अच्छे काम को फोटो खिचवाने छपवाने से हटकर करोगे उस दिन देखना समाज कैसा होगा। जब तक तुम दिखावे के लिए समाज में परमार्थ करते रहोगे तब तक न हमारा भला होगा न अंध भक्तों का। करोड़ों की गाडियों में लेटे विलासी बाबाओं की गाडियों के टायरों की प्रदूषित मिट्टी न तो चरण रज होती है और न ही स्वर्ग की प्राप्ति का साधन। न किसी नल से आज तक जनता को अमृत नसीब हुआ है।

देश दुनिया से

नेतृत्व की शालीनता से ही समृद्ध लोकतंत्र

> एनडीए गठबंधन सरकार बनाये और इंडिया गठबंधन विपक्ष का दायित्व निभाये। इसके बाद कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, लेकिन अठारहवीं लोकसभा के पहले ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में जिस तरह का व्यवहार हमारे सांसदों का रहा है, वह सवालिया निशान तो लगाता ही है कि जनतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति हम कितने सजग हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव को लेकर जिस तरह की बहस दोनों सदनों में देखने-सुनने को मिली है, वह इस संदर्भ में आश्वस्त करने वाली तो नहीं ही है। दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष को खरी-खोटी सुनायी। दोनों सदनों में नेता-विपक्ष के वक्तव्यों में से कुछ शब्द हटा दिये गये अर्थात् रिकॉर्ड में वे शब्द नहीं रहेंगे।

हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जनतांत्रिक देश है। हमें किसी से जनतांत्रिक परंपराएं सीखने की आवश्यकता नहीं है। जनतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे देश में। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नेता या तो जनतांत्रिक परंपराओं को निभा नहीं रहे या फिर उन परंपराओं को समझ नहीं रहे। अब इन्हीं चुनाव की बात करें- मतदाता ने अपना निर्णय स्पष्ट दिया है : एनडीए गठबंधन सरकार बनाये और इंडिया गठबंधन विपक्ष का दायित्व निभाये। इसके बाद कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, लेकिन अठारहवीं लोकसभा के पहले ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में जिस तरह का व्यवहार हमारे सांसदों का रहा है, वह सवालिया निशान तो लगाता ही है कि जनतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति हम कितने सजग हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव को लेकर जिस तरह की बहस दोनों सदनों में देखने-सुनने को मिली है, वह इस संदर्भ में आश्वस्त करने वाली तो नहीं ही है। दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष को खरी-खोटी सुनायी। दोनों सदनों में नेता-विपक्ष के वक्तव्यों में से कुछ शब्द हटा दिये गये अर्थात् रिकॉर्ड में वे शब्द नहीं रहेंगे। असंसदीय शब्दों के नाम पर होने वाली यह कवायद अब इस अर्थ में भी बेमानी हो चुकी है कि देश की जनता वह सब देख-सुन चुकी होती है जिसे पीठासीन अधिकारी असंसदीय घोषित करके न सुनने और न देखने लायक बता देते हैं। कथित असंसदीय भाषा से कहीं अधिक असंसदीय तो बहस के दौरान कुछ सांसदों का व्यवहार हो जाता है। सदस्यों को निष्कासित करके ऐसे व्यवहार को उजागर तो किया जाता है, पर यह प्रक्रिया इस हद तक अतार्किक हो जाती है कि पिछली संसद में से सौ से अधिक सांसदों का निष्कासन किया गया! लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने यह निर्णय अपने विवेक से किया होगा, इस पर सवाल तो उठता ही है कि इस तरह की कार्रवाई को कितना जनतांत्रिक कहा जा सकता है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर सांसदों या विधायकों का सदन में, और सदन के बाहर भी, व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस संदर्भ में मुझे ब्रिटेन के नए और पिछले प्रधानमंत्री के भाषण याद आ रहे हैं। हाल के चुनाव में ब्रिटेन के मतदाता ने सरकार पलट दी है। कंजरवेटिव पार्टी का शासन मतदाता ने नकार दिया है और लेबर पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार्मर्स ने इस अवसर पर जो भाषण दिए हैं उनमें ऐसा बहुत कुछ है जो बताता है कि राजनेताओं को एक-दूसरे के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अपनी हार को स्वीकार करते हुए ऋषि सुनक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वे इस हार का दायित्व लेते हैं और नयी सरकार को ब्रिटेन के हित में काम करने में हर उचित सहयोग देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि 'नये प्रधानमंत्री की सफलता हम सब की सफलता होगी। वे जन-हित के लिए काम करने वाले ऐसे उत्साहित व्यक्ति हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं।' ऐसा ही सम्मान प्रधानमंत्री चुने जाने वाले स्टार्मर्स ने भी ऋषि सुनक के प्रति व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'मैं निवर्तमान प्रधानमंत्री को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूं। वे हमारे देश के पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री थे। इस नाते उन्हें कुछ कर पाने के लिए जो अतिरिक्त प्रयास और मेहनत करनी पड़ी उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम उनकी निष्ठा और मेहनत को भी स्वीकारते-समझते हैं।' ये शब्द ब्रिटेन के उन दो राजनेताओं के हैं जो कल तक चुनावी-मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। ऐसा नहीं है कि वहां एक-दूसरे पर राजनेता आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाते। आरोप सब जगह लगते हैं। कुछ कटुता भी होती होगी। लेकिन नेतृत्व से जिस तरह की शालीनता की अपेक्षा होती है, कम से कम इस समय तो उनके व्यवहार में वह स्पष्ट दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां विभिन्न दलों के राजनेताओं के बीच पारस्परिक संबंध नहीं होते। ढेरों उदाहरण हैं इस आशय के जिनसे यह पता चलता है कि नीतिगत विरोध का अर्थ दुश्मनी नहीं होता। लेकिन ऐसे भी उदाहरण कम नहीं हैं जो बताते हैं कि या तो हमारे नेताओं में पारस्परिक संबंधों वाली परिपक्वता नहीं है या फिर यह कि नेताओं को लगता है कि संबंधों की मधुरता का कोई लक्षण दिख गया तो उनके राजनीतिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ जायेगा। चुनावी-सभाओं में तो नेताओं के विरोधी तेवर अक्सर दिख जाते हैं, और एक सीमा तक उनकी 'आवश्यकता' को समझा भी जा सकता है, लेकिन संसद और राज्यों की विधानसभाओं में जब राजनीतिक विरोध शालीनता की सीमाएं लांघता दिखता है तो हैरानी भी होती है और दुख भी होता है।

आप का नजरिया

स्मार्ट नहीं, कबाड़ सिटी

जो लोग कल तक बारिश का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पहली बौछारों में मालूम हो गया होगा कि शहर में कहर का होना अब एक हकीकत है। जल निकासी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलने की हरकतों का असर अब यह कि पहली वर्षा ने बता दिया कि हमारे निर्माण की औकात क्या है। यह सडक़, मोहल्ले से शहर तक आवारा है और इसीलिए हमारे स्थानीय निकाय सिर्फ चुनाव का आंकड़ा बने सियासी हस्तियों और उनकी इच्छाओं को शरण दे रहे हैं। अतिक्रमण की बाहों में फंसे गांव से शहर को अगर देखना है, तो बरसात के हर पहलू में ये कसूरवार हैं। सबसे अधिक पशुओं की आवारगी अगर शहरों में है, तो वहां के समाज में जीने की शर्तें भी लावारिस हैं। भटके तो शिमला के बंदर और बंदरों की निगाह में खुराफाती मंजर का एक मुआयना यह भी कि हर साल उनके जख्म लिए आईजीएमसी तक पहुंच जाते हैं। शहर की वास्तविकता में पीठ किसकी ठोंकी जाए और शहरी विकास महकमा कहां देखा जाए। हद यह कि प्रदेश को दो स्मार्ट सिटी परियोजनाएं मिलीं, लेकिन शिमला पर्यटक सीजन के जाम में जकड़ा रहा और धर्मशाला स्मार्ट रोड के निर्माण में अपने जल की निकासी भूल गया। मंडी शहर ने मंदिरों की प्रदक्षिणा में अपने अतिक्रमण का दस्तूर इतना दिखा दिया कि सारी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत अब पानी भरने निकल जाती है, तो तमाम बिजली परियोजनाओं से निकला पानी शहर के हर छोर से टकराने लगा है। इस साल भी डर है कि कहीं उम्मीदों से आगे निकल कर बरस गए बादल तो तेरा क्या होगा मंडी शहर। डरने लगीं नगर परिषदें और आश्चर्य करते सोलन, पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और शिमला के लोग कि आखिर नगर निगम बनाकर भी शहर क्यों कबाड़ लगने लगा। अब तो नागरिक सोचने पर मजबूर हैं कि चले तो स्मार्ट सिटी बनाने थे, लेकिन पहुंच गए 'कबाड़ सिटी' के पास। आजादी के बाद हिमाचल में एक कस्बे में पर्यटन और पर्यटन में कस्बे का विस्तार करते हुए बीड़-बिलिंग एक सर्किट बन गया, लेकिन वहां की अफरातफरी में निर्माण खूंखार और प्रकृति बीमार हो गई। चंबा व नाहन अपने आप में नगीना थे और यह श्रेय वहां के शासक राजाओं को जाता है। नाहन की जल निकासी और चंबा में बिजली व पानी की व्यवस्था ने कभी नागरिक जवाबदेही को सांस्कृतिक पटल पर सुदृढ़ किया था, लेकिन क्या इन सेवाओं के मॉडल वहां बचे। नाहन अपने विस्तार में पहाड़ खोदते-खोदते कहीं आगे निकल कर कबाड़ हो गया, तो चंबा अपनी वास्तुकला और प्रवृत्ति के खिलाफ चौगान को छीलते-छीलते तंग गलियों में बंद हो गया। आश्चर्य यह कि प्रगति ने नाहन को ऐसा मेडिकल कालेज भवन दे दिया, जिसके अगल-बगल भविष्य अपने कारनामे पर रोता रहेगा। रामपुर बुशहर अपनी भुजाओं में नदी से डरता है, तो हर छोटे-बड़े शहर ने प्राकृतिक कूहलों का नामोनिशान मिटाकर बरसात को कफन का सामान बना दिया, लेकिन पूछेगा कौन। ऑडिट करके देखें कि हिमाचल के नगर निकायों में जो कभी पार्षद बने उनके नाम शहरों की संपत्तियां कैसे लीज, किराए पर या पीपीपी मोड में उठ गईं। कभी सुबह शिमला की सैर करते हुए देखना कि आवारा कुत्ते शहर में किसकी हड्डियां खोज रहे।

पहले लेबर पार्टी से उसका 37 साल पुराना गढ़ छीना, अब संसद में गीता लेकर शपथ ली

लंदन, 11 जुलई (एजेंसियां) ।

लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद भी लेबर पार्टी को एक सीट पर करारी हार मिली। उसे अपनी 37 साल पुरानी लीसेस्टर ईस्ट सीट से हाथ धोना पड़ा है। इस सीट पर किसी और ने नहीं बल्कि गुजराती मूल की 29 साल की शिवानी राजा ने जीत हासिल की है। इसके बाद, 10 जुलाई को वह अपने हाथ में भगवद् गीता लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंची। इससे उन्होंने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

1987 से था लेबर का गढ़

बता दें कि शिवानी राजा ने कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से लीसेस्टर ईस्ट सीट पर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय मूल के लेबर उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कई मायने में शिवानी की जीत महत्वपूर्ण है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लीसेस्टर ईस्ट 1987 से लेबर का गढ़ रहा है। चुनाव में उन्हें 14,526 वोट मिले हैं, जबकि लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर अग्रवाल 10,100 वोट मिले।

गीता की शपथ लेने पर गर्व

संसद में शपथ लेने के तुरंत बाद शिवानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, लीसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में शपथ लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर सच में गर्व है।

हिंदू-मुसलमानों के बीच संघर्ष

गौर करने वाली बात है कि 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के टी-20 मैच के बाद लीसेस्टर सिटी में भारतीय हिंदू समुदाय और मुसलमानों के बीच संघर्ष देखने को मिला था। हालिया इतिहास को देखते हुए शिवानी की जीत काफी अहम है। इन तनावों के बीच संसद में उनके चुनाव को एक बड़ी जीत माना जाता है।

कौन हैं शिवानी राजा

शिवानी राजा का जन्म 21 जुलाई 1994 में लीजेस्टर के रशी मीड में हुआ था। उनके माता-पिता 1970 के दशक में भारत और केन्या से ब्रिटेन आए थे। राजा गुजराती मूल की हैं। ब्रिटेन चुनाव के दौरान राजा ने अपना काफी समय ब्रिटिश-भारतीय मतदाताओं को लुभाने में लगाया था। इन्होंने हेरिक प्राइमरी स्कूल , सोअर वैली कॉलेज, विगेस्टन और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने कॉस्मेटिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री के साथ डी मोंटफोर्ट विश्वविद्यालय से स्नातक किया।

2017 में उन्होंने मिस इंडिया यूके ब्यूटी पीजेंट में भाग लिया था, जहां वह सेमी-फाइनलिस्ट रही थीं। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो इस साल मई में राजा लीसेस्टर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी थीं। आम चुनाव के दौरान 14,526 वोटों के साथ बहुमत प्राप्त करने के बाद वह हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गईं।

ब्रिटेन की संसद में नए चेहरे

बता दें, शिवानी के अलावा 27 अन्य भारतीय मूल के सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं। इस चुनाव में सैकड़ों नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद में प्रवेश किया। यूनाइटेड किंगडम में चार जुलाई को हुए आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में ऋषि सुनक को करारी हार मिली।

न्यूज ब्रीफ

जनता के मुद्दे उठाने वालों पर बरस रहा कहर, इस साल छह महीने में ही रिकॉर्ड पत्रकारों की हत्या

इस्लामाबाद । सोचिए जिस देश में सच्चाई को सामने लाने वालों को ही मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, वहां आमजन की क्या हालत होगी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी तो यह साल बीता भी नहीं है और यहां अबतक सात पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल के शुरुआती छह महीनों में रिकॉर्ड संख्या में पत्रकार मारे गए हैं। जून में हुई थी जिब्रान की हत्या सबसे हालिया घटना की बात करें तो जून में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक स्थानीय प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष खलील जिब्रान की हत्या कर दी गई थी। दरअसल, जिब्रान कार से कहीं जा रहे थे, तभी दो लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इन बदमाशों ने पहले उन्हें कार से बाहर खींचा और फिर गोलियों से भून दिया। पत्रकारों की हत्याओं की जांच करने वाले एक संगठन के लिए काम करने वाले आदिल जवाद ने बताया कि सात में से कम से कम चार पत्रकारों की हत्या के मामले उनके काम से संबंधित थे। बता दें, जिन लोगों की जान ली गई है उनमें पारंपरिक पत्रकार और नागरिक पत्रकार शामिल थे। अधिकत मौतें छोटे शहरों और कस्बों में हुई हैं, जहां पेशेवर पत्रकारों की पहचान बढ़ाने और नागरिक पत्रकारों को मंच देने में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अधिक महसूस की गई है। जवाद ने कहा कि ये हमले अपराधियों को बचाने के लिए किए जा रहे थे। 53 में से मात्र दो मामलों में सजा वहीं, प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले फ्रीडम नेटवर्क ने कहा कि 2012 और 2022 के बीच 53 पत्रकारों को उनके काम के चलते मार दिया गया था। जबकि सजा केवल दो मामलों के दोषियों को दी गई। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में नागरिक पत्रकारिता में काफी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह सोशल मीडिया का बढ़ना और मुख्यधारा के प्रेस पर अंकुश लगना है। आम लोगों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को सामने लाने का बीड़ा उठा लिया है। इन पत्रकारों को भी बनाया निशाना मई के अंत में स्थानीय राजनेताओं, जमीन मालिकों और सामंती प्रभुओं को अपनी रिपोर्टिंग में जवाबदेह ठहराने के लिए जाने जाने वाले पत्रकार नसरुल्लाह गदानी की सिंध प्रांत के बदीन जिले में हत्या कर दी गई थी।

दुनिया के नेता मोदी जैसे आध्यात्मिक हों, नोबेल विजेता वैज्ञानिक एंटोन युवाओं के विचारों पर भी बोले

वियना । नोबेल विजेल ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी पेंटेन जिलिंगर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत की आध्यात्मिक हैं और दुनिया के कई नेताओं की उनकी इस विशेषता को धारण करना चाहिए। ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने एंटीन जिलिगर से मुलाकात की और क्वांटम तकनीक के साथ ही आध्यात्म पर भी चर्चा की भारत का आध्यात्मिक और तकनीकी अतीत बहुत व्यापक 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक ने कहा, जब आप प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अपने विचारों के आधार पर शोध को समर्थन देते हैं तभी वास्तव में नए विचार सामने आते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हर देश में हो सकता है, निश्चित रूप से भारत में भी, क्योंकि भारत का आध्यात्मिक और तकनीकी अतीत बहुत व्यापक और समृद्ध है। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की दी जानकारी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और नोबेल विजेता वैज्ञानिक की मुलाकात से इतर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताया कि उन्होंने चार प्रमुख ऑस्ट्रियाई इंडोलॉजिस्ट और भारतीय इतिहास के विद्वानों से मुलाकात की।

रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए 2025 से 2034 तक संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित, महासभा ने लिया फैसला

न्यूयॉर्क । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए 2025 से 2034 तक संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा की है। जिसमें बताया गया है कि मध्य अफ्रीका से उत्तरी चीन तक बदलते मौसम की घटनाएं स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल रही हैं। युगांडा के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत गॉडफ्रे क्वोबा, जिन्होंने 77 समूह की तरफ से प्रस्ताव पेश किया। जो कि 134 विकासशील देशों और चीन के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र समूह है। इस दौरान 193 सदस्यों को बताया गया कि इस पहल का उद्देश्य रेत और धूल के नकारात्मक प्रभावों को रोकना और कम करना है। यूएन में सदन के सदस्यों के समर्थन से अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा जोरदार ध्वनि के साथ प्रस्ताव को पास किया।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, 60 घायल

ढाका, 11 जुलाई (एजेंसियां) बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं पर ताजा हमला हुआ है, जिसमें 60 लोग घायल हो गए हैं। ये हमला ढाका की मीरांजिला कॉलेनी में हुआ। जहां हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया और मंदिर को भी निशाना बनाया गया।बुधवार 10 जुलाई 2024 को दोपहर करीब 1.30 बजे मजिस्ट्रेट मुहम्मद मोनिरुज्जमां ने हिंदू अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए ढाका में बनाई गई मीरांजिला कॉलोनी का दौरा किया। इस कदम का स्थानीय पार्षद मुहम्मद औवाल हुसैन और उनके समर्थकों ने विरोध किया और हिंदुओं पर हमला बोल दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई और घरों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमले कर उन्हें तहस-नहस कर दिया। इस दौरान मंदिर को भी निशाना बनाया गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले में कम से कम 60 हिंदू घायल हो गए, जिन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज और आसपास के अस्पताल में ले जाया गया है।ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन मीरांजिला कॉलोनी इलाके की देखरेख करता है।

यहां एक माह पहले स्थानीय लोगों को बाहर निकालने का फैसला लिया गया था और कई घरों को तोड़ा गया था, लेकिन देश में इसका विरोध और प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने घरों को खाली कराने का अभियान बंद कर दिया था। इस दौरान सिटी कॉरपोरेशन ने उन लोगों की मदद का फैसला किया, जिनके घरों को तोड़ा गया था और उन्हें मीरांजिला कॉलोनी से निकाला गया था। इन लोगों में अधिकांश हिंदू थे। यही वजह रही कि विपक्षी दल आवामी लीग के नेता और इस्लामिक कट्टरपंथी इस बात से नाराज हो गए कि हिंदुओं को फिर से क्यों इस जगह पर बसाया जा रहा है।बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले आम हो चुके हैं।

इस साल की शुरुआत में 7 जनवरी को बांग्लादेश के चुनाव के बाद बहुत सारे हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़े थे। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था और घरों को लूट लिया गया। बांग्लादेश में इस तरह के हमले फरीदपुर, सिराजगंज, बागेरहाट, झेनाइदाह, पिरोजपुर, कुश्तिया, मदारीपुर, लालमोनिरहाट, दाउदकांडी, ठाकुरगांव, मुंशीगंज और गैबांधा समेत कई जगहों पर हुए।

प्रचंड से सत्ता छीनने के लिए साथ आएगा विपक्ष, देउबा-ओली की मुलाकात से सरगर्मियां तेज

काठमांडू, 11 जुलई (एजेंसियां) ।

पिछले हफ्ते सरकार में सबसे बड़े दल सीपीएन यूएमएल ने नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। नेपाल में राजनीतिक सत्ता के लिए चल रही उठापटक अब तेज हो चली है। अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बहुमत परीक्षण से गुजरेंगे। इस परीक्षण में प्रचंड के लिए विश्वास मत हासिल करना चुनौती है। वहीं बहुमत परीक्षण से पहले एक मुलाकात के दौरान नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार के गठन को लेकर चर्चा की। इसमें तय किया गया कि संसद के तीन साल के कार्यकाल में दोनों दलों के नेता डेढ़-डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें पहले चरण में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। माना जा रहा है कि नई सरकार का गठन हो जाएगा। पिछले हफ्ते सरकार में सबसे बड़े दल सीपीएन यूएमएल ने नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके साथ ही सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी सीपीएन यूएमएल के आठ कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने पद छोड़ने से इंकार करते हुए संसद में विश्वास मत का सामना करना की बात कही। प्रचंड विश्वास मत का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह उनके लिए समर्थन जुटाना बड़ी चुनौती है। वहीं होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा से मुलाकात की। इसमें नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई। देउबा के आवास पर दो घंटे तक चली बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने नई गठबंधन सरकार के लिए हस्ताक्षर किए और समझौते को राष्ट्रपति को सौंपने पर विचार-विमर्श किया। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में छोटे दलों को भी शामिल करने पर सहमति बनी। दोनों दलों ने संसद की शेष तीन साल की अवधि के लिए बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक समझौता किया है।

बाइडन ने नाटो देशों से कहा-अपना औद्योगिक आधार मजबूत करें, रूस तेजी से रक्षा उत्पादन बढ़ा रहा

वॉशिंगटन, 11 जुलई (एजेंसियां) ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नाटो के देशों से अपना औद्योगिक आधार मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रूस अब रक्षा उत्पादन को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की थी। इसलिए आज हमको खुद से सवाल करना होगा कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। हम खुद को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसका जवाब निकलकर आता है कि हमको अपना औद्योगिक आधार मजबूत करना होगा।

चीन, उत्तर कोरिया, ईरान रूस की मदद कर रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'रूस इस वक्त रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। रूस हथियारों, युद्ध सामग्री और वाहनों में तेजी से काम कर रहा है। उसको चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की मदद मिल रही है। अब हमको भी इस नाटो गठबंधन को पिछड़ने नहीं

देना है। बाइडन बोले- मुझे खुशी है कि हम अपना औद्योगिक आधार मजबूत करने का संकल्प ले रहे बाइडन ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि हम सभी नाटो सदस्य हम यहां अपने औद्योगिक आधार और अपनी क्षमता का विस्तार करने का संकल्प ले रहे हैं। यह हमारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक जरूरी कदम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हर एक नाटो देश स्वदेशी रक्षा उत्पादन की योजना बनाने का वचन दे रहा है।

अमेरिका में 38 देशों के नेता जुटे

पहले नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए 38 विभिन्न देशों के नेता वाशिंगटन में एकत्र हुए हैं।

आईएसआई को फोन कॉल ट्रेस करने का अधिकार देने पर मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता, शहबाज सरकार की आलोचना की

इस्लामाबाद, 11 जुलई (एजेंसियां) ।

पाकिस्तान सरकार ने खुफिया एजेंसी आईएसआई को अपने नागरिकों के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर एक मानवाधिकार संगठन ने आलोचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक बयान जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को संवैधानिक रूप से संरक्षित कुछ अधिकारों का उल्लंघन बताया।

अपने बयान में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा, हम सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई असंवैधानिक अधिसूचना से बहुत चिंतित हैं। सरकार ने खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी नागरिक के फोन कॉल को ट्रेस करने का अधिकार दिया है। इसे संविधानिक रूप से संरक्षित कुछ अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने कहा, यह अधिसूचना अनुच्छेद 9, 14 और 19 के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों का घोर उल्लंघन है। यह पूर्व प्रधानमंत्री

बेनजीर भुट्टो मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की भावना का भी उल्लंघन है।

क्या था बेनजीर भुट्टो बनाम पाकिस्तान राष्ट्रपति का मामला

बता दें कि बेनजीर भुट्टो बनाम पाकिस्तान राष्ट्रपति 1996-97 तक निजता के अधिकार से संबंधित एक प्रमुख मामला था। इस मामले के अनुसार, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निजता के अधिकार के संदर्भ में टेलीफोन टैपिंग और ईव्सड्रॉपिंग के इस्तेमाल पर फैसला सुनाया था। पांच नवंबर 1996 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और बेनजीर बुट्टो को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम बेनजीर भुट्टो द्वारा निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कैबिनेट को भंग करने और फरवरी 1997 में राष्ट्रीय असेंबली के लिए आम चुनाव कराने का भी आदेश दिया। दरअसल बेनजीर भुट्टो ने शीर्ष अदालत के जजों, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों के फोन टैपिंग का आदेश दिया था। इसके जवाब में 11 और 13 नवंबर 1996 में सैयद यूसुफ रजा गिलानी और बेनजीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 9, 14 और 17 के की सुरक्षा की मांग करते हुए एक संवैधानिक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध बताया। इस मामले के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लोगों की गरिमा और घर की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी

वॉशिंगटन, 11 जुलई (एजेंसियां) ।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच आई दरारों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। यह बात विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो शिखर सम्मेलन से इतर कहा। बता दें, इस सम्मेलन में अमेरिका के हिंद-प्रशांत साझेदारों- ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

तीसरी बार किया आमंत्रित

वास्तव में, यह लगातार तीसरी बार है, जब अमेरिका ने अपने हिंद-प्रशांत भागरीदारों को आमंत्रित किया है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उनके काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संभवत: यह बात यूक्रेन द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी, जब जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने कहा था कि आज जो यूरोप में हो रहा है, वह कल पूर्वी एशिया में भी हो सकता है।

जब रूस ने किया हमला...

ब्लिंकन ने कहा, जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई तो इसके विरोध में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खड़ा हुआ। यह इस बात को दर्शाता था कि ये चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। साथ ही जब लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वे यूरोप, एशिया या कहीं और हों, हम अधिक मजबूत और अधिक प्रभावी होंगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए जैसा कि हम यहां वाशिंगटन में अपने हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आई दरारों को खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन का पहले दिन से ही एक उद्देश्य रहा है कि न केवल हमारे सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधारना बल्कि यूरोपीय भागीदारों और एशियाई भागीदारों के बीच बाधाओं को खत्म करना है।

चीन को लेकर भी विमर्श

उन्होंने यह भी कहा कि रूस और चीन से कैसे संपर्क किया जाए इस बात पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।

रूस को हथियार मुहैया करा रहा चीन

ब्लिंकन ने कहा, पिछले डेढ़ साल में जो कुछ हुआ है, उसने इस जरूरत को और मजबूत किया

है। दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि चीन रूस को अपनी आक्रामकता जारी रखने के लिए हथियार नहीं दे रहा है, बल्कि मॉस्को के रक्षा औद्योगिक बेस में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रूस जिन 70 प्रतिशत मशीन टूल्स का आयात कर रहा है वे चीन से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मॉस्को द्वारा उपयोग किए जाने वाले 90 प्रतिशत माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आ रहे हैं। बीजिंग ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

दो नाव की सवारी नहीं कर सकता चीन

उन्होंने कहा, हमने पिछले डेढ़ साल में टैंक, मिसाइल, युद्ध सामग्री जैसे इसके हथियारों में बड़ी वृद्धि देखी है। चीन द्वारा मॉस्को को यह हथियार दिए जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि यूरोपीय सहयोगी यूरोप की सुरक्षा के लिए चीन द्वारा उत्पन्न चुनौती को समझते हैं। निश्चित तौर पर चीन दोनों तरह से नहीं चल सकता है। उन्होंने आगे कहा, यह सब एक साथ नहीं हो सकता है या यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह शांति के लिए है और यूरोप के साथ बेहतर संबंध चाहता है, जबकि साथ ही, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से यूरोपीय सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरे को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध

शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा, हम इसे रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों में देखते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है। इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही कुछ हाइब्रिड खतरों में, जिनका आपने पहले उल्लेख किया था, संबंध स्पष्ट और स्पष्ट होते जा रहे हैं। गठबंधन (नाटो) एक ऐसा स्थान है और शायद मैं तर्क दूंगा कि एक केंद्रीय स्थान है, जहां हम सभी को एक साथ ला सकते हैं ताकि हम एक साथ काम कर सकें। चीन पर दो तरह से ध्यान उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन पर दो तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा, पहला, हम अपने देश में निवेश कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम घरेलू ताकत की स्थिति से चीन से मुकाबला कर रहे हैं। जब आप हमारे अपने बुनियादी ढांचे - हमारी सड़कों, हमारे पुलों, हमारे संचार - में अविश्वसनीय निवेश के साथ पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुई हर चीज को देखते हैं, जब आप यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को देखते हैं कि हम अपने नेतृत्व, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक पर हमारे विश्व नेतृत्व को बनाए रखें, जब आप जलवायु प्रौद्योगिकी में किए गए निवेशों को देखते हैं, जो 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को ताकत की स्थिति में रखता है। यूरोपीय सहयोगी ठीक यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इसका दूसरा पहलू न केवल यूरोप के साथ शुरू होने वाले हमारे गठबंधनों और साझेदारियों को फिर से सक्रिय करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि चीन द्वारा उत्पन्न कुछ चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण समान हो। नाटो ने रणनीतिक अवधारणा में क्या कहा उन्होंने कहा, मुझे लगता है ।

विम्बलडन सेमीफाइनल में जोकोविच से भिड़ेंगे इटली के मुसेटी

लंदन, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में इटली में सभी की निगाहें जानिक सिनर पर थीं, लेकिन यह लोरेंजो मुसेटी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर और 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच के साथ मुकाबला करने की देश की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ऑस्ट्रेलियाई एलेक्स डी मिनौर के चोट के कारण नाम वापस लेने के बाद जोकोविच सेमीफ़ाइनल में पहुंचे हैं।

मुसेटी ने अपने करियर का अब तक का संभवत: सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन करते हुए टेलर फ्रिट्ज़ को 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 से हरा दिया। ऐसा करने पर, 22 वर्षीय खिलाड़ी इवेंट के इतिहास में केवल चौथा इतालवी पुरुष एकल सेमीफाइनलिस्ट बन गया।

वर्ल्ड नंबर 1 सिनर के दानिल मेदवेदेव से हारने के बाद भी, मुसेटी ने अपने पहले प्रमुख क्वार्टरफाइनल में उत्कृष्ट और संयमित प्रदर्शन के साथ इतालवी टेनिस की ताकत की तुरंत याद दिला दी। 25वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने ग्रास-कोर्ट के एक विशिष्ट प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने के लिए अपने स्लाइस बैकहैंड का शानदार इस्तेमाल किया और जोकोविच के साथ अंतिम-चार मुकाबले की तैयारी कर ली।

दो बार के एटीपी टूर टाइटलिस्ट मुसेटी ने तीन घंटे, 27 मिनट में यह मुकाबला जीता। ऑल-इंग्लैंड क्लब के नंबर 1 कोर्ट पर अपनी पहली उपस्थिति में मुसेटी की जीत की नींव उनकी सर्विस थी। मुसेटी ने एटीपी टूर के सबसे बड़े सर्वरों में से एक के खिलाफ अर्जित 13 ब्रेक प्वाइंट में से छह को परिवर्तित किया।

हालाँकि, तीन बार के ईस्टबॉर्न चैंपियन फ़िरट्ज़ मैच की स्थिति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। मुसेटी ने विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट के रूप में अपने देशवासियों निकोला पिएट्रांगेली (1960), माटेओ बेरेटिनी (2021) और सिनर (2023) के साथ जुड़ने के लिए एक प्रसिद्ध जीत हासिल की।

एलेक्स डी मिनौर चोट के कारण जोकोविच के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले विंबलडन से हट गए। नौवीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई ने घोषणा की कि वह सात बार के चैंपियन जोकोविच के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में, डी मिनौर ने आर्थर फिल्स के खिलाफ चौथे दौर की जीत के अंतिम चरण में अपने कूल्हे की चोट के बारे में बात की थी, और वह सेंटर कोर्ट पर दूसरी वरीयता प्राप्त जोकोविच से मुकाबला करने के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए।

न्यूज ब्रीफ

टोक्यो की निराशा भुलाकर पेरिस में प्रभावित करने उतरेंगे निशानेबाज

नई दिल्ली। भारतीय निशानेबाज पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ (एनआरएआई) ने भी इसके लिए कमर कस ली है। टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक से पहले निशानेबाजी दल में निजी प्रशिक्षकों को लेकर काफी विवाद हुए थे, जिसका प्रभाव टीम के प्रदर्शन पर पड़ा था। इससे सीख लेते हुए ओलंपिक के दौरान विवादों से दूर रहने के लिए एनआरएआई ने निशानेबाजों के साथ उनके निजी प्रशिक्षकों को पेरिस भेजने की मंजूरी दे दी है। इन निशानेबाजों ने रखी थी मांग तीन इवेंट में हिस्सा ले रहीं मनु भाकर, अनीश, विजयवीर सिद्ध, रिदम सांगवान, राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस में निजी प्रशिक्षकों का साथ मांगा है। एनआरएआई, साई ने निजी प्रशिक्षकों को मंजूरी दे दी है। पांचों प्रशिक्षक निशानेबाज के खेल गांव में नहीं ठहरेंगे। उन्हें नजदीक के होटल में ठहराया जाएगा। मनु भाकर ने ओलंपिक के लिए दिग्गज जसपाल राणा, अनीश ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरप्रीत सिंह, विजयवीर सिद्ध ने इन्हीं खेलों के स्वर्ण पदक विजेता गुरप्रीत सिंह, रिदम सांगवान ने विनीत कुमार और राजेश्वरी कुमारी ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चेक गणराज्य के डेविड कोस्टेलेकी को अपने साथ ओलंपिक में ले जाने की मांग की थी। सभी ने टॉप्स के जरिये अपने निजी प्रशिक्षकों को ले जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मिशन ओलंपिक सेल ने मंजूर कर लिया। रिकॉर्ड 21 शूटर पेरिस में उतरेंगे ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये निशानेबाज पेरिस में 27 पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत से अधिक सिर्फ चीन के 22 निशानेबाज होंगे। ओलंपिक में उतरने जा रही युवा निशानेबाजी टीम है। मनु, ऐश्वर्य, एलावेनिल, अंजुम को ओलंपिक का अनुभव है। इन निशानेबाजों से देश को इस बार पदक लाने की भी उम्मीद रहेगी।

जडेजा सहित कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर , श्रेयस को मिल सकता है अवसर

मुम्बई। गौतम गंभीर के भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनने के साथ ही टीम में बदलाव होने भी तय हैं। ऐसे में जहां कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह मिल सकती है। वहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ सकता है। इन खिलाड़ियों में ऑलरांडर रविन्द्र जडेजा भी हैं। जडेजा टीम के मैच विजेता खिलाड़ी रहे हैं पर पिछले काफी समय से वह लय में नहीं हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी पहले जैसी नहीं रही। ये लगातार देखने में आया है। मैदान में वह गेंदबाजी के दौरान विकेट नहीं ले पा रहे। दूसरी और उनका बल्ला भी खामोश है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी जगह कोई युवा खिलाड़ी ले सकता है। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं और उन्हीं में से किसी खिलाड़ी को जडेजा की जगह मिल सकती है। वहीं टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे की संभावनाएं भी अब तकरीबन समाप्त हो गयी हैं। रहाणे पहले ही टी20 और एकदिवसीय प्रारुप से बाहर हो गये थे। अब गंभीर के आने के बाद उनकी टेस्ट फॉर्मेट में भी वापसी संभव नहीं है क्योंकि अब वह 36 साल के हो गये हैं और गंभीर ऐसे खिलाड़ियों को रखना चाहेंगे जो लंबे समय तक रहे। इसके अलावा टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की वापसी की संभवना भी समाप्त हो गयी है। पुजारा पिछले काफी समय से टीम से बाहर हैं और उनकी उम्र भी 36 साल की हो गयी है। ऐसे में उनका कैरियर भी अब समाप्त है। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की वापसी की संभावनएं प्रबल हो गयी हैं। श्रेयस को घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के बाद टीम से बाहर कर दिय गया था हालांकि उन्होंने एकदिवसीय विश्वकप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। श्रेयस आईपीएल विजेता केकेआर टीम के कप्तान हैं जबकि गंभीर इसी टीम के मेंटोर रहे हैं और उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में अब श्रेयस की वापसी की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं।

रुतुराज सहित युवा खिलाड़ियों के पास विराट, रोहित और जडेजा की जगह लेने का अवसर

हरारे। युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने कहा है कि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली की जगह लेना काफी मुश्किल है पर उनका लक्ष्य किसी भी क्रम पर बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। टी20 विश्व कप जीत के बाद विराट के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने छोटे प्रारुप को अलविदा कह दिया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास इनकी जगह हासिल करने का अवसर है। ऐसे माना जा रहा है कि रुतुराज गायकवाड़ को विराट के स्थान पर जबकि अभिषेक शर्मा को रोहित की जगह खेलने का अवसर मिल सकता है। वहीं रुतुराज ने कहा कि अभी इस बारे में वह नहीं सोच रहे हैं। साथ ही कहा कि कोहली से तुलना करने के बारे में सोचना या उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास करना भी बेहद कठिन है।

चैंपियंस ट्रॉफी- भारत के पाकिस्तान जाने के आसार नहीं : बीसीसीआई दुबई या श्रीलंका में मैच कराने के लिए आईसीसी से अपील कर सकता है

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। अभी बीसीसीआई ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज में खेलने भी भारत नहीं गया था। भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे।

पीसीबी अध्यक्ष ने तय किया 15 मैचों का कार्यक्रम

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगा, जिसमें 10 मार्च फाइनल के लिए रिजर्व डे होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के 15 मैचों का ड्राफ्ट आईसीसी को भेज दिया है। आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के बोर्ड से सहमति लेने के बाद ही इस शेड्यूल को अप्रूव करेगा।

पाकिस्तान 1 मार्च 2025 को लाहौर में सबसे बड़े राइवल भारत से भिड़ सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक इस मैच के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। आईसीसी बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने पीटीआई को यह जानकारी दी थी।

1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि, पीसीबी ने 2008 में पूरे एशिया कप की मेजबानी की थी और पिछले साल भी एशिया कप के कुछ मैच पकिस्तान में हुए थे।

पीसीबी ने भारत के सभी मुकाबले लाहौर में कराने का प्रस्ताव भेजा था

रिपोर्ट के मुताबिक, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने 15 मैचों का शेड्यूल आईसीसी को भेजा है। जिसमें भारत के सभी मैच सुरक्षा कारणों की वजह से लाहौर में रखे गए हैं। आईसीसी बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, पीसीबी ने 15 मैचों की आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। लाहौर में सात, कराची में तीन और रावलपिंडी में पांच मैच होंगे। शुरुआती मैच कराची में होंगे, जबकि दो सेमीफाइनल कराची और रावलपिंडी में होंगे। इसके अलावा फाइनल मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा। भारत के सभी मैच लाहौर में होंगे, अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो यह मैच भी लाहौर में ही होगा।

दो ग्रुप में आठ टीमें

भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं। हाल ही में आईसीसी के इवेंट प्रमुख क्रिस टेटली ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, जब सुरक्षा टीम ने आयोजन स्थलों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था।

भारत के कहने पर एशिया कप के मैच श्रीलंका में हुए थे

पिछले साल भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। तब भी भारत के वहां नहीं जाने पर यह टूर्नामेंट 'हाइब्रिड मॉडल' पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे। कोलंबो में हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर चैंपियनशिप जीती थी।

1996 के बाद टीम को पहली बार मिली मेजबानी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी ने टूर्नामेंट के वेन्यू का ड्राफ्ट आईसीसी को सौंप दिया है। टूर्नामेंट के आयोजन अगले साल फरवरी-मार्च में होना है। वनडे वर्ल्ड कप 1996 के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी गई है।

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पकिस्तान को हराया था

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट चेज नहीं करने दिया। पाकिस्तान की टीम 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। टी-20 इंटरनेशनल में भारत ने यह सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। टीम इंडिया 119 रन पर ऑलआउट हो गई।

वाटकिंस के अंतिम समय में किए निर्णायक गोल से जीता इंग्लैंड, नीदरलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा

डॉर्टमुंड, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर खेलने उतरे ओली वाटकिंस ने स्टॉपेज टाइम में निर्णायक गोल दागकर इंग्लैंड को लगातार दूसरी बार यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप (यूरो कप) फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कराया। डॉर्टमुंड में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड को 2-1 से हराया। मैच के अंतिम समय में वाटकिंस ने कोले पालमेर द्वारा मिले पास पर कॉर्नर से शानदार गोल दागा और टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में सफल रहे। इंग्लैंड का सामना अब खिताबी मुकाबले में स्पेन से होगा जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल मैच में फ्रांस को 2-1 से मात दी थी।

इंग्लैंड की अच्छी नहीं रही थी शुरुआत

इंग्लैंड की इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और जावी सिमंस ने सातवें मिनट में ही गोल कर नीदरलैंड को शुरुआती बढ़त दिला दी थी। हालांकि, इंग्लैंड ने भी वापसी करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और हैरी केन ने 18वें मिनट में मिली पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पहला हॉफ बराबरी पर छूटा, जबकि दूसरे हॉफ में दोनों टीमों ने बढ़त लेने की पुरजोर कोशिश की। मुकाबला अतिरिक्त समय में जाता दिख रहा था, लेकिन तभी सब्स्टीट्यूट खिलाड़े के तौर पर उतरे वाटकिंस ने पालमेर द्वारा मिले पास पर स्टॉपेज टाइम के पहले ही मिनट में गोल करने का मौका नहीं गंवाया।

इंग्लैंड को लंबे समय से खिताब का इंतजार

गारेथ साउथगेट की टीम इंग्लैंड का अभियान इस यूरो कप में भी शानदार रहा है और वे लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। इंग्लैंड की कोशिश 1966 के बाद अपना पहला बड़ा खिताब जीतने की है। इसके लिए उसे फाइनल में स्पेन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा जिसने अब तक शानदार खेल दिखाया है। नीदरलैंड 1988 में जर्मनी में आयोजित पिछले यूरो में अपनी जीत दोहराने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी वर्तमान टीम में मार्को वैन बास्टेन या रूड गुलिट जैसी स्टार खिलाड़ी की कमी दिखी। अगर नीदरलैंड की टीम सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने में सफल रहती तो यह 2010 विश्व कप के फाइनल की तरह मुकाबला होता।

हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब (एचपीआरसी) शनिवार (13 जुलाई) को अपने परिसर में अत्याधुनिक सिल्वर स्पर एथलेटिक एरिनाफलॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य कार्यक्रम की प्रस्तावना के तौर पर गुरुवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्सी लॉन्च की। जर्सी लॉन्च के मौके पर क्लब के उपाध्यक्ष कुंवर साई विजेंदर सिंह, अध्यक्ष चैतन्य आर. कुमार, स्पर स्पोर्ट्स एरिना के प्रभारी और सचिव (प्रशासन) अहमद शेख रियाज मोइनाबाद मंडल के अजीज नगर स्थित एचपीआरसी में मौजूद थे।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह टी20 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी चहल से मिले

हरियाणा, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

गुरुग्राम और दिल्ली दौरे पर निकले हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने विश्व विजेता टीम इंडिया के सदस्य युजवेंद्र चहल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चहल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। टीम इंडिया ने बारबाडोस में 29 जून को दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले युजवेंद्र चहल 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसके चलते उन्हें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। इस दौरान चहल का परिवार भी वहां मौजूद था। युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद जिले में हुआ था। शुरुआती दिनों में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब छकाने वाले चहल टी 20 विश्व कप 2024 की टीम में प्लेइंग-11 में जगह बनाने में सफल नहीं हुए, लेकिन टीम इंडिया में हमेशा उनका योगदान अतुलनीय रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर लिखा, टी20 विश्व कप की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और हरियाणा की मिट्टी के लाल युजवेंद्र चहल से मिलना हुआ। युजवेंद्र चहल ने पूरे देश सहित हरियाणा के असंख्य युवाओं को क्रिकेट के प्रति और खेलों में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। इस शानदार विजय के लिए उनको और समस्त भारतीय टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर चहल और नायब सिंह की मुलाकात का फोटो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सीएम ने चहल को पहले विश्व कप विजेता मेडल पहनाया। फिर शाल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए उस मुकाबले में भारत ने 7 रनों से जीत हासिल की थी। भारत ने प्रतियोगिता में कोई मैच नहीं हारा था और 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को समाप्त किया था। विश्व कप का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद कप्तान रोहित समेत टीम के सभी खिलाड़ी काफी भावुक थे। रोहित और विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। भारतीय टीम के स्वदेश आगमन के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ था। टीम से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और फिर टीम मुंबई के मरीन ड्राइव से विजय परेड में भाग लेते हुए वानखेड़े स्टेडियम गई थी, जहां बीसीसीआई ने टीम को सम्मानित किया था।

धनराज पिल्लै की बराबरी पर पहुंचे मिडफील्डर मनप्रीत अपने चौथे ओलंपिक के लिए तैयार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसियां)।

पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में होने वाला है। खेल के इस महाकुंभ को लेकर भारतीय दल तैयार है। इस बीच भारतीय हॉकी टीम के वरिष्ठ मिडफील्डर मनप्रीत सिंह पेरिस में अपने चौथे ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित हैं।

यह एक ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो उन्हें इस खेल के दिग्गज धनराज पिल्लै के बराबर खड़ा करती है।

अपने चौथे ओलंपिक में खेलने के लिए तैयार, मनप्रीत ने अपनी खुशी और गर्व व्यक्त करते हुए कहा, मेरा चौथे ओलंपिक में खेलना एक सपने के सच होने जैसा है। यह मेरे परिवार, कोचों और साथियों के वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट समर्थन का प्रमाण है। धनराज पिल्लै जैसे दिग्गज के नक्शेकदम पर चलना, जो मेरे सहित अनगिनत खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा रहे हैं, शब्दों से परे सम्मान है।

उन्होंने आगे कहा, मैं पेरिस में भारत के लिए अपना बेस्ट देने को लेकर उत्साहित हूं, न केवल टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, बल्कि देश में लाखों प्रशंसकों की उम्मीदों और सपनों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं। हमारी टीम दुनिया को भारतीय हॉकी की भावना और ताकत दिखाने के लिए तैयार है।

हमने कड़ी मेहनत की है, और हम अपने देश को सम्मान दिलाने और अपने देशवासियों को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ हैं।

मनप्रीत ने 2011 में सीनियर टीम में डेब्यू किया। तब से इस मिडफील्डर ने 370 कैप हासिल किए हैं और 27 गोल किए हैं, जिससे मैदान पर उनके कौशल और निरंतरता का पता चलता है।

राष्ट्रीय टीम के साथ उनके सफर में पिछले तीन ओलंपिक खेलों में भागीदारी शामिल है। 2012 लंदन ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक, जहां उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया, जो 41 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक हॉकी पदक था।

साथ ही, पेरिस ओलंपिक के लिए टीम की मानसिकता और उम्मीदों के बारे में बात करते हुए मनप्रीत ने कहा, हम पर कोई दबाव नहीं है। हम हर मैच में अपने प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं। हमें किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे उनकी रैंकिंग कुछ भी हो। प्रत्येक टीम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और हम भी ऐसा ही करेंगे।हमारा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और एकजुट इकाई के रूप में एक-दूसरे का समर्थन करने पर है।

हमारा मानना है कि अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करके और अपना संयम बनाए रखकर हम बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्विट्जरलैंड में माइक हॉर्न के बेस के लिए रवाना हुई, जहां वे तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से गुजरेंगे। इसके बाद, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम 20 जुलाई को पेरिस पहुंचने से पहले अभ्यास मैचों की एक श्रृंखला के लिए नीदरलैंड जाएगी।

पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत को पूल बी में रखा गया है जिसमें मौजूदा चैंपियन बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड शामिल हैं।

क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ने के लिए, टीम को अपने पूल में शीर्ष चार में जगह बनानी होगी। पूल ए में नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और मेजबान देश फ्रांस शामिल हैं, जो 12 टीमों के एक बेहद प्रतिस्पर्धी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के लिए मंच तैयार करता है।

दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, पीएलआई योजना से तीन वर्षों में 3,400 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली,11 जुलाई (एजेंसियां)। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और मेक इन इंडिया के दम पर देश दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पीएलआई योजना की मदद से देश में तीन वर्षों में दूरसंचार उपकरणों की विनिर्माण बिक्री 50,000 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कहा, यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस बिक्री में करीब 10,500 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। पीएलआई योजना की मदद से दूरसंचार क्षेत्र ने तीन वर्षों की इस अवधि में 3,400 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 17,800 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। सरकार ने कहा, आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना से देश में उत्पादन, रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि एवं निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

आयात और निर्यात के बीच घटा अंतर

पीएलआई योजना के अलावा सरकार के अन्य प्रयासों से दूरसंचार आयात और निर्यात के बीच अंतर काफी कम हो गया है। दूरसंचार उपकरण और मोबाइल दोनों को मिलाकर 2023-24 में 1.49 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात किया गया। इस अवधि में आयात 1.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

दूरसंचार व्यापार घाटे में आई गिरावट

पीएलआई योजना ने आयातित दूरसंचार उपकरणों पर भारत की निर्भरता को करीब 60 फीसदी तक कम कर दिया है। इससे देश कुछ उत्पादों में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय निर्माता अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को 5जी उपकरण निर्यात कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले पांच वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र (दूरसंचार उपकरण और मोबाइल) में व्यापार घाटा 68,000 करोड़ से कम होकर 4,000 करोड़ रुपये रह गया है।

मोबाइल फोन आयातक से निर्यातक बना भारत

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पीएलआई योजना की मदद से देश में मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात में काफी तेजी आई है। भारत अब मोबाइल फोन आयातक से निर्यातक बन गया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

इस्लामिक फर्ज में...

चोर रास्तों से लाकर मक्का-मदीना में अवैध तरीके से ठहराते हैं और हज की व्यवस्था करते हैं। चूंकि इनके पास परमिट नहीं होता, इसलिए हज यात्रियों को चोरी-छिपे, दुर्गम रास्तों से लाकर कष्टप्रद स्थितियों में रखा जाता है, जहां न पीने का पानी होता है और न ही अन्य सुविधाएं। अवैध तरीके से आने वाले इन हज यात्रियों को अभावों के बीच भीषण गर्मी में रहना पड़ता है, जिसे वे सहन नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं।

सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल-जलाजेल के अनुसार, इस वर्ष 18 लाख से अधिक हज यात्री पहुंचे। इसके अलावा अवैध तरीके से हज करने वालों की संख्या 4 लाख से अधिक थी। सऊदी सरकार को इसका अनुमान था, इसलिए उसने हज शुरू होने से पहले सारी सीमाएं सील कर रेगिस्तान से लेकर अन्य जगहों तक सेना की तैनाती की थी ताकि अवैध तरीके से हज के लिए आने वालों को रोका जा सके। इस चौकसी के कारण इस बार हजारों अवैध हज यात्री पकड़े गए। यही नहीं, गैर-कानूनी तरीके से आने वाले हज यात्रियों में भय पैदा करने के लिए सेना ने सड़कों पर मार्च भी किया। यहां तक कि मक्का की दोनों मस्जिदों के इमामों ने हज शुरू होने से पहले जुमे की नमाज के खुतबे में अवैध तरीके से हज करने को गैर-इस्लामिक बताते हुए कहा कि ऐसी हज कबूल नहीं होतीं। लेकिन ये तमाम उपाय नाकाफी साबित हुए। बहरहाल, सरकार ने बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत के मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। विदेशी मीडिया में मौतों पर लगातार खबरें प्रकाशित होती रहीं, पर सऊदी सरकार मृतकों के आंकड़े छिपाती रही।

अंततः हज समाप्त होने के कई दिन बाद उसने मृतकों का आंकड़ा जारी किया। सरकार ने सफाई दी कि उसने हीट वेव के मद्देनजर हज यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया था, लेकिन उन्होंने हिदायतों का उल्लंघन किया, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुईं। परोक्ष रूप से सरकार ने अव्यवस्था, सुरक्षा में चूक और गैर-कानूनी तरीके से आने वाले हज यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की कमी की बात भी कबूल की। अवैध हज को गैर-इस्लामी करार देने के बावजूद लोग सऊदी अरब जाने का जोखिम क्यों उठाते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स, एएफपी जैसे मीडिया प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट के अनुसार, अंडरवर्ल्ड का जाल विभिन्न देशों के अलावा सऊदी अरब तक फैला हुआ है। इसमें कई देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, निजी टूर ऑपरेटरों के अलावा स्थानीय लोग भी अवैध हज यात्रियों के आने-जाने, रहने-खाने की व्यवस्था करते हैं।शुरुआती जांच के बाद सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1,301 मौतों में से 83 प्रतिशत हज यात्रियों के पास परमिट नहीं थे। उन्हें धूप में लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा। इस वर्ष हज के मौसम में तापमान में वृद्धि एक बड़ी चुनौती थी। उनके लिए यह मौसम दर्दनाक रहा, जो बिना परमिट मक्का आए। उनके अवैध प्रवेश से कई जरूरी सुविधाएं कम पड़ गईं। बिना परमिट हज यात्रा कराने में टूर ऑपरेटर, तस्करों और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मरने वाले 1,301 लोगों में 98 हज यात्री भारतीय थे। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद बिना परमिट लोग कैसे इतनी बड़ी संख्या में मक्का पहुंच गए?

फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी का कहना है कि जब उसने सऊदी सरकार से 4 लाख अवैध हज यात्रियों के मक्का में प्रवेश के बारे में जानना चाहा तो अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अन्य में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल लगभग हर पांच में से एक हज यात्री अवैध तरीके से मक्का पहुंचा था। बिना परमिट वाले हज यात्रियों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी और उन्होंने भीषण गर्मी में बिना एसी वाली बसों में सफर किया। इस बार हज के दौरान तापमान 51 डिग्री से अधिक रहा। सेना की सख्ती के कारण उन्हें भीषण गर्मी में मीलों तक पैदल चलना पड़ा। वहीं, जिन हज यात्रियों के पास वैध परमिट थे, उन्हें सारी सुविधाएं मिलीं। हालांकि गर्मी के कारण स्वस्थ हज यात्री भी मूर्छित होकर गिर रहे थे। ऐसे कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें सड़क किनारे लाशें पड़ी हुई दिख रही थीं।

साल दर साल बढ़ते मौत के आंकड़े पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री सफाई देते हैं कि वार्षिक हज हो या उमराह, हज यात्रा पर आने वालों का मरना सामान्य बात है, क्योंकि वे गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं। हज में हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग आते हैं। उनमें कुछ को गर्मी, तनाव, बीमारी या असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे-जैसे अपराधियों का दखल बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष अकेले इंडोनेशिया के 774 हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी तरह वर्ष 2015 में भगदड़ से 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 1985 में मक्का के मजहबी स्थलों के आसपास 1,700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इनमें अधिकतर मौतें गर्मी के कारण हुई थीं। प्रश्न है कि सऊदी सरकार रोगियों को हज की अनुमति क्यों देती है? वैसे तो हज यात्रियों को तरह-तरह के टीके लगवा कर आने की हिदायत दी जाती हैं, पर गंभीर रोगियों को आने से रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? चलो, अनुमति दे भी दी तो उनकी देखभाल क्यों नहीं की जाती? हज यात्रियों से अरबों डॉलर वसूले जाते हैं, पर इस रकम को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च क्यों नहीं किया जाता?

द न्यूयॉर्क टाइम्स से एक साक्षात्कार में कुछ टूर ऑपरेटरों, हज यात्रियों और मृतकों के परिजनों ने सऊदी सरकार की व्यवस्था में खामियों का आसानी से लाभ उठाने की बात कबूल की है। उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार उन लोगों को वीजा के साथ हज यात्रा की अनुमति देती है, जिनके पास कोटा-परमिट हो। यह परमिट संबंधित देशों की सरकारें और वहां के कुछ निजी टूर ऑपरेटर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उन्हें सभी सुविधाएं मिलती हैं। मंदी झेल रहे मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बढ़ती आर्थिक हताशा के कारण गैर-पंजीकृत हज यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आधिकारिक रूप से प्रत्येक हज यात्री के लिए मूल देश को 5,000 से 10,000 डॉलर से अधिक का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति इस खर्च को वहन नहीं कर सकता, फिर भी चूंकि हज 5 इस्लामिक फर्जों से एक है, इसलिए गरीब हो या अमीर, हर मुसलमान हज यात्रा करना चाहता है।

मिस्र की एक 32 वर्षीया महिला मारवा ने, जिसके माता-पिता ने इस वर्ष बिना परमिट हज यात्रा की, बताया, उन्होंने यात्रा के लिए लगभग 2,000 डॉलर चुकाए, तब मिस्र के एक एजेंट और सऊदी अरब के एक दलाल ने उनकी हज यात्रा को सुगम बनाया। उन्हें लगा कि जल्द हज कर लेना चाहिए, क्योंकि मिस्र की मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। ऐसे में वे अगले वर्ष हज कर पाते या नहीं, इसमें संदेह था। मारवा के माता-पिता की तरह कई अन्य देशों के लोगों ने भी अवैध तरीके से हज करना बेहतर समझा।

अवैध तरीके से हज यात्रा कराने के धंधे में अंडरवर्ल्ड के खुलासे के बाद कई देशों में जांच शुरू हो गई है। अब उन रास्तों की भी खोज की जा रही है, जिसका सहारा बिना परमिट वाले हज यात्रियों को मक्का पहुंचाने के लिए लिया जाता है। इस वर्ष हज में ट्यूनीशिया के 50 से अधिक नागरिकों की मौत हुई। इसलिए राष्ट्रपति ने मजहबी मामलों के मंत्री को बर्खास्त कर दिया। वहीं, हज के दौरान 99 लोगों की मौत के बाद जॉर्डन ने भी जांच शुरू कर दी है। सरकार अवैध हज मार्गों का पता लगा रही हैं, जबकि मिस्र ने अपने यहां 16 टूर ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। काहिरा के एल-इमान टूर्स के सह-मालिक इमान अहमद मानते हैं कि इस अवैध व्यवसाय में बहुत लालच है। उन्होंने जब इस वर्ष गैर-पंजीकृत हज यात्रियों को भेजने से मना किया, तो मिस्र के अन्य टूर ऑपरेटरों ने सऊदी के दलालों की मदद से इस काम को अंजाम दिया।

अवैध तरीके से हज यात्रा करने वालों में मिस्र के शहर लक्सर की 55 वर्षीया सफा अल-तवाब भी थीं। उनके भाई अहमद अल-तवाब ने अपनी बहन को हज परमिट न मिलने पर मिस्र के एक टूर ऑपरेटर को 3,000 डॉलर देकर हज यात्रा करवाई। सफा को यह अहसास नहीं था कि ऐसा करके वह सऊदी अरब के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। सउदी अरब पहुंच कर उन्होंने रिश्तेदारों को बताया कि उन्हें ऐसी जगह रखा गया, जहां सुविधाओं का अभाव था। उन्हें बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, भीषण गर्मी में मीलों पैदल चलना पड़ा।

हज से कुछ सप्ताह पहले बिना परमिट मक्का आने वालों पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा हर वर्ष किया जाता है, फिर भी इस बार बड़ी संख्या में बिना परमिट वाले हज यात्री मक्का पहुंचने में सफल रहे। मक्का में छिपने के लिए उन्होंने तस्करों और दलालों की मदद ली और बदले में उन्हें पैसे दिए। अवैध तरीके से मक्का पहुंचे जॉर्डन के अब्दुल रहमान ने बताया कि मक्का जाने के लिए उसने कई तस्करों का सहारा लिया। उससे चट्टानी पहाड़ी मार्ग से शहर ले जाने के एवज में 200 डॉलर वसूले गए। उसे पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गईं। उसे घंटों प्रचंड गर्मी में पैदल चलना पड़ा। उसके साथ जो लोग थे, पुलिस ने कुछ समय के लिए उन सभी को हिरासत में ले लिया। फिर किसी ने पैरवी की तो सबके नाम लिखकर छोड़ दिया। 49 वर्षीय अब्दुल रहमान को बखूबी मालूम था कि वह गैर-कानूनी तरीके से हज यात्रा कर रहा है, लेकिन कम पैसे लग रहे थे तो उसने यह जोखिम उठाना बेहतर समझा।

बहरहाल, कड़े पहरे के बावजूद गैर-कानूनी तरीके से हज यात्रियों के मक्का पहुंचने का सिलसिला साल दर साल बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने दबी जुबान में ही सही, यह तो माना कि हज माफिया, जिसमें टूर ऑपरेटर, तस्कर और अंडरवर्ल्ड शामिल हैं, कम पैसे में बिना परमिट मुसलमानों को हज करा रहे हैं। साफ है कि वैध हज यात्रियों की आमद के कारण व्यवस्था चरमरा जाती है और हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं।

भारत को...

पीएम मोदी ने पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठक की, इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं।पीएम नरेंद्र मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ होने वाली बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर प्री-बजट बैठकों के खत्म होने के बाद हुई। वित्त मंत्री ने 19 जून से 05 जुलाई के बीच 10 स्टेकहोल्डर समूहों से जुड़े 120 से अधिक विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसमें किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार एवं कौशल, एमएसएमई, व्यापार एवं सेवाएं, उद्योग, अर्थशास्त्री, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार, साथ ही, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। लोकसभा चुनाव के बाद पेश किए जाने वाले इस बजट से आम जनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस साल झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटा की चिंता किए बगैर लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। नौकरी-पेशा से जुड़े लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है। देश के करोड़ों किसान भी इस बजट से आस लगाए हुए हैं।इस बजट में मोदी सरकार से टैक्स में और छूट की उम्मीद की जा रही है। इस बार सरकार बेसिक टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। बेसिक टैक्स छूट लिमिट वह सीमा है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आयकर नियम के अनुसार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। टैक्स छूट लिमिट बढ़ने से टैक्सपेयर्स को ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा।लगातार तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 18 जून 2024 को पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी की गई थी। अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी में है। इस बार देश के अन्नदाता उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में राशि में सरकार इजाफा कर सकती है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार पीएम किसान राशि की बढ़ाकर 6000 से 8000 कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो किसानों को साल में चार किस्तें मिलेंगी। अभी सरकार इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपए अन्नदाताओं के खाते में ट्रांसफर करती है। पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना को लॉन्च किया था।

टैक्सपेयर्स को एक प्रमुख उम्मीद है कि सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में वृद्धि करेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक खास धनराशि होती है जो एक वेतनभोगी कर्मचारी टैक्स का हिसाब लगाने से पहले अपनी सालाना सैलरी में से घटा सकता है। मौजूदा सीमा के तहत कर्मचारी वेतन के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी कर योग्य आय के विरुद्ध एक साल में 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी वह अपनी सालानी सैलरी में से 50,000 रुपए घटाकर अपने टैक्स का हिसाब लगा सकता है। यह कटौती प्राप्त वेतन पर लागू होती है।

मोदी सरकार इस बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या और बीमा राशि दोनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मोदी सरकार गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का तोहफा दे सकती है। अभी देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती है।

पूर्ण बजट 2024 में मोदी सरकार महिलाओं को तोहफा दे सकती है। रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर रही है। विवाहित महिलाओं के लिए टैक्स छूट में संयुक्त फाइलिंग विकल्प या विवाहित जोड़ों के लिए टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं। कामकाजी महिलाएं कार्य-संबंधी व्यय, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन या शिक्षा व्यय से संबंधित टैक्स कटौती के लिए पात्र हो सकती हैं। बच्चों वाली महिलाएं टैक्स क्रेडिट, कटौती या बच्चों के देखभाल सब्सिडी या शिक्षा बचत योजना जैसे लाभों के लिए पात्र हो सकती हैं।

मोदी सरकार का यह बजट ग्रामीणों पर फोकस रह सकता है। मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। केंद्र सरकार इस बार के बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ा सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकती है ताकि गांव में रहने वाले लोगों का रोजगार मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके।

प्राइवेट सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पेश होने वाले इस बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनुफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में भी नौकरियों के अवसर बनाए जा सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने पर होगा।

उद्योग जगत ने भी बजट को लेकर इस बार वित्त मंत्री के सामने मांगों की लम्बी चौड़ी सूची सौपी है। उद्योग संघ (फिक्की) के पूर्व अध्यक्ष और इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉएज़ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभ्रकान्त पांडा ने वित्त मंत्री के सामने बजट 2024-25 को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। पांडा ने कहा कि वित्त मंत्री का विशेष फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बजट आवंटन बढ़ाने और देश में स्टार्ट-अप कल्चर को मजबूत करने पर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेश हो रहे बजट को लेकर खास सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सचिवों और विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें कीं। बजट पर वित्त मंत्रालय की हुई नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, बैंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव (बजट) के अलावा केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल रहे। बैठकों के दौर के बाद बजट पर मिलने वाले योजनाओं और खर्चों के सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजे गए। जबकि टैक्स से जुड़े सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे गए। बजट निर्माण से लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ खास है, इसे इतना गोपनीय रखा जा रहा है कि संसद में बजट पेश होने तक इसकी भनक किसी को नहीं लगे।

केंद्र सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इच्छा है कि आम बजट के जरिए विकसित भारत का रोडमैप तैयार हो। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। आज की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के रोडमैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव लिए। केंद्र सरकार का ध्यान गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग पर सबसे ज्यादा है। सरकार की तरफ गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है।

इस बार बजट में सरकार मध्यमवर्गीय लोगों को राहत देने की घोषणा कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी पूर्व में इसे लेकर संकेत दे चुके हैं जब उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ाने के प्रयास की बात कही थी। चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री ने 70 की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए आयुष्मान योजना की घोषणा की थी। वह भी बजट का हिस्सा हो सकता है। युवाओं के अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने जैसे प्रावधान की भी घोषणा हो सकती है। ध्यान रहे कि अगले तीन चार महीनों में चार राज्यों में चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा की कोशिश होगी कि यहां जीत दर्ज की जाए। बजट के निर्माण की प्रक्रिया में इन बातों को निश्चित तौर पर ध्यान में रखा गया होगा। ऐसा आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है।

मोदी काल...

बजट 2016 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)

वर्ष 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि बीपीएल परिवारों को परिवार की महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसने मोदी सरकार की एक और सुपरहिट योजना का मार्ग प्रशस्त किया। उसी साल मई में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना के तहत, महिलाओं को अभी भी सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं।

बजट 2017 (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा)

वर्ष 2017 के बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की घोषणा हुई, जो देश की कुछ शीर्ष परीक्षाओं का आयोजन करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। शुरुआत में एनटीए सीबीएसई, सीमैट और जीपैट परीक्षा आयोजित करती थी। बाद में इसे नीट, जेईई और यूजीसी-नीट जैसी परीक्षाओं तक की जिम्मेदारी दी गई।

बजट 2018 (आयुष्मान भारत योजना)

बजट 2019 में अरुण जेटली ने 10 करोड़ परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना गया और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा कवरेज मिला।

बजट 2019 (पैन-आधार की इंटरचेंजेबिलिटी)

वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित पूर्ण बजट में कहा कि पैन और आधार का म्युचुअल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस साल से टैक्सपेयर अपने आधार नंबर का यूज करके भी अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं, यह नियम लागू हुआ।

बजट 2020 (नई टैक्स व्यवस्था)

2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था शुरू की थी। इसमें अलग-अलग आय वर्गों के लिए ज्यादा टैक्स स्लैब थे, लेकिन छूट कम थी। आम आदमी के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए नई टैक्स व्यवस्था शुरू की गई थी।

बजट 2021 (कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित)

कोविड-19 के भारत में आने और हजारों लोगों की जान लेने के बाद यह पहला बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिन्हें जल्द ही विकसित किया गया और करोड़ों भारतीयों पर मुफ्त में लगाया गया।

बजट 2022 (पीएम गति शक्ति पर ध्यान, क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स)

2022 के बजट में पीएम गति शक्ति योजना पर जोर दिया गया, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। नेशनल हाईवे के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया। धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी कैपिटल गेन्स पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई।

बजट 2023 (नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव)

2023 के बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए। इसके तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा।

अंतरिम बजट 2024 (वंदे भारत को बढ़ावा)

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40,000 सामान्य ट्रेन बोगियों को हाई-स्पीड वंदे भारत में बदला जाएगा।

यासीन मलिक...

उसके बाद अपहरणकर्ताओं को छोड़ा गया। रिहा किए अपहर्ताओं ने बाद में मुंबई बम ब्लास्ट को अंजाम दिया।25 मई 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मलिक को पांच अलग-अलग मामलों में 10-10 साल और तीन अलग-अलग मामलों में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 10 मई 2022 को यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल किया था। 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताफ अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। 1993 में अलगववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। हाफिज सईद ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। गृह मंत्रालय को यह सूचना मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।

कश्मीर में हिंसा की शुरुआत करने वाले और असंख्य निर्दोष हिंदुओं की हत्या कराने वाले सरगना के फांसी पर लटकने का पूरे देश को इंतजार है। यासीन मलिक के जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के आतंकियों ने 1989 में श्रीनगर में पूर्व जस्टिस नीलकंठ गंजू की गोली मार कर हत्या कर दी थी। जस्टिस नीलकंठ गंजू का कसूर यह था कि उन्होंने एक खूंखार आतंकवादी को मौत की सजा सुनाई थी। इस हत्या में जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक का हाथ था। 1990 में श्रीनगर में दूरदर्शन के निदेशक लस्सा कौल सहित पत्रकार शबान वकील की हत्या में भी यासीन शामिल था। ये हत्याएं कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने के लिए दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा थी। घाटी में कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग का सिलसिला 14 सितंबर 1989 में एडवोकेट टीकालाल टपलू की हत्या से शुरू हुआ था। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने आतंकी संगठन जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट को इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या में फांसी की सजा सुनाई थी। जेकेएलएफ ने मकबूल की रिहाई के लिए कई प्रदर्शन किए। 1984 में इन आतंकियों ने लंदन में भारतीय राजनयिक रवींद्र म्हात्रे की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मकबूल भट को 1984 में फांसी दी गई। जेकेएलएफ मकबूल बट की फांसी का बदला लेने की नीयत से नवंबर 1989 में श्रीनगर बाजार में रिटायर हो चुके जस्टिस नीलकंठ गंजू की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

यासीन मलिक ने ही रावलपोरा में अंधाधुंध गोलियां चला कर वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर समेत चार वायुसैनिकों की हत्या कर दी थी। इस फायरिंग में 22 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। यह खौफनाक घटना जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदातों के इतिहास का एक अहम अध्याय है। उसी साल यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया। वायुसैनिकों की हत्या के चश्मदीद वायुसैनिक राजवर उमेश्वर की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कांग्रेस सरकार ने फाइल दबा दी और यासीन मलिक को रिहा करते हुए आतंकियों के प्रति नरमी दिखाई। यासीन मलिक की सीधी पहुंच कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री तक थी।

वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने यासीन मलिक के संगठन जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया और मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने 25 मई 2022 को यासीन मलिक को आतंकवादी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वायुसैनिकों की हत्या के चश्मदीद गवाह राजवर उमेश्वर का बयान दर्ज हुआ। उमेश्वर ने भरी अदालत में यासीन मलिक की तरफ उंगली उठा कर उसे पहचाना और अदालत से कहा, यही यासीन मलिक वह हत्यारा है जिसने 25 जनवरी 1990 को दिनदहाड़े वायुसैनिकों पर गोलियां बरसाई थीं। वायुसैनिक स्टाफ पिकअप बस का इंतजार कर रहे थे। तभी यासीन मलिक ने अपने फेरण के नीचे से बंदूक निकाली और उन पर गोलियां चलाईं। उस अंधाधुंध गोलीबारी में चार वायुसैनिक शहीद हुए थे। उमेश्वर की जान बच गई थी।

हिंदुस्तान...

सांस्कृतिक समझ सामने रखी। संयुक्त प्रेस वार्ता में ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में मेरे लिए भारत के आकलन को जानना और उसे समझना काफी महत्वपूर्ण था। भारत को यूरोपीय चिंताओं और परेशानियों से परिचित कराना भी आवश्यक था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग-अलग छोर पर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। लोकतंत्र हम दोनों देशों को जोड़ता है। स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून शासन का आदर हमारी साझा मूल्य हैं। हम दोनों समाज बहु संवर्धित और बहुभाषी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं जबकि भारत में हमने अभी-अभी लोकतंत्र का पर्व आन बान शान के साथ मनाया है। आज भारत में चुनावों के बारे में सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ सप्ताह पहले ही संपन्न हुए चुनावों में 650 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया, यानी कि 65 ऑस्ट्रिया के बराबर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया होती है, लेकिन मतदान के परिणाम कुछ ही घंटों के अंदर स्पष्ट हो जाते हैं। यह हमारी चुनावी मशीनरी और हमारे लोकतंत्र की ताकत है। भारत में सैकड़ों राजनीतिक दलों के 8000 से अधिक उम्मीदवारों ने इन चुनावों में भाग लिया। इस स्तर का मुकाबला, इतना विविध मुकाबला, उसके बाद ही जनता ने अपना जनादेश दिया। 60 साल बाद किसी सरकार को भारत में लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और संस्कृति भी बहुत पुरानी और शानदार रही है। हमारा एक दूसरे से संपर्क भी ऐतिहासिक रहा है। इसका फायदा दोनों देशों को मिला है। यह फायदा संस्कृति के साथ-साथ व्यापार को लेकर भी हुआ है। मेरा हमेशा से मत रहा है कि दो देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों से नहीं बनते, रिश्तों को मजबूती देने में जन-भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इन रिश्तों के लिए आप सभी के रोल को अहम मानता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि करीब 200 साल पहले वियना विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। 1880 में इंडोलॉजी के लिए एक स्वतंत्र पीठ की स्थापना के साथ ही इसे और बढ़ावा मिला। आज मुझे कुछ प्रख्यात इंडोलॉजिस्ट से मिलने का मौका मिला, उनकी चर्चाओं से यह स्पष्ट था कि उन्हें भारत में बहुत रुचि थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। आज हम 5वें स्थान पर हैं और जल्द ही हम शीर्ष 3 में होंगे। मैंने अपने देश के लोगों से वादा किया था कि मैं भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाऊंगा। हम सिर्फ शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मिशन 2047 है। आज भारत कम कागज और कम नकदी वाली, लेकिन निर्बाध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज भारत सबसे बेहतरीन, सबसे उज्ज्वल, सबसे बड़े और सबसे ऊंचे मील के पत्थर के लिए काम कर रहा है। आज हम भारत को उद्योग 4.0 और हरित भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के...

नीतीश कुमार की कुछ प्रमुख मांगों की मंजूरी पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी के लिए तीन स्थानों पर चर्चा की गई। इनमें श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम शामिल हैं। लोगों ने बताया कि रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में किए जाने की संभावना है। स्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कम से कम दो महीने लगेंगे और बजट में स्थान की घोषणा नहीं की जा सकती है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ अपनी बैठकों के दौरान रिफाइनरी स्थापित करने के लिए जोर दिया था। नायडू के 16 सांसद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बहुत जरूरी समर्थन देते हैं। नायडू साफ-साफ कह चुके हैं कि राज्य का हित उनके लिए सर्वोपरि है। वे किसी भी कीमत पर प्रदेश की नाव को अस्थिर करने के लिए तैयार नहीं हैं। रिफाइनरी राज्य के विभाजन के समय की गई प्रतिबद्धता है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में शामिल है। अधिनियम की धारा 93 में कहा गया है कि केंद्र नियत तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तराधिकारी राज्यों की प्रगति और सतत विकास के लिए तेरहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी आवश्यक उपाय करेगा। तेरहवीं अनुसूची के बुनियादी ढांचे शीर्षक के तहत चौथा बिंदु कहता है, आईओसी या एचपीसीएल, नियत तिथि से छह महीने के भीतर, उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड कच्चे तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा और उस पर शीघ्र निर्णय लेगा।

बीपीसीएल और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस कदम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन नायडू ने इसे सार्वजनिक करते हुए कहा, देश के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित हमारे राज्य में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हमने आंध्र प्रदेश में 60-70,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की संभावना पर विचार किया। मैंने 90 दिनों में एक विस्तृत योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है। इस परियोजना के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए तत्पर है।इसके बाद अब बिहार की बारी है। बिहार नौ हवाई अड्डे, चार नई मेट्रो लाइन्स और सात नए मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पैसा मांगा है। 20 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए बिहार ने अलग से मांग रखी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कुमार काफी अर्से से कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को लेकर बजट में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं।

अब सिक्किम में ...

विधायक तेनजिंग नोरबू लाम्था से मिलकर खुशी हुई। वे अब आधिकारिक तौर पर हमारे एसकेएम परिवार में शामिल हो गए हैं।

10 साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब सिक्किम में विपक्षी दल को कोई विधायक नहीं है। बता दें कि दो जून को आए नतीजे में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती थीं। वर्तमान में विधानसभा में 32 में से 30 विधायक है। इनमें से सभी अब एसकेएम के सदस्य हैं। सोरेंग-चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री तमांग और नामची-सिंघीथांग सीट से उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी राय के इस्तीफे के बाद दो सीटें खाली हैं। दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए तमांग ने रेनॉक का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना है।

लाम्था की गिनती एसडीएफ के बड़े नेताओं में की जाती है। विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ एसकेएम नेता और शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा को उन्होंने 1,314 मतों से हराया था। 2 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही उनके एसकेएम में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि चुनाव के बाद जब लाम्था से पूछा गया कि क्या वह एसकेएम में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि वह अपना कोई भी फैसला जनता से पूछकर ही तय करेंगे।

हवस में नाकाम...

केरल के सिबी मैथ्यूज और गुजरात के आरबी श्रीकुमार व तीन अन्य रिटायर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।

सीबीआई ने बताया है कि केरल के पूर्व सीआईएस एस विजयन ने जासूसी का मामला गढ़ा था। उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के मालदीव की मूल निवासी मरियम रशीदा के खिलाफ वंचियूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था। पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज ने बिना किसी ठोस सबूत के गैरकानूनी तरीके से वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को गिरफ्तार किया था। एस विजयन, सिबी मैथ्यूज, केके जोशुआ, आरबी श्रीकुमार और पीएस जयप्रकाश ने झूठे दस्तावेज बनाने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इन पुलिस अधिकारियों ने वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया और यातनाएं दी।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि जब रशीदा की हिरासत अवधि समाप्त होने वाली थी, तब विजयन की तरफ से पेश की गई एक झूठी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें और हसन को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामले में फंसा दिया गया और उनकी हिरासत जासूसी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को सौंप दी गई। एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है, शुरुआती गलतियों को बरकरार रखने के लिए, पीड़ितों (नारायणन और अन्य समेत) के खिलाफ झूठी पूछताछ रिपोर्ट के साथ गंभीर प्रकृति का एक और मामला शुरू किया गया।

सीबीआई ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और सिबी मैथ्यूज, पूर्व एसपी एस विजयन और केके जोशुआ और पूर्व खुफिया अधिकारी पीएस जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। एजेंसी ने उन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिनमें धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 330 (स्वीकारोक्ति करवाने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 167 (लोक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करना), 193 (झूठी गवाही देना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं। हालांकि, सीबीआई ने मामले में केरल पुलिस और आईबी के तत्कालीन अधिकारियों समेत अन्य 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।

इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए नम्बी नारायणन ने बुधवार (10 जुलाई 2024) को कहा, एक व्यक्ति के तौर पर उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि चार्जशीट किए गए पूर्व पुलिस और आईबी अधिकारियों को दंडित किया गया या नहीं, क्योंकि मामले में उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। नारायणन ने पत्रकारों से कहा, उन्हें पहले ही दंडित किया जा चुका है। वे पहले से ही पीड़ित हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि उन्हें जेल जाना चाहिए। मुझे उनसे माफी की भी उम्मीद नहीं है। मुझे खुशी होती अगर वे सिर्फ इतना कहते कि उन्होंने गलती की है।

नम्बी नारायणन को फंसाने की साजिश से जुड़ा मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था। 15 अप्रैल, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसरो वैज्ञानिक नम्बी नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सीबीआई को दी जाए।

इस मामले में नम्बी नारायणन को 1996 में जाकर राहत मिली थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इसके बाद नम्बी नारायणन ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत सरकार ने मुआवजा भी दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार को भी उन्हें मुआवजा देना पड़ा। मोदी सरकार ने नम्बी नारायणन को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।

वहीं, एक्टर-डायरेक्टर आर माधवन ने नम्बी नारायणन की जिंदगी पर नम्बी-द रॉकेट इफेक्ट नाम की फिल्म भी बनाई थी, जिसके राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की करें उपासना

पीपल और तुलसी से जुड़े उपायों से होगी आर्थिक तंगी दूर

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। साथ ही सुख-समृद्धि एवं धन में वृद्धि के लिए उनके निमित्त लक्ष्मी वैभव व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्रती के धन-दौलत, सुख, ऐश्वर्य एवं यश-कीर्ति में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट भी दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी आर्थिक विषमता से निजात पाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन पूजा के समय पीपल और तुलसी से जुड़े ये उपाय जरूर करें।

सनातन शास्त्रों में निहित है कि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। अतः शुक्रवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा करें। अगर घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है, तो पूजा के समय पीपल वृक्ष के नाम का उच्चारण अवश्य करें।

अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है।

जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। अतः शुक्रवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद कच्चे दूध से तुलसी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है।

अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद कच्चे दूध में केसर मिलाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें। इस समय सुख, समृद्धि एवं धन में वृद्धि की कामना करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।

शुक्रवार के दिन पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही तुलसी की मंजरी लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है।

भाग्यशाली लोगों को दिखाई देते हैं ऐसे सपने...

माना जाता है कि व्यक्ति के कुछ सपने व्यक्ति को भविष्य के बारे में शुभ संकेत देते हैं, तो कुछ अशुभ संकेत भी दे सकते हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह का सपना जरूर आता है। हर सपने का अपना एक अर्थ माना गया है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में भी कुछ सपनों के बारे में बताया गया है, जो आने वाले समय में कुछ अच्छा होने की तरह इशारा करते हैं।

हो सकता है धन लाभ

हिंदू धर्म में सूर्य की भी अन्य देवी-देवता की तरह पूजा की जाती है। ऐसे में भविष्य पुराण में यह वर्णन मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में सूर्य देव का दर्शन होते हैं, तो यह काफी ज्यादा शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है।

यह सपना भी है शुभ

भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को सोने के गहने पहनते हुए देखता है, तो इससे भी भविष्य के बारे में शुभ संकेत मिलने लगते हैं। इस सपने का अर्थ है कि भविष्य में आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है या आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है।

जीवन में आती है सुख-समृद्धि

असलियत में बाल टूटने देखकर कोई भी व्यक्ति दुखी हो सकता है, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार, सपने में बाल टूटते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की समस्याओं का जल्द ही अंत होने वाला है। इसके साथ ही भविष्य पुराण के अनुसार, गाय का दूध निकालने का सपना देखना भी एक अच्छा संकेत माना गया है। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।

एकादशी व्रत से अक्षय फलों की प्राप्ति

सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 24 एकादशी मनाई जाती हैं जिनका अपना-अपना अलग महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधि-विधान से पूजा आराधना करने और व्रत करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन सच्चे भक्तिभाव से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में जानिए जुलाई के महीने में कौन-कौनसी एकादशी पड़ रही हैं और किस दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत।

देवशयनी एकादशी कब है ।

पंचांग के अनुसार, आसाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 मिनट पर होगा। उदयातिथि को देखते हुए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी और इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जुलाई को मनाई जाएगी। शाम 4:44।मिनट पर इसकी शुरुआत होगी और समापन अगले दिन 31 जुलाई को शाम 3:55 मिनट पर होगा। कुल मिलाकर 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। इसका पारण 1 अगस्त को होगा।

*** ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।।**

*** ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।**

ॐ भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

*** मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः। मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः।।**

गुरु प्रदोष व्रत 18 को

सिर्फ इतने मिनट ही हो सकती है भगवान शिव की पूजा, जानें सही समय और विशेष योग

वैसे तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है। कहते हैं प्रदोष का व्रत करने से जातकों के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं, ऐसे में जुलाई के महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ेगा वो और खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ये गुरु प्रदोष व्रत होने वाले हैं। दरअसल, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार गुरुवार को पड़ रही है, ऐसे में ये प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष कहा जा रहा है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त क्या है आइए हम आपको बताते हैं।

कब मनाया जाएगा गुरु प्रदोष व्रत

ज्योतिषों के अनुसार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार 18 जुलाई को रात 8:44 पर शुरू होगी, जो कि 19 जुलाई को शाम 7:41 पर खत्म होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 जुलाई को ही गुरु प्रदोष का व्रत किया जाएगा, क्योंकि इस बार प्रदोष का व्रत गुरुवार को मनाया जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जा रहा है।

गुरु प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए केवल 39 मिनट का समय ही शुभ है, आप रात को 8:44 से लेकर 9:23 तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं।

गुरु प्रदोष पर बना रहे ये खास योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 जुलाई को गुरु प्रदोष का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन ब्रह्म योग और ज्येष्ठ नक्षत्र है। ब्रह्म योग 19 जुलाई को सुबह 4:45 तक रहेगा और ज्येष्ठ नक्षत्र 18 जुलाई प्रातः काल से लेकर 19 जुलाई को देर रात 3:25 तक रहेगा। ऐसे में इस नक्षत्र में कोई भी शुभ काम करना बहुत फलदायी माना जाता है। गुरु प्रदोष के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो 19 जुलाई को सुबह 3:25 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा और रवि योग में स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है।

कैसे पड़ा भगवान विष्णु का नाम नारायण ?

सनातन धर्म में हर भगवान को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, भोले भंडारी जैसे कई नाम से बुलाया जाता है। इसी तरह से जगत के पालनहार भगवान विष्णु के भी कई नाम हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान के नाम का स्मरण कर लेने से ही भक्तों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु के नाम के बारे में और बताते हैं कि उन्हें उनके प्रिय नाम नारायण से क्यों बुलाया जाता है और इसका अर्थ क्या है।

इस तरह पड़ा भगवान विष्णु का नाम नारायण

पद्म पुराण के मुताबिक, कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीरसागर में निवास करते हैं और यही कारण है कि भक्त देवर्षि नारद उन्हें नारायण कहकर पुकारते हैं। जिसका अर्थ होता है जल जिसका प्रथम अयन हो। दरअसल, जल को संस्कृत में नीर कहा जाता है। अगर नारायण शब्द का संधि विच्छेद करें, तो यह नर और अयण से मिलकर बना है, नर यानी की जल, अयन मतलब स्थान, यानी कि जल ही जिसके रहने का स्थान हो, इसलिए भगवान विष्णु को नारायण कहा जाता हैं।

भगवान विष्णु के अन्य नाम और उनका अर्थ

विष्णु नाम का मतलब

सबसे पहले आपको पालनहार नारायण के प्रथम नाम विष्णु का अर्थ बताते हैं, जिसका अर्थ होता है जिनकी आंख कमल जैसी हो, उन्हें विष्णु कहा जाता है। इसके अलावा चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित होने के कारण भी भगवान श्री हरि को विष्णु नाम से बुलाया जाता हैं।

हरि नाम का मतलब

भगवान विष्णु को श्री हरि या हरि नाम से भी पुकारा जाता हैं, जिसका अर्थ होता है जो सभी के दुख और दर्द को हर लें। जगत पालनहार भगवान विष्णु पूरे संसार का संचालन करते हैं और जीव जंतु के दुख भी हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरी नाम से पुकारा जाता हैं।

अच्युत

भगवान विष्णु के अनेकों नाम में से एक नाम अच्युत भी है, जिसका मतलब होता है ऐसा दिव्य पुरुष जो अमर हो और जिसे कभी नष्ट न किया जा सकें।

पुरुषोत्तम

भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम नाम से भी पुकारा जाता हैं, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है ऐसा पुरुष जो सभी में सर्वश्रेष्ठ हो और यह तो हमारे जगत के पालनहार विष्णु भगवान ही हैं, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम नाम की उपाधि भी दी गई हैं।

इस समय करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ तो मिलेंगे अच्छे परिणाम

घर आएगी सुख-समृद्धि, मिलेगा संकट मोचन का आशीर्वाद

मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भक्त सच्चे भक्तिभाव से बजरंगबली की पूजा आराधना करते हैं और उनके लिए व्रत भी रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करते हैं उनके घर सुख-समृद्धि का वास होता है और बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा और उनके लिए व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त न सिर्फ हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं।

हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान जी की पूजा करने से बुद्धि, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा के साथ-साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है कई लोग संकट मोचन का आशीर्वाद पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन पूरे दिन में 2 ऐसा वक्त होता है जब हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है।

इस समय हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे शुभ

वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह 4 से 5 के बीच करेंगे तो यह सबसे शुभ समय होगा। इसके अलावा आप रात को सोने से कुछ समय पहले अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसके शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। रात में हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो आपको मिलती ही हैं, साथ ही आपकी सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है और सुख-समृद्धि का घर में वास होता है। अगर आप सही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे जीवन में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं।

मां त्रिपुर भैरवी को समर्पित है गुप्त नवरात्र का छठवां दिन

रहस्यमयी है देवी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा

इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का बहुत महत्व होता है। इस दौरान दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तंत्र साधना करने वालों के लिए यह अवधि खास होती है। गुप्त नवरात्र का छठा दिन मां त्रिपुर भैरवी को समर्पित माना जाता है। माता का यह स्वरूप अहंकार का नाश करता है। मां त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए, जानते हैं कि मां त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी।

मां त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा रंग पाने का विचार आया। जिसके बाद देवी अन्तर्धान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते, तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी।

महादेव के आदेश के अनुसार, नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी, महाकाली के छाया रूप से प्रकट हुईं। रुद्रामल तंत्र के अनुसार, सभी दस महाविद्याएं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार, छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी, महाकाली का ही रौद्र रूप हैं। इनके कई भेद हैं जैसे त्रिपुर भैरवी, चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, सम्पदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र और शतकुत आदि।

तंत्र शास्त्र के अनुसार

तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, मां त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों (भुर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक) में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। 'त्रिपुरा' का अर्थ है 'तीन लोक' और 'भैरवी' का अर्थ है 'भय को दूर करने वाली देवी'।

उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं।

फिल्में बनने के बाद ऐसे पहुंचती हैं सिनेमाघर?

इंडियन सिनेमा में अलग-अलग भाषाओं में हर साल तमाम फिल्में बनाई जाती हैं। इन फिल्मों को बनाने के लिए काफी समय और काफी लोग लगते हैं। काफी मेहनत और काफी पैसे खर्चे होने के बाद एक फिल्म को तैयार किया जाता है। जब फिल्म तैयार होकर सिनेमाघरों में पहुंचती है तो इनमें से कुछ बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करती हैं तो कुछ फ्लॉप साबित होती हैं। अब समझने वाली बात है कि फिल्म बनने के बाद बाद सिनेमाघरों की स्क्रीन तक कैसी पहुंचती हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में सवाल होता है कि फिल्म के फ्लॉप होने पर किसे नुकसान होता है और हिट होने पर किसे फायदा होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किसी फिल्म को बनाने के बाद सिनेमाघरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है और इसके साथ ये भी बताएंगे कि फिल्म के हिट या फ्लॉप होने पर किसे फायदा या नुकसान होता है।

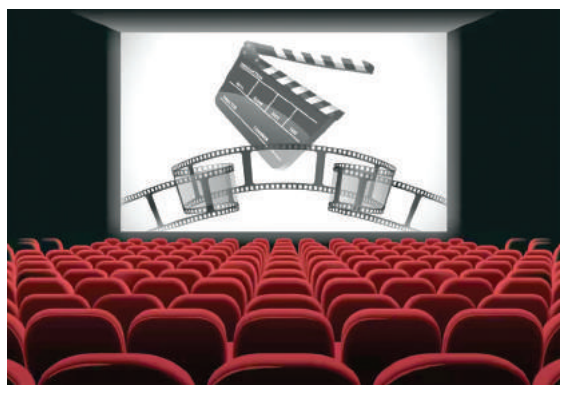

मेकर्स और सिनेमाघरों के बीच कड़ी का काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर

एक फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर और एक्टर से लेकर कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर तक सभी की जिम्मेदारी होती है। जब एक फिल्म बनकर तैयार होती है तो इसे सिनेमाघरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है। मेकर्स यानी प्रोड्यूसर फिल्म को बनाने में पैसा लगाते हैं और जब फिल्म बनकर तैयार हो जाती है तो वह डिस्ट्रीब्यूटर पास लेकर जाते हैं। इसके बाद फिल्म को सिनेमाघरों की स्क्रीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदने के बाद इसे राज्यों और फिल्म सर्किट में खुद बेचते हैं या फिर सब-डिस्ट्रीब्यूर को बेच देते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूर और सब डिस्ट्रीब्यूर का काम फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाना होता है। आसान भाषा में समझें तो मेकर्स और सिनेमाघरों के बीच डिस्ट्रीब्यूटर कड़ी का काम करते हैं। इस तरह से फिल्म बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से सिनेमाघरों तक पहुंचती है। बताते चलें कि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म को बनाने वाले प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन सहित कई मेकर्स अपनी फिल्म का बनने के बाद खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं।

फिल्म के हिट और फ्लॉप पर ऐसे तय होता है फायदा और नुकसान

अब बात आती है कि मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच फिल्म को लेकर किस तरह से सौदा होता है। एक तरीका है कि मेकर्स फिल्म में लगी लागत से ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। अब अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान और हिट होने पर फायदा होता है। इस तरह के सौदे में मेकर्स पुरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एक तरीका होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म के मुनाफे से कुछ कमीशन मिलता है और मेकर्स पर फिल्म के चलने या ना चलने का पूरा रिस्क होता है। एक तरीका होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक रकम तय करके मेकर्स को दे देते हैं, चाहें फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। अगर फिल्म हिट होती है तो मुनाफे का कुछ हिस्सा रॉयलटी के तौर पर मेकर्स को दिया जाता है। इस तरीके में फिल्म को लेकर होने वाला रिस्क मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर में बराबर होता है। बताते चलें कि डिस्ट्रीब्यूटर कई बार फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइल राइट बेचकर भी पैसा कमाते हैं।

मिर्जापुर 3 की सलोनी भाभी का किरदार निभाने वाली नेहा सरगम को मिला नेशनल क्रश का टैग

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुका है, जिसे फैन्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों को जहां मिर्जापुर 3 काफी पसंद आई है तो वहीं कई लोगों को इसकी कहानी दिलचस्प नहीं लगी। हालांकि इन सबके बीच जो किरदार चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है दद्दा त्यागी की बहू सलोनी त्यागी। यह एक्ट्रेस मिर्जापुर सीजन 2 में दद्दा के बड़े बेटे भरत त्यागी की पत्नी बनीं, अब सीजन 3 में वो अपनी भूमिका को प्रमुखता से निभा रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि अब वो भारत की नई क्रश बन गई हैं। आइए एक्ट्रेस के बारे में विस्तार से जानते हैं।मिर्जापुर सीजन 3 में सलोनी त्यागी के किरदार में नजर आ रही एक्ट्रेस का असली नाम नेहा सरगम है और वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। नेहा मूल रूप से बिहार के पटना की रहने वाली हैं। पटना में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी मां और छोटी बहन के साथ मुंबई चली गईं। वह हमेशा से एक सिंगर बनने की ख्वाहिश रखती थीं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की।नेहा ने इंडियन आइडल में भाग लिया और सीजन 4 में जगह बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतियोगिता के दौरान गले में संक्रमण के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नेहा साल 2012 में टीवी शो रामायण: सबके जीवन का आधार में नजर आईं, जिसमें उन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नील भट्ट और नेहा तीन साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि, आपसी मतभेदों के कारण दोनों को ब्रेकअप हो गया और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए।

ब्रेकअप की खबरों के बीच लंदन के कैफे में रोमांटिक हुए करण कुंद्रा

टीवी इंडस्ट्री में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा पावर कपल हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। तेजस्वी और करण अपनी क्यूट केमिस्ट्री से फैंस को खुश भी करते रहते हैं। उनकी हर एक फोटो इंटरनेट पर आग लगा देने का काम करती है, लेकिन फिर भी कपल के ब्रेकअप की खबर आग की तरह वायरल होती रहती है। तेजस्वी और करण के ब्रेकअप की खबरें आए दिन सामने आई हैं, जो फेक निकली। इसी बीच दोनों लंदन में वेकेशन एंन्जॉय कर रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इन दिनों लंदन में अपना वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं। कपल ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें दोनों काफी मस्तीभरे अंदाज में दिख रहे हैं।करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे के काफी क्लोज नजर आ रहे हैं, लेकिन करण ने अपना चेहरा ऊपर की ओर कर रखा है और तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड को निहार रही हैं।करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने लंदन में काफी मस्ती भी की।करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की ये फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में दोनों को अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश की ब्रेकअप की खबरें आए दिन वायरल होती रहती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों अलग हो चुके हैं। या फिर दोनों के बीच काफी दिक्कतें हैं। हालांकि, खबरें हमेशा फेक निकली हैं।करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को फैंस शादी करते हुए देखना चाहते हैं। करण कई बार शादी पर स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। तेजस्वी ने भी बताया था कि जब शादी होगी तब सबको बताया जाएगा।

चियान विक्रम की तंगलान का ट्रेलर रिलीज

चियान विक्रम के फैंस के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म थंगालान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टीजर और फर्स्ट-लुक पोस्टर के लॉन्च होने के लंबे इंतजार के बाद फिल्म के ट्रेलर ने काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। तंगलान एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो एक निडर आदिवासी नेता की स्टोरी बताती है जो कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपनी जमीन के लिए ब्रिटिशर्स ने लडऩे की हिम्मत करता है।ट्रेलर में अत्याचार, बहादुरी और विजय से भरे युग की झलक दिखाई गई है, जिसमें चियान विक्रम अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में चियान विक्रम के अलावा पार्वती थिरुवोथु, डैनियल कैल्टागिरोन, पसुपथी और मालविका मोहनन सहित कई टैलेंटेड कलाकार हैं जो फिल्म में खास रोल निभाते नजर आएंगे। पा रंजीत द्वारा निर्देशित, तंगलान निर्देशक और संगीतकार जीवी प्रकाश कुमार के बीच फिल्म के साउंडट्रैक पर पहला कोलेबोरेशन है। फिल्म का निर्माण स्टूडियो ग्रीन और जियो स्टूडियो द्वारा केई ज्ञानवेल राजा और ज्योति देशपांडे के बैनर तले किया गया है।शुरुआत में जनवरी 2024 में रिलीज होने वाली तंगलान को कई बार पोस्टपोन किया गया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म अब 15 अगस्त को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित पांच भाषाओं में सिनेमाघरों में आने वाली है। फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी भी बाकी है। लेकिन फैंस इस एपिक ड्रामा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पायल मलिक और कृतिका मलिक हैं लेस्बियन?

पहली बीवी बोलीं 'आपकी नजरों में...'

बिग बॉस ओटीटी 3 में इन दिनों जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस शो में फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दोनों बीवियों पायल और कृतिका के साथ एंट्री मारी थी। हालांकि दूसरे हफ्ते में ही पायल का पत्ता अनिल कपूर के शो से साफ हो गया। हालांकि बिग बॉस ओटीटी 3 में एंट्री लेते ही पायल मलिक, कृतिका और अरमान मलिक की काफी ट्रोलिंग हुई, इस दौरान लोगों ने अरमान की दो शादियों को गैरकानूनी बताया। वहीं कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि पायल और कृतिका लेस्बियन हैं और इसी वजह से ये दोनों एक साथ रह रही हैं। वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर पायल ने रिएक्ट किया है।

पायल मलिक ने लेस्बियन वाले कमेंट पर किया रिएक्ट

बता दें कि सौतन होने के बावजूद पायल मलिक और कृतिका मलिक के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हैं। यह दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। हाल ही में कृतिका पर कमेंट करने को लेकर पायल ने विशाल को खूब लताड़ा था। जिसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पायल और कृतिका लेस्बियन्स हैं। वहीं अब अपने एक व्लॉग में पायल मलिक ने इन रिपोर्ट्स पर रिएक्ट किया है। पायल मलिक ने लोगों को लताड़े हुए कहा, क्या घर में दो सगी बहनें होती हैं अगर उनमें इतना प्यार होता है, क्या आपकी नजरों में वो भी लेस्बियन हैं।

चार बच्चों और दो बीवियों के साथ रहते हैं अरमान मलिक

बता दें कि यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों पायल और कृतिका के साथ खुशी से रहते हैं। इन तीनों के चार बच्चे हैं। बताते चलें कि पायल से शादी के 8 साल बाद अरमान मलिक को उन्हीं की बेस्टफ्रेंड कृतिका से प्यार हो गया था। दोनों ने 7 दिनों के प्यार के बाद ही शादी रचा ली थी। इस बात से खफा पायल एक साल तक अपने बेटे के साथ अरमान से अलग रही थीं। इस बात का खुलासा खुद पायल ने बिग बॉस ओटीटी 3 के ग्रैंड प्रीमियर में किया था। वहीं रियलिटी शो से बाहर आने के बाद अब घर में अरमान मलिक और कृतिका बचे हैं, जिन्हें पायल मलिक जमकर सपोर्ट कर रही हैं।

फिल्म रायन का नया पोस्टर जारी

साल 2024 की शुरुआत में कैप्टन मिलर की सफलता के साथ धनुष ने धमाकेदार शुरुआत की। अब वह रायन के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म रिलीज से पहले निर्माताओं ने दर्शकों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। धनुष के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म के मुख्य किरदारों का दिलचस्प पोस्टर साझा किया गया है, जिसे देखकर प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। नए पोस्टर में धनुष के साथ कालिदास जयराम, संदीप किशन और दुशारा विजयन भी हैं, जो कैमरे की ओर देखते हुए एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर सितारे फिल्म में धनुष के भाई-बहन की भूमिका निभा रहे हैं। नए पोस्टर में उन सभी को एक बाल्टी पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि धनुष केंद्र में खड़े हैं। जानकारी हो कि रायन 26 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मुख्य कलाकारों के अलावा आगामी गैंगस्टर ड्रामा में प्रकाश राज, एसजे सूर्या, वरलक्ष्मी सरथकुमार और अपर्णा बालमुरली भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।अब तक रायन के लिए बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई अन्य बड़ी रिलीज नहीं है, जिसका अर्थ है कि धनुष स्टारर को 26 जुलाई, 2024 को एकल रिलीज मिल सकती है। हालांकि, अल्लू सिरीश की बडी भी उसी दिन बड़े स्क्रीन पर आ रही है इससे रयान के व्यवसाय पर असर पडऩे की बहुत कम संभावना है। इसके अलावा एक और बड़ी रिलीज थंगालान है, जिसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। 28 जुलाई को धनुष का जन्मदिन है। इसलिए भी फिल्म की रिलीज का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

आज का राशिफल

मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ

आप की नासमझी और बडो के प्रति गलत व्यवहार परिवारिक के माहौल को बिगाड़ सकता हैं . यह स्थिति आपको तनावग्रस्त कर सकती है. आज कार्य स्थल पर सहकर्मियों से टकराव होने का खतरा है. घरेलू मोर्चे से निपटने के लिए संयमित रहने की जरुरत हैं वित्तीय व्यवहार और निवेश के साथ अधिक सतर्क और सावधान रहें क्योंकि दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, कमाई घट सकती है और धन अवरुद्ध हो सकता है.कर्ज लेने से बचें। धार्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय करें।

वृषभ – इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो

आज काम बनता हुआ दिख रहा हैं रुका हुआ सोचा हुआ काम पूरा हो जायेगा , छात्रों के लिए समय अच्छा हैं इस समय मे किया हुआ कार्य उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी , आप की जान–पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा. कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे. आपको कोई महत्वपूर्ण काम मिल सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी. शिवलिंग पर केशर मिश्रित दूध चढाए ।

मिथुन – क,कि,कृ,घ,ड़,छ,के,को,ह

आप के रुके हुए काम मे परिवार का सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर सोच–समझकर बोलें. उन्नति के रास्ते खुलेंगे. बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं. घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं. अपनी सोच सकारात्मक रखें. विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है.आपकी भावनाओं का सम्मान होगा. दाम्पत्यजीवन सुखमय हैं स्वास्थ्य का देखभाल करें।

कर्क – ही,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो

आज सुबह कुछ ऐसा वाद विवाद होगा जिससे पारिवारिक सदस्यो का मन विचलित हो सकता है. आप को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी. व्यापार–व्यवसाय में वृद्धि के योग हैं. उत्साह बना रहेगा. काम में मन लगेगा. नया काम मिलेगा. प्यार के लिए समय बेहतरीन है. नई जगह निवेश करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं. आज प्रेमी और जीवनसाथी ही आपकी बड़ी ताकत होगा. छोटे बालक को दूध की सेवा करें।

सिंह – म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

आप का भाग्य प्रबल हैं आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे. आप एक नई साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं. अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं. वित्तीय मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे. प्रतिद्वंद्वी गतिविधि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक पर जा सकते हैं मानसिक शांति के लिए आप को परिवार के साथ धर्म युक्त यात्रा करनी होगी ।

कन्या – टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो

समय आज अनुकूल हैं आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. छात्रो का शिक्षकों के साथ करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे संतान पक्ष की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी. अपने कार्यों में संतान से पूरी मदद मिलेगी. आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे. किसी खास व्यक्ति से कामकाज के मामले में आपको कुछ नए आइडिया मिल सकते हैं. शाम को बच्चों के साथ पार्क में घूमने जायेंगे गाय को गेहूँ का भूसा खिलाए ।

तुला – र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

शिवलिंग पर दूध चढाए एवं पंचाक्षर मंत्र का जप आप को कर्ज से छुटकारा मिल सकता है. अपने काम पर पूरी नजरे रखें. अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. आज आपके लिए योजना बनाना मेहनत करने से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. आपके लिए परिवार, जमीन–जायदाद के मामले, दोस्त और रिश्तेदार बहुत खास हो सकते हैं। कुछ नया और सकारात्मक काम आप को मान प्रतिष्ठा देगा।

वृश्चिक – तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज खर्च ज्यादा होगा घरेलू जिम्मेदारियों में धन खर्च होने की संभावना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा जिससे मन प्रसन्न होगा. आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पुराने मित्रों के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.यात्रा पर दही का प्राशन करके ही निकले।

धनु – ये,यो,भ,भी,भू,धा,फा,ढा,भे

आय का स्रोत बढेगा आर्थिक रूप से यह बहुत अच्छी अवधि है. व्यापारी वर्ग वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाएंगे. सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त करने के शुभ संकेत हैं. आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा. परिवार में शादी या बच्चे का जन्म हो सकता है. प्रेम सम्बन्ध मजबूत होंगे. छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे. शारीरीक कष्ट बनेगा ।

मकर – भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा सीनियर भी काम का अधिक प्रेशर देंगे पारिवारिक मामलों में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी. ऑफिस में काम धीमी गति से पूरे हो सकते हैं, इससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है. आज किसी से भी बेवजह मजाक करने से आपको बचना चाहिए. आप नए काम पर सोच–विचार कर सकते हैं. आप किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं. सेहत ठीक बनी रहेगी. आपके काम में स्थिरता बनी रहेगी.बस हनुमानजी को सिन्दूर तेल चढाए।

कुम्भ – गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

आज समय नक्षत्र आप के लिए अनुकूल हैं बिजनेस में आत्मनिर्भरता रहेगी. नए लोगों से मुलाकात होगी कामकाज बढ़ेगा. साथ के लोगों से सहयोग मिल सकता है. नए लोगों से भी अच्छे संबंध बनेंगे. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा. आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार लाने में सफल रहेंगे. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे. मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं.भोजन पर नियंत्रण रखें।

मीन – दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची

आप को परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण स्वैया अपनाना पडेगा परिवार के साथ रुखा व्यवहार करने से परेशानी मे आ सकते हैं . यह पारिवारिक शान्ति को भंग कर सकता है.किसी बड़ी समस्या से सामना हो सकता है. दूसरों के बहकावे में न आएं. आय में निश्चितता रहेगी. अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें. निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें. शिक्षा–प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी , शिव मंत्र का जप करें ईष्ट का स्मरण करें।

शुक्रवार का पंचांग

दिनांक : 12 जुलाई 2024 , शुक्रवार
विक्रम संवत : 2081
मास : आषाढ़ , शुक्ल पक्ष
तिथि : षष्ठी दोपहर 12:35 तक
नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी सायं 04:09 तक
योग : परिघ रात्रि 05:14 तक
करण : तैतिल दोपहर 12:35 तक
चन्द्रराशि : कन्या
सूर्योदय : 05:49 , सूर्यास्त 06:54 (हैदराबाद)
सूर्योदय : 06:00 , सूर्यास्त 06:50 (बैंगलोर)
सूर्योदय : 05:51 , सूर्यास्त 06:44 (तिरुपति)
सूर्योदय : 05:42 , सूर्यास्त 06:44 (विजयवाडा)

शुभ चौघड़िया

चंचल : 06:00 से 07:30
लाभ : 07:30 से 09:00
अमृत : 09:00 से 10:30
शुभ : 12:00 से 01:30
राहुकाल : प्रातः 10:30 से 12:00
दिशाशूल : पश्चिम दिशा
उपाय : दूध पीकर यात्रा करें
दिन विशेष : गुप्त नवरात्र सप्तम कालरात्रि पूजन

* पाण्डित्य विषय में सम्पर्क करें *
पं.चिदम्बर मिश्र (टिल्लू महाराज)
हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा एवं मूल पारायण, वास्तुशान्ति, गृहप्रवेश,शतचंडी, विवाह, कुंडली मिलान, नवग्रह शान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं
फक्कड़ का मन्दिर, रिकाबगंज, हैदराबाद, (तेलंगाना)
9246159232, 9866165126
chidamber011@gmail.com

करौली एसपी बृजेश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा

अपराध नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता

करौली,11 जुलाई (एजेंसियां)। करौली एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने अपराध नियंत्रण को लेकर कार्यालय सभागार में जिला के पुलिस उपाधीक्षक, थानाधिकारियों समेत अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसपी अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी ने जिले थानाधिकारियों और डीएसपी को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता है। इसमें कोई कोताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसपी बृजेश ज्योति ने पिछले महीने घटित अपराधों की थानावार समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने और उचित विश्–लेषण एवं क्रियान्वयन से संगठित अपराधों जैसे अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, अवैध शराब की तस्करी, अवैध खनन, पेशेवर अपराधियों व माफियाओं पर नकेल कसने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जुलाई माह में खेती की बुवाई होने के कारण भूमि विवादों में बढ़ोतरी होती है। जमीन संबंधी विवादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। साइबर अपराधों करने वाले ठगों के जाल को तोड़ने के लिए जिले की साइबर टीम, सोशल मीडिया टीम और थानाधिकारियों ने मिलकर कार्य योजना तैयार की है।अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों, महिला एवं बच्चों संबंधी अपराधों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में जारी किए निर्देश। एसपी ने बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा कार्य करने वाले जांबाज पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

शेखावाटी की वीरांगनाओं का होगा सम्मान

झुंझुनू,11 जुलाई (एजेंसियां)। झुंझुनू जिला वीर सैनिकों के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जिसे लेकर अब डॉ. सलाउद्दीन फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल शुरू की है, जिसके तहत जिले के वीर जवानों और शहीदों की वीरांगनाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे।

डॉ. सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन के डायरेक्टर और राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विजय दिवस के दिन शेखावाटी के सबसे बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम वीर जवानों और शहीदों की वीरांगनाओं का स्वागत और सम्मान करेंगे।शेखावाटी अपने वीर जवानों के नाम से जाना जाता है।

झुंझुनू जिला अपने वीर जवानों के शौर्य और उनकी शहादत की गवाही देता है। सम्मान समारोह में जिले के तमाम जवान और शहीदों की वीरांगनाएं शामिल होंगी।

स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने जयपुर एयरपोर्ट पर एएसआई को मारा थप्पड़

बिना जांच के अंदर जाना चाहती थी

जयपुर,11 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के एसआई को थप्पड़ मार दिया। महिला क्रू मेंबर के बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था। कुछ देर हुई बहस के बाद महिला ने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। इसे लेकर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी सुबह चार बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। उसने बिना सिक्योरिटी जांच के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एएसआई गिरिराज प्रसाद ने उसे रोक दिया और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। इस पर अनुराधा ने महिला स्टाफ नहीं होने की बात कहकर स्क्रीनिंग कराने से मना कर दिया। इसके बाद एएसआई गिरिराज ने एयरपोर्ट कंट्रोल के अधिकारियों को वायरलेस पर सूचना देकर महिला स्टाफ भेजने के लिए कहा। इस पर अनुराधा नाराज हो गई और एएसआई से बहस करने लगी। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि अनुराधा ने एए–सआई गिरिराज को थप्पड़ मार दिया। इससे एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर हंगामा हो गया। सीआईएसएफ के अधिकारी और अन्य भी मौके पर पहुंच गए। एएसआई गिरिराज प्रसाद ने आरोपी स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बदला लेने के लिए की गई थी पति–पत्नी की हत्या

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

सिरोही,11 जुलाई (एजेंसियां)। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के पिपलियाबेरा में नौ दिन पहले हुई पति–पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए एक आरोपी भूराराम के खिलाफ मृतका ने 2 साल पहले एक केस दर्ज करवाया था। जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने अपने साथी उदाराम को 15 हजार रुपये का लालच और दोस्ती का वास्ता देकर अपने साथ शामिल किया था।

सिरोही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि 2 जुलाई की रात में पुलिस थाना पिंडवाड़ा क्षेत्र के पिपलीयाबेरा में जिला उदयपुर निवासी कालू पुत्र सामोरा गरासिया और उसकी पत्नी कोनी उर्फ कानकी की अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। मामले की मृतका के भाई सोवनाराम पुत्र भुराजी गरासिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर जिला सिरोही निवासी भूराराम पुत्र धन्नाजी गरासिया और उदाराम पुत्र सामीराराम गमेती भील को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतका कोनी ने 2 साल पहले भूराराम गरासिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इससे आरोपी करीब 7 जेल में रहा था। उसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी भूराराम ने अपने साथी उदाराम को जगह भी दिखाई थी। भूराराम ने पति–पत्नी दोनों की हत्या करने के लिए उदाराम को 15 हजार रुपए का लालच और दोस्ती का वास्ता दिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने 2 जुलाई की रात खेत पर सो रहे पति–पत्नी की लाठी से वार कर और धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

करौली में घायल मिले लेपर्ड की मौत

वन विभाग की टीम ने कराया पीएम

करौली,11 जुलाई (एजेंसियां)। करौली जिला मुख्यालय के समीप कल्ला पुरा छाबर वन क्षेत्र में घायल मिले लेपर्ड की मौत हो गई। वन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासनिक–अधिकारियों की मौजूदगी में करौली पशु चिकित्सालय में लेपर्ड का पोस्टमार्टम कराया है। वन विभाग के अनुसार टीम जब घायल लेपर्ड को रेस्क्यू करने पहुंची, उस दौरान उसकी मौत हो गई। आशंका है कि किसी दुर्घटना के चलते लेपर्ड की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।

करौली उप वन संरक्षक सुमित बंसल ने बताया कि कल्ला पुरा छाबर गांव के पास एक लेपर्ड के घायल अवस्था में पहुंचने की सूचना मिली थी। सूचना पर वन विभाग की टीम क्षेत्र में पहुंची और घायल लेपर्ड की जांच के बाद जब उसे रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान ही लेपर्ड ने दम तोड़ दिया। संभवतया दो–तीन दिन पूर्व लेपर्ड किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में घिसटते हुए ही लेपर्ड क्षेत्र में पहुंचा था। क्षेत्र में लेपर्ड के पहुंचने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लेपर्ड की मौत के बाद उसके शव को करौली पशु चिकित्सालय लाया गया। जहां मेडिकल टीम द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है।

ट्रैवल्स बस पर बदमाशों का हमला

सिरोही,11 जुलाई (एजेंसियां)। आबूरोड सदर पुलिस थानांतर्गत सरूपगंज–अहमदाबाद फोरलेन पर ओर गांव के समीप बीती रात बदमाशों ने ट्रैवल्स बस में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 से 5 बदमाश दो बाइक पर सवार होकर आए। बदमाश बस सवार यात्रियों से मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बस में सवार यात्रियों से जानकारी प्राप्त की।

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद, गुजरात से जोधपुर जा रही ट्रैवल्स की बस में बुधवार देर रात करीब 11 बजे ओर गांव के समीप अचानक खराबी हो गई थी। चालक ने हाईवे के पास साइड में खाली जगह देखकर बस को खड़ा किया था। इस दौरान दो बाइक पर सवार होकर 4 से 5 की संख्या में बदमाश वहां आए। उन्होंने आते ही वहां खड़े यात्रियों से लूटपाट करना शुरू कर दिया। वे लोग 3 से 4 यात्रियों के मोबाइल फोन और नकदी लूटकर भाग खड़े हुए। इस घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

क्षेत्र में लगातार हो रही लूटपाट की घटनाओं के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर खूब खरी खोटी सुनाई। इस मामले में आबूरोड सदर पुलिस थानाधिकारी राजीव भादू का कहना है कि इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच करते हुए बदमाशों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने भांजे को पकड़ा, घर से 5 पिस्टल बरामद, मामा फरार

करनाल,11 जुलाई (एजेंसियां)। करनाल पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी और उसका मामा अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। दोनों मामा–भांजा मध्य प्रदेश से हथियार लेकर आए थे। डीएसपी बीर सिंह ने मामले का खुलासा किया। फिलहाल मामा फरार है। डीएसपी के अनुसार करनाल के कोट मोहल्ला निवासी आरोपी मनोज के घर से सीआईए की टीम ने 5 अवैध देसी पिस्टल व सात कारतूस बरामद की है। जो अपने मामा के साथ मध्यप्रदेश से लेकर आया था। मामा पानीपत का रहने वाला है। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हिंदुओं को आतंकी कहने वाले उनके पास क्यों ऐसी–तैसी कराते हैं :महिपाल

बहादुरगढ़,11 जुलाई (एजेंसियां)। तीसरी बार हरियाणा की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ मैदान में आ गई है। नए प्रभारी सतीश पूनिया ने कमान संभालते हुए सभी जिलों में विस्तारित बैठकें शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 50 प्रतिशत सीटें गंवाने के बाद भाजपा नेताओं के सुर भी बदले और बिगड़े हुए हैं। पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला।

महिपाल ढांडा वीरवार को बहादुरगढ़ के गलेक्सी रिजॉर्ट में भाजपा की विस्तारित जिला बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान ढांडा ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं को आतंकी कहते हैं तो उन हिंदुओं के पास क्या अपनी ऐसी–तैसी कराने जाते हो। क्यों जाते हो उनके पास वोट मांगने। ढांडा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने में लगी है। कांग्रेस तो कह चुकी है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है तो फिर बाकी हिंदुस्तानी कहां जाएंगे।

महिपाल ढांडा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि 10 साल में हरियाणा के गांव देहात में बहुत काम हुए हैं और जो काम रह गए हैं वह इन दो महीनों में करवा दिए जाएंगे।अब कोई सरपंच नाराज नहीं है। कांग्रेस के हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पर महिपाल ने कहा कि सपने लेने का हक सभी को है, लेने दो सपने, लेकिन काठ की हांडी बार–बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर वोट ले लिए, लेकिन उसी कांग्रेस ने कर्नाटक में एससी और बीसी का आरक्षण काट कर मुसलमानों को देने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी।

राज्यसभा चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या बल : मोहनलाल बडौली

करनाल,11 जुलाई (एजेंसियां)। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली करनाल में भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे। जहां उनका जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा शीघ्र ही मंडल प्रवास योजना शुरू की जाएगी। जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ गरीबों तक पहुंचाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता एक सेवक की भांति काम करता है। आने वाले समय में हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत है, सभी जनता के पास जाएंगे। लेकिन जनता को जिसकी नीतियां अच्छी लगेगी जनता उसे ही आशीर्वाद देगी।

भाजपा ने पिछले साढ़े नौ सालों में जनता की सेवा की है और गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। भाजपा में पहले जानकारी नहीं होती कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसका निर्णय हाई कमान करता है। नीट परीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। भाजपा सरकार ने सर्वाधिक युवाओं को रोजगार दिया है। जहां तक महंगाई की बात है तो उस पर नियंत्रण के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

शुभ लाभ DAILY
खबरें जो सोच बदल दे
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

श्रावणी मेले के लिए सरकार ने 15 लाख राशि का किया आवंटन

मंत्री दिलीप जायसवाल ने मधेपुरा में की घोषणा

मधेपुरा (एजेंसियां)।

सिंहेश्वर स्थान में श्रावणी मेला के लिए 15 लाख और बाबा विशु राउत धाम चौसा के लिए 4.50 लाख रुपए राशि का आवंटन किया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में 14 जगहों पर लगाए जाने वाले श्रावणी मेले की सूची जारी की थी। जिसमें सिंहेश्वर धाम का नाम नहीं रहने से स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में नाराजगी थी। इसको लेकर डीएम ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सिंहेश्वर स्थान को श्रावणी मेले की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी सरकार से इसकी मांग की थी।

गुरुवार की सुबह राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल सिंहेश्वर स्थान पहुंचे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के बाद राशि के आवंटन की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड अलग होने के बाद सिंहेश्वर धाम मंदिर का अपना अलग महत्व है। बिहार के लिए सिंहेश्वर धाम मंदिर दूसरा बैद्यनाथ धाम मंदिर माना जाता है। राजस्व विभाग द्वारा श्रावणी मेले को लेकर बिहार के कुछ बाबा के धाम के लिए स्पेशल पैकेज का घोषणा किया था, जो कि सरकार की सूची में दर्ज है। इसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इसमें सिंहेश्वर स्थान का नाम नहीं है।

जानकारी मिलने पर उन्होंने बुधवार को पटना में स्पेशल बैठक बुलाकर बाबा सिंहेश्वर धाम और विशु राउत धाम चौसा को राजकीय मेला की सूची में जोड़कर कुल 19.5 लाख रुपए का आवंटन किया है। वहीं सिंहेश्वर स्थान में अतिक्रमण को लेकर मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल एक्शन में दिखे। मौजूद अधिकारियों को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सिंहेश्वर स्थान से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए और इसके बीच में जो भी बाधक हो उन एफआईआर दर्ज करवाएं।

डायन का आरोप लगाकर मां-बेटी को बेरहमी से पीटा

न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ितों के परिजन

पटना (एजेंसियां)।

पटना के एक गांव में डायन का आरोप लगाकर मां बेटी के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में गौरीचक थाना की प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष चिंकी कुमारी ने बताया कि लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित परिवार के युवक रवीश कुमार ने बताया कि उनके घर गौरीचक थाना के कंसारी गांव में पड़ता है। मंगलवार की देर शाम

जब वह घर में नहीं थे तो गांव कहीं कुछ लोगों द्वारा उनकी मां एवं बहन को डायन का आरोप लगाकर घर में घुस आए और जमकर मारपीट की। इस क्रम में गांव के लोगों द्वारा मंगलसूत्र और कान की बाली भी छीन लिया गया।

घायल अवस्था में उन्होंने दोनों को इलाज के लिए संपतचक के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घटना के बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत गौरीचक थाना को दी है।

रवीश कुमार ने बताया कि घटना के 24 घंटा गुजर जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर गौरीचक की प्रशिक्षु डीएसपी चिंकी कुमारी ने बताया कि घटना में किन-किन लोगों की संलिप्तता है। इसकी छानबीन की जा रही है। इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है।

सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल

न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी

मुजफ्फरपुर (एजेंसियां)।

नगर थाना की पुलिस ने कचहरी परिसर में शराब की खेप पहुंचाने आए सकरा के रामनगर निवासी धंधेबाज पप्पू कुमार को एक बैग शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में शराब बेचने वाले मनीष कुमार नामक धंधेबाज का मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिला है।

पुलिस ने गिरफ्तार पप्पू कुमार को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि दारोगा सत्येंद्र कुमार के आवेदन के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि वहां सिपाही इंद्रजीत ने आरोपित पप्पू कुमार को एक बैग शराब के साथ पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे मिठनपुरा में शराब से भरे इस बैग को रंजीत कुमार ने दी थी। उसने एक मोबाइल नंबर देते हुए कहा था कि इस पर कॉल करने पर मनीष नामक व्यक्ति आयेगा, जिसे यह बैग देना है।

सीएम नीतीश कुमार का आदेश

जदयू में आए आईएएस मनीष वर्मा बने राष्ट्रीय महासचिव

पटना (एजेंसियां)।

आरसीपी सिंह के जाने के बाद अगले नौकरशाह में रूप में आईएएस मनीष वर्मा को जनता दल यूनाईटेड में एंट्री के 48 घंटे के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए राज्यसभा सांसद संजय झा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर मनीष वर्मा को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जदयू महासचिव और विधायक आफाक अहमद खान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की।

ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके मनीष वर्मा ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृति

ली थी। शुरू में वह ओडिशा के जिलों में डीएम रहे थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के मूल निवासी मनीष वर्मा 2012 में अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति के तहत अपने राज्य लौट आए थे। इसके बाद से वह लगातार बिहार में ही सेवा दे रहे थे। वह पटना और पूर्णिया के जिलाधिकारी भी रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की जो जाति है, वही मनीष वर्मा की भी जाति है- कुर्मी। अफसरशाह के रूप में भी मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास ही रहे थे। नीतीश कुमार खुद कुछ कार्यक्रमों के इनके घर पर भी जा चुके थे। इस कारण जदयू में लोग उन्हें पहले से सीएम के करीबी के रूप में जानते रहे हैं।

जब मनीष वर्मा की प्रतिनियुक्ति दिल्ली हो गई तो वह वीआरएस लेकर बिहार आ गए। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें दूसरे तरीके से पद और शक्तियां दीं। इसके बाद धीरे-धीरे मनीष वर्मा ने जदयू के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन किया। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जदयू के अच्छे प्रदर्शन के पीछे मनीष वर्मा की अहम भूमिका थी। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते समय मनीष वर्मा के लिए इस तरह की अफवाह उड़ी थी, लेकिन अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। मनीष वर्मा ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और गुरुवार को उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी से नवाजा गया है।

तेज रफ्तार वाहन ने लील ली उप प्रमुख के भाई की जिंदगी

दर्दनाक मौत के बाद छाया मातम

बेगूसराय (एजेंसियां)।

बेगूसराय में तेज रफ्तार का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उप प्रमुख के भाई को कुचल दिया। इस हादसे में उप प्रमुख के भाई की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौत की खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एनएच 31 के पास की है। मृतक उप प्रमुख भाई की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले धीरज कुमार यादव के रूप में की गई है।

परिजनों बताया है कि अपने रिश्तेदार के शादी समारोह के बारात में शामिल होने के लिए राजापुर डुमरी गांव से खगड़िया जा रहा था। तभी शाहपुर कमाल के पास तेज रफ्तार अज्ञात बहन ने मोटरसाइकिल में जोरदार धक्का मार दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि इस हादसे में धीरज कुमार यादव की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस समय रोशनी थी उसे समय अगर समय रहते हुए पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे इलाज करने के लिए ले जाते तो उसकी जान बच सकती थी। वहीं मौत की खबर लगते ही शादी की खुशी गम में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना साहेबपुर कमाल थाना पुलिस को दी। मौके पर साहेब-पुर कमाल थाने की पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है।

भाभी का इलाज करवाकर बाइक से लौट रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, देवर की मौत

पटना (एजेंसियां)।

खगड़िया में सड़क हादसा में एक युवक की जान चली गई है। इस घटना में उसके पिता और उसकी भाभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनका इलाज चल रह है। घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित करना गांव निवासी सिकंदर सिंह के 22 वर्षीय पुत्र गुलशन कुमार के रूप में हुई है। जो अपने पिता और

भाभी के साथ खगड़िया में डॉक्टर के पास आया हुआ था। जहां से वह वापस घर की ओर लौट रहा था।

गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में अपनी जान गवाने वाला युवक अपने पिता के साथ अपनी भाभी को डॉक्टर से दिखने खगड़िया आया हुआ था। भाभी को दिखाने के बाद वह अपने घर करना के लिए लौट रहा था। लेकिन, इसी दौरान एनएच 31 मानसी थाना क्षेत्र स्थित सड़क पर एक बेलगाम ट्रक ने उसकी बाइक को पीछे से ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

यहां खुद नदी करती है बाबा का जलाभिषेक

कटाव के बीच खड़ा है मुजफ्फरपुर का अनोखा बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर

मुजफ्फरपुर (एजेंसियां)।

भगवान भोलेनाथ का प्रिय सावन मास में उनके मंदिर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर का जलाभिषेक स्वयं बागमती नदी करती हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष से सावन में हर वर्ष पानी काफी आता है।पूरे महीने मंदिर के गर्भ गृह तक जाता रहता है। वहीं नदी के पानी से मंदिर के भवन को

कोई क्षति नहीं होता।

मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड क्षेत्र के धनौर गांव के बागमती तट पर बाबा धनेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। जहां पर सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं होती है। इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह नदी बागमती के किनारे में होने के कारण इस मंदिर में मौजूद यहां पर के शिवलिंग बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने पर 3 से 4 महीना तक पानी में डूबी रहती है।

भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक 24 घंटे होता रहता है और यह जलाभिषेक कोई शिवभक्त नहीं बल्कि उफनाती हुई दो नदियां करती है। वर्षों से सावन माह की शुरुआत से ही इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक निरंतर होता चला आया है। बताया जा रहा है कि जनवरी माह से सावन के पहले तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।

स्थानीय ग्रामीण सुजीत कुमार बताते हैं सैकड़ों वर्ष से यह मंदिर बागमती नदी की बीच धारा के बीच अवस्थित है। यह पूरा ही इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सैकड़ों घर तहस-नहस हो जाते हैं, कई पुल ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रलयकारी बाढ़ भी कभी इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाया।

थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बैंक में डकैती

आठ लाख रुपये कैश की हुई लूट, पुलिस जांच में जुटी

मोतिहारी (एजेंसियां)।

ताजा मामला हरसिद्धि थाना के बगल का है, जहां महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित स्पंदना स्फूर्ति बैंक में कल रात नौ बजे के आसपास करीब आठ लाख की लूट हुई है। कहा जा रहा है कि नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है।

बैंक के कर्मचारी के द्वारा बताया गया है की तीन बाइक पर सात अपराधी आए थे, सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वहीं मामले की जानकारी होते ही हरसिद्धि पुलिस रात में हरकत में आई और धवही के दो युवक को

पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

अभी तक कोई घटना को लेकर अपराधियों के बारे कोई जानकारी पुलिस द्वारा नहीं मिली है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मगर अपराधी का सुराग नहीं मिला है। वहीं बीते आठ दिनों में सिर्फ हरसिध्दि में ये दूसरी घटना है। बीते दो जुलाई को बाइक पर सवार दो अपराधी मुर-रापुर गांव में फाइनेंस कर्मी को हथियार दिखा कर एक लाख तेईस हजार रुपए लूटकर ले गए थे। फाइनेंस कर्मी बृज किशोर कुमार ने पुलिस को अपराधी के बारे में बताया था कि दो अपराधी एक मोटा तथा दूसरा गोरा था जो अभी तक पुलिस की जांच और पकड़ से बाहर है। इस तरह के घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ हैं। वहीं स्पंदना स्फूर्ति बैंक में हुई डकैती मामले में सभी बैंक कर्मी के मोबाइल को पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। बैंक कर्मियों पर मिलीभगत का संदेह के मद्देनजर सभी कर्मियों से सुबह से पुलिस पूछताछ कर रही है।

नेशनल हाईवे पर मिला 35 वर्षीय युवक का शव

नहीं हो पाई शिनाख्त, डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची

गया (एजेंसियां)।

मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह जिले के आमस थाना क्षेत्र के राजपुर दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे के समीप पेट्रोल पंप के पास पुलिस पर एक 35 वर्षीय युवक का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आमस थाना पुलिस व डॉग स्क्वायड की टीम निरीक्षण किया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस शव की पहचान के लिए प्रयास कर रही है।

इस संबंध में आमस थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की आस

पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। राजपुर गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंच कर आस पास के लोगों से इसकी शिनाख्त करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पहचान नहीं हो सकी। मरने वाले की उम्र लगभग 35 वर्ष के करीब है।

शव की पहचान के लिए सभी थानों में सूचना भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि शव की जांच में युवक के सीने पर गहरा जख्म का निशान है। अपराधियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए दूसरे जगह हत्या कर शव लाकर यहां फेंक दिया है। हालांकि आरोपी पुलिस से ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकते हैं। वहीं युवक के शव को देखने से लगता है कि युवक पहले किसी स्थान पर ले जाकर जमकर मारपीट की गई है, फिर सर का बाल मुंड़ा गया है। उसके बाद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक गोपाल अग्रवाल द्वारा श्री शेषसाई इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर. 98/1, को-ऑपरेटिव इंडस्टीयल एस्टेट, गांधी नगर, बालानगर के पास मेडचेल-मल्काजगिरि जिला. हैदराबाद 500037, तेलंगाना स्टेट से मुद्रित तथा प्लॉट नं. ए-23/5 तथा 6, दूसरा माला, ओपीआईई, बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना राज्य-500037 से प्रकाशित। आर. एन. आई रजिस्टर्ड नं. TELHIN/2019/78163, फोन नं. 040-29551811. E-mail : dailyshubhlabh@gmail.com